https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंता बढ़ाने वाला समझौता

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रैटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसके मुताबिक, किसी एक के प्रति दिखाई गई आक्रामकता दूसरे के खिलाफ भी मानी जाएगी, कुछ वैसा ही समझौता जैसा नैटो के सदस्य देशों के बीच है। भले कहा जा रहा हो कि यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के लंबे ऐतिहासिक रिश्तों का परिणाम है, लेकिन भारत के लिए यह चिंता बढ़ाने वाला है। सऊदी अरब खाड़ी में भारत के करीबी सहयोगियों में से एक है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रों में दोनों के बीच पिछले दो दशकों में संबंध गहरे हुए हैं- खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौर में नई तरह की गर्मजोशी देखने को मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल अप्रैल में ही अपने तीसरे सऊदी दौरे पर गए थे, जहां दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी थी। केवल सऊदी ही नहीं, क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ भी भारत का सहयोग बढ़ रहा है। यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ओमान व कतर के साथ बात चल रही है। लेकिन, सऊदी अरब-पाकिस्तान समझौते से इस क्षेत्र में भारत की कोशिशों को झटका लग सकता है। चार महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉर्डर पर अब भी तनाव है। ऐसे में यह आशंका दरकिनार नहीं की जा सकती कि भारत और पाकिस्तान के तनाव में इस समझौते की वजह से सऊदी अरब भी पार्टी बन जाए। समझौते का एक और अहम एंगल है, हाल में इस्राइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक कर हमास के नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास किया था। इसे लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में काफी गुस्सा है। इस हमले के बाद दोहा में इस्लामिक देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, जहां यह चर्चा भी उछली कि क्या नाटो जैसा कोई संयुक्त सुरक्षा बल बनाया जा सकता है। अब दूसरे मुस्लिम देश भी इस तरह के समझौते की संभावना टटोल सकते हैं। इस रक्षा समझौते से पूरे क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। भारत ने कहा है कि वह इसके असर को देखेगा। सरकार को अपनी चिंताओं को लेकर सऊदी अरब से खुलकर बात करनी चाहिए। ध्यान रखना होगा कि यह समझौता किसी भी तरह से नई दिल्ली-रियाद संबंधों के आड़े न आए।

'कीचड़ में खिले कमल की तरह बनो'

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर
(आध्यात्मिक गुरु)

मरुस्थल में पानी की बोतल का मूल्य एक झरने के पास से कहीं अधिक होता है। जब चारों ओर शांति हो और आप शांत हों, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। परंतु जब चारों ओर सब बिखर रहा हो और तब भी आप अपनी मुस्कान बनाए रखें, तभी शांति का असली मूल्य है। जब लोग आपको दोष दें, जब वे आपको समझ न पाएँ - तब मुस्कुराते रहने की आंतरिक शक्ति चाहिए। जब आप अराजकता और भ्रम से घिरे हों, तभी सबसे अधिक शांति की आवश्यकता होती है। आनंद अराजकता से ही निकलता है, और अराजकता का आनंद लेने की क्षमता ही आत्मज्ञान है। जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल न हों, तभी धैर्य, शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है ताकि आप विचलित न हों।

आत्मज्ञान का अर्थ है जीवन को गहराई से जीना। जब आपकी जड़ें गहरी हों, जब आप अपने अस्तित्व की गहराई से जीते हों, तब संसार हिल सकता है पर आप अडिग रहते हैं। आप तूफान का अनुभव करते हैं, परंतु तूफान आपको निगल नहीं पाता। कीचड़ में खिलने वाले कमल की तरह बनो, जो कीचड़ से अछूता रहता है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, परंतु यदि उस पर पानी की एक बूँद डाली जाए तो वह मोती की तरह उस पर टिकती है, पर चिपकती नहीं। वैसे ही इस संसार में रहो, पर किसी से चिपको मत। जब आप संघर्ष और अराजकता के साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं, तो वे मिट जाते हैं। आप केंद्रित कैसे रह सकते हैं? अपने अनुभव से ध्यान हटाकर अनुभव करने वाले की ओर ले जाएँ। अनुभव हमेशा परिधि पर होते हैं, वे बदलते रहते हैं। लेकिन अनुभव करने वाला, जो अपरिवर्तनीय है - वह केंद्र में है। बार-बार केंद्र में लौटें। यदि आप निराश हैं, तो निराशा के अनुभव में खोने के बजाय पूछें,'कौन निराश है? ' यदि आप दुखी हैं, तो पूछें, 'कौन दुखी है? ' यदि आप अज्ञानी लगते हैं, तो पूछें, 'कौन अज्ञानी है?' यदि आप सोचते हैं 'मैं तो बेचारा हूँ,' तो पूछें, 'यह ह्यबेचारा मैं कौन है? अपने सारे मुखौटे उतार दो और मैं का सामना करो।

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है , 'समत्वं योग उच्यते' अर्थात समभाव ही योग की कसौटी है। महात्मा गांधी की जीवनसंगिनी कस्तूरबा गांधी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थीं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, 'बस कुछ ही घंटे या मिनट बाकी हैं।' उसी क्षण गांधीजी अपने कुटीर से बाहर आए और पंडित सुधाकर चतुर्वेदी से कहा, 'गीता का वह श्लोक मुझे सुनाओ।' जब उन्होंने गीता का पाठ किया तो गांधीजी बोले, 'आज मेरी परीक्षा है।'

आत्मज्ञान का अर्थ है जीवन को गहराई से जीना। जब आपकी जड़ें गहरी हों, जब आप अपने अस्तित्व की गहराई से जीते हों, तब संसार हिल सकता है पर आप अडिग रहते हैं। आप तूफान का अनुभव करते हैं, परंतु तूफान आपको निगल नहीं पाता। कीचड़ में खिलने वाले कमल की तरह बनो, जो कीचड़ से अछूता रहता है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, परंतु यदि उस पर पानी की एक बूँद डाली जाए तो वह मोती की तरह उस पर टिकती है, पर चिपकती नहीं। वैसे ही इस संसार में रहो, पर किसी से चिपको मत। जब आप संघर्ष और अराजकता के साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं, तो वे मिट जाते हैं। आप केंद्रित कैसे रह सकते हैं? अपने अनुभव से ध्यान हटाकर अनुभव करने वाले की ओर ले जाएँ। अनुभव हमेशा परिधि पर होते हैं, वे बदलते रहते हैं। लेकिन अनुभव करने वाला, जो अपरिवर्तनीय है - वह केंद्र में है। बार-बार केंद्र में लौटें।

21 सितम्बर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर विशेष

यदि आप निराश हैं, तो निराशा के अनुभव में खोने के बजाय पूछें,'कौन निराश है? ' यदि आप दुखी हैं, तो पूछें, 'कौन दुखी है? ' यदि आप अज्ञानी लगते हैं, तो पूछें, 'कौन अज्ञानी है?' यदि आप सोचते हैं 'मैं तो बेचारा हूँ,' तो पूछें, 'यह ह्यबेचारा मैं कौन है? अपने सारे मुखौटे उतार दो और मैं का सामना करो।

व्यवस्था और अराजकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अनिश्चितता को दो तरीकों से देखा जा सकता है - यह या तो आपके उत्साह और आनंद को बढ़ा सकती है, या आपको डर, चिंता और अवसाद में धकेल सकती है। जब आप किसी आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो आप दरअसल क्या चाहते हैं? कुछ ऐसा जिसकी आपको अपेक्षा नहीं है, है न? सुखद आश्चर्य जीवन में रोमांच लाता है, मनोबल बढ़ाता है। फिल्म देखते समय यदि पहले से पता हो कि आगे क्या होगा, तो मजा नहीं आता। लेकिन जब पता नहीं होता, तो उत्साह और आनंद बना रहता है।

अनिश्चितता आपको कब चिंतित करती है? जब आपको यह भरोसा नहीं होता कि आपकी देखभाल की जा रही है, कि इस सृष्टि में एक शक्ति है जो आपसे प्रेम करती है और आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है। अनिश्चितता भय पैदा कर सकती है। लेकिन इसे आप सभी संभावनाओं के क्षेत्र के रूप में भी देख सकते हैं।

जीवन बदसूरत मुझे नहीं पता से खूबसूरत मुझे नहीं पता तक की एक यात्रा है। बदसूरत मुझे नहीं पता तब होता है जब आप झुंझलाहट में कहते हैं: मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो! लेकिन खूबसूरत मुझे नहीं पता विस्मय है। अपने प्रश्न को विस्मय में बदलो! बुद्ध ने कहा, अनुत्तर भव - उत्तरहीन बनो। उन्होंने कभी नहीं कहा, प्रश्नही न बनो। जब आप विस्मय में होते हैं, तभी सच्ची भक्ति प्रस्फुटित होती है।

अराजकता में सामंजस्य खोजना, दुख में आनंद खोजना, मूर्खता में ज्ञान खोजना, अंधकार में प्रकाश खोजना, मृत्यु के स्थान में अमरत्व खोजना - यही भगवद्गीता है।उथल-पुथल इस संसार का स्वभाव है, जबकि शांति बनाना हमारे आत्मा का स्वभाव है। यदि दृढ़ संकल्प और कौशल के साथ हम शांति में केंद्रित रह पाते हैं, तो यह केवल हमारे भीतर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे चारों ओर की उथल-पुथल को भी शांत करने लगती है।

चुनाव से पहले बिखरता लालू परिवार

संतोष कुमार पाठक
(वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक)

बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे लालू यादव के परिवार में घमासान तेज होता जा रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को किस तरह से पार्टी (आरजेडी) और परिवार से बाहर निकाला गया था, यह सब जानते हैं। उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तेज प्रताप यादव ने कई मौकों पर बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें जयचंद तक बता दिया। बिहार की राजनीति और खासकर लालू यादव के परिवार से जुड़े लोगों को यह लगता है कि संजय यादव के कारण ही तेज प्रताप को अपने ही परिवार से बाहर होना पड़ा।

तेज प्रताप के प्रकरण के बाद अब लालू यादव को किडनी देकर लोकप्रिय होने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बयानों ने भी लालू यादव के परिवार में चल रहे उठा-पटक और घमासान को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। तेज प्रताप के बाद लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव को निशाने पर ले लिया है। लालू यादव के परिवार में इस बार बवाल की शुरूआत गुरुवार को उस तस्वीर से हुई, जिसमें बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बस में सबसे आगे वाली तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए। संजय यादव की यह तस्वीर सामने आते ही बिहार की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया।

तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव के बैठने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेता के लिए ही होती है। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इस फ्रंट सीट पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बैठते देखने के लोग अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे यह हमें तो कतई मंजूर नहीं। सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस पोस्ट को रिपोस्ट कर देती हैं। इससे यह साफ-साफ नजर आने लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी पारिवारिक मामलों में संजय यादव के बढ़ते हस्तक्षेप से खुश नहीं है। इससे लालू यादव के परिवार में राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाता है। तेजस्वी यादव के नाराजगी जताने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी भी सक्रिय होकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट जाते हैं। इसके बाद रोहिणी आचार्य से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करवाया जाता है, जिसमें वह अपनी ही पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं के तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखती हैं कि, वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है।

इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। जितनी तेजी से लालू यादव ने मैदान में उतर कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इससे पहले जितनी तेजी से उन्होंने सोशल मीडिया पर उतर कर अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से निकालने का पोस्ट किया था।

उससे दो बातें तो बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रही है। पहली बात तो यह है लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसके लिए उनके बच्चे उनके ही बेटे तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं। दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता रहे लालू यादव को इस बात का अहसास बखूबी है कि उनके परिवार में घमासान की जितनी खबरें बाहर आएंगी, विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन की हार उतनी ही तय होती जाएगी। इसलिए लालू यादव हर हाल में विधानसभा चुनाव तक इस बवाल को थामे रखना चाहते हैं। लेकिन यह तय मान कर चलिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी आए लेकिन इसके बाद लालू यादव भी अपने परिवार में जारी उठा-पटक को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी सूरत में या तो लालू यादव का परिवार ही बिखर जाएगा या फिर तेजस्वी यादव को संजय यादव को अपने से दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इस फ्रंट सीट पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बैठते देखने के लोग अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे यह हमें तो कतई मंजूर नहीं। सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस पोस्ट को रिपोस्ट कर देती हैं। इससे यह साफ-साफ नजर आने लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी पारिवारिक मामलों में संजय यादव के बढ़ते हस्तक्षेप से खुश नहीं है। इससे लालू यादव के परिवार में राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाता है। तेजस्वी यादव के नाराजगी जताने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी भी सक्रिय होकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट जाते हैं। इसके बाद रोहिणी आचार्य से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करवाया जाता है, जिसमें वह अपनी ही पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं के तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखती हैं कि, वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। जितनी तेजी से लालू यादव ने मैदान में उतर कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इससे पहले जितनी तेजी से उन्होंने सोशल मीडिया पर उतर कर अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से निकालने का पोस्ट किया था।

पुस्तक समीक्षा

कैकेई के राम : नर से नारायण बनने की यात्रा

अनूप चतुर्वेदी

जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

इसी भाव में वाल्मीकि रामायण से लेकर अब तक अनगिनत राम कथाएं लिखी जा चुकी हैं। सबके अपने-अपने राम हैं और उनकी अपनी -अपनी व्याख्या। राम कथा के विभिन्न पात्रों को लेकर भी अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं। आज के युग में भी यह कार्य अनवरत जारी है। ख्यातिलब्ध लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद् रहीस सिंह की नवीनतम औपन्यासिक कृति 'कैकेई के राम' राम कथा के अहम प्रसंगों को अनूठी भाषा-शैली में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आम जनमानस में कैकेई की छवि नकारात्मक है लेकिन यह कृति भगवान राम की मझली माता के बारे में इससे उलट हमें एक नूतन दृष्टि प्रदान करती है।

लोकमानस में यही धारणा है कि कैकई ने मंथरा के कहने पर अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। यहां तक कि भरत ने भी अपनी माता कैकेई को ही दोषी माना और उन्हें कुमाता कहा। हालांकि राम ने अपनी मझली मां को सदैव अपना शुभचिंतक और पथ प्रदर्शक ही माना। फिर भी समाज में किसी स्त्री का नाम कैकेई नहीं रखा गया। यह कृति युगों से समाज में चली आ रही कैकेई के प्रति परंपरागत धारणा को बदलने का सफल प्रयास है।

प्रथम अध्याय में वनवास के पीछे के रहस्य का पर्दा गुरु वशिष्ठ उठाते हुए राम से कहते हैं, 'मेरी इच्छा थी कि आप राज सिंहासन पर न विराजकर वन की ओर प्रस्थान करें क्योंकि मेरी दृष्टि में वह समय आपके भोग का नहीं, योग का था। आपके सुख का नहीं, तप का था। आपके शासन का नहीं, संघर्ष का था। उस समय यह आवश्यक था कि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और यश का अर्जन। यही राष्ट्रहित में था और आपके हित में भी। ......मैंने ही महारानी कैकेई को महाराज दशरथ से भरत के लिए राज और आपके लिए 14 वर्ष के वनवास हेतु वचन मांगने के लिए कहा था। महारानी कैकई आपकी वनवास का कारण नहीं अपितु एक माध्यम थीं। सत्य तो यह है राम ! तुम्हारे इस समस्त यश का वे ही माध्यम थीं। उन्होंने लोकविष को तुम्हारे लिए ही स्वीकार किया जो तुम्हारी नर से नारायण की यात्रा संपन्न करने के लिए अनिवार्य था।' अर्थात् राम के वनवास की योजना वशिष्ठ ने बनाई थी और उसे कैकेई के माध्यम से कार्यान्वित कराया था। कारण होते हुए भी गुरु वशिष्ठ उस प्रस्थान के दोषी होने से बच गए और कैकेई कारण न होते हुए भी सामाजिक कलंक की भागीदार बन गयीं।

लेखक ने भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की वह यात्रा, जो उन्हें दशरथ कुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम तक की पूर्णता तक ले जाती है, को 14 अध्याय में पूरा किया है। हर अध्याय अपने आप में विशिष्ट है। यह कृति इस यात्रा के संपूर्ण काल खंड

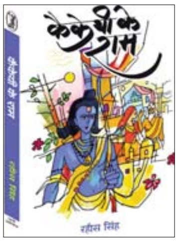

को संवादों के माध्यम से उस लोकमानस के मन को छूती है जिसके आधार राम हैं। साथ ही यह प्रश्न भी उठाती है कि इस यात्रा की पाथेय राम की मझली मां कैकेई थीं, और राम इस सत्य से पूरी तरह अवगत भी थे, फिर यह संसार इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाया? राम के यश का हेतु रचने वाली माता कैकेई के हिस्से में अपयश ही आया। संवाद शैली इतनी मोहक है कि पाठक का ध्यान भटक ही नहीं पाता। भाषा चमत्कारिक है। विशेष तौर पर राम नाम के अनगिनत पर्यायवाची जानने हों तो इस पुस्तक के अतिरिक्त कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। इससे ज्ञात होता है कि रचनाकार का शब्द सागर कितना गहरा है !

'कैकेई के राम' वन के हैं, राजमहल के नहीं। इसीलिए वनवासियों और गिरिवासियों के लिए उनके मन में अगाध प्रेम और

लेखक : रहीस सिंह

सम्मान है। जब लक्ष्मण राम से प्रश्न करते हैं कि वह सामान्य वनवासी शबरी की कुटिया में क्यों जाना चाहते हैं, तो राम इस प्रश्न का वह उत्तर देते हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। लक्ष्मण से राम कहते हैं, 'किसी भी व्यक्ति की महत्ता और उपादेयता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि वह झोपड़ी में रहता है अथवा राजमहल में, वह वन में रहता है अथवा किसी विशाल नगर में, वह पर्वतों पर रहता है अथवा घाटियों में, उसकी महत्ता तो 'मनसा, वाचा, कर्मणा' होनी चाहिए।...... केवल शबरी ही नहीं अपितु प्रत्येक वनवासी राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और प्रकृति के साथ-साथ वाह्य व आंतरिक सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण आटविक बल और आटविक अर्थव्यवस्था इन्हीं से बनती है जो राष्ट्र को सशक्त बनाने में नींव के पत्थर की तरह काम करती है।

'राम रस' में पगी यह कृति हमें तत्कालीन समरस सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताती है। राम के सबसे प्रिय सखा निषादराज गुह हैं, जिनका विशाल साम्राज्य भी है। जबकि आज इस समाज को पिछड़ों की श्रेणी में रखा जा रहा है। इतना ही नहीं इसी समाज के सामान्य केवट से गंगा पार जाने के लिए 'राजकुमार राम' अनुनय विनय करते दिखते हैं और वह केवट उन्हें अपनी सभी शर्तें मानने के लिए विवश कर देता है।

यह कृति राम के विराट स्वरूप का तो दर्शन कराती ही है, साथ ही गुरु वशिष्ठ और माता कैकेई की उस लोक हितकारी दृष्टि को भी सामने लाती है, जिससे अभी तक आम जनमानस अनभिज्ञ था। वशिष्ठ के लिए राष्ट्र प्रथम था। इसलिए वह राम को राजा तब बनाना चाहते थे, जब दशरथ नंदन इसके लिए पूरी तरह से योग्य हो जाएं। और यह योग्यता राज महल में रहते हुए नहीं आ सकती थी। वशिष्ठ चाहते थे कि राम राज निवास से निकलकर आम लोगों के बीच जाएं, उनके जैसा जीवन जीएं। इसके बाद जब वह लौट कर आएंगे तो राज पद के सर्वथा योग्य होंगे। कैकई भी चाहती थी कि उनका राम राजकुल का नहीं, लोक का राम हो। इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दिया। कैकेई जानती थीं कि इस कृत्य के लिए वह हमेशा हमेशा के लिए कलंकिनी कहलाएंगी लेकिन लोक हित के लिए उन्होंने इस अपयश को स्वीकार किया।

'कैकेई के राम' एक ऐसी साहित्यिक - सांस्कृतिक रचना है, जो राम कथा को एक नया आयाम देगी। लेखक की स्वान्तः सुखाय रचना हमें अपनी जड़ों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक उस हर व्यक्ति को अवश्य पढ़नी चाहिए जो भगवान राम के विराट स्वरूप से आज के संदर्भ में परिचित होना चाहता है।

पुस्तक अंश

'माता यदि आपने मुझे वन जाने का आदेश पिताश्री के माध्यम से न दिया होता तो मुझे यह पता ही नहीं चलता कि इस राष्ट्र की रक्षा सैनिक ही नहीं आटविक भी करते हैं, योद्धा ही नहीं ऋषि भी करते हैं, अंतेवासी ही नहीं वनवासी भी करते हैं। इसके समृद्ध और सुदीर्घ होने की कामना केवल राज सिंहासन पर विराजे हुए राजा ही नहीं करते हैं अपितु उसे देश की सीमाओं के भीतर रहने वाली वन्य जातियां और पशु - पक्षी भी करते हैं। हमारी विजय, हमारे यश और हमारी समृद्धि में उनका भी योगदान होता है। बस वे कभी अपना भाग आपसे मांगने नहीं आते। वे तो परमार्थ को ही अपना प्रसाद समझते हैं।'

(माता कैकई को वनवास का अभिप्राय बताते हुए राम)

'धन्य हो मझली मां ! आपने अपने समस्त सत्कर्मों का पुण्य मुझे आशीर्वाद में दे दिया और स्वयं पाप की भागीदार कहलाने लगीं। समस्त संसार का यश मेरे हिस्से में कर दिया और सारा कलंक अपने सिर ले लिया। यह संभव है कि यह संसार आपको कभी समझ ना पाए। परंतु मैं समझ गया। मैं समझ गया माता !'

(मन ही मन माता कैकेई से संवाद करते हुए राम)

'अयोध्या के राज सिंहासन पर तो कोई तपस्वी ही आरूढ़ हो, ऐसी ही मेरी भी इच्छा थी। आज वह पूर्ण हो रही है। मेरा पाथेय मर्यादा पुरुषोत्तम बनें, इसी में मेरी सिद्ध थी और राष्ट्र का यश। चूंकि इसका हेतु महारानी कैकेई बनी, इसलिए हम सभी को उनका ऋणी होना चाहिए।'

(राम के राज्याभिषेक के समय स्वयं से संवाद करते गुरु वशिष्ठ)

'...आपने शबरी के झूठे बेर खाकर उन सारे विभेदों की समाप्ति का संदेश संपूर्ण राष्ट्र को दिया जो न जाने कब से मनुष्य- मनुष्य में भेद की खाई गहरी करते चले आ रहे थे, ऐसी खाई जिसमें संवेदनाएं गिरकर अपना दम तोड़ रही थीं। आपने सुग्रीव का साथ देकर यह बता दिया कि आप प्रत्येक निर्बल का संबल हैं।'

(राम से संवाद करते गुरु वशिष्ठ)

पड़ोसी देश में सत्ता का अवसान

अशोक राज

भारत का निकटतम पड़ोस गहन राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। नेपाल की हिमालय की तलहटी से लेकर म्यांमार के संघर्षग्रस्त मैदानों तक, सत्ता परिवर्तन, सैन्य तख्तापलट, नागरिक अशांति और आर्थिक पतन दक्षिण एशियाई राजनीतिक मानचित्र को तेजी से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। जो सरकारें कभी स्थिर प्रतीत होती थीं, वे भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और युवाओं द्वारा नेतृत्व में उठती बदलाव की मांगों के बोझ तले ढह रही हैं।

नेपाल में, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार का पतन एक ऐसे कदम के कारण हुआ जिससे जनता में आक्रोश फैल गयाः फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और अन्य जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया। इसका औचित्य एक नए कानून को बताया गया जिसके तहत वैश्विक तकनीकी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य था, लेकिन नागरिकों ने इसे असहमति को दबाने की कोशिश माना। इसके बाद श्जेन जेडश विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हुई–युवाओं के नेतृत्व में, तकनीक से प्रेरित, और न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल्कि बेरोजगारी, असमानता और व्यापक भ्रष्टाचार जैसे गहरे मुद्दों पर केंद्रित थी। ओली के इस्तीफा देने के बावजूद, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास–2008 से अब तक तेरह सरकारें–ने कई नागरिकों को नेतृत्व में एक और फेरबदल की आशंका से आशंकित कर दिया है।

हालांकि, उम्मीद की किरण फिर से जगी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है–ऐसा पद संभालने वाली वह पहली महिला हैं। भारतीय मूल और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण, उनकी नियुक्ति का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। कई नेपाली अब उनके नेतृत्व को राजनीतिक विश्वास के पुनर्निर्माण और एक नए लोकतांत्रिक मार्ग को प्रशस्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं।

बांग्लादेश में भी, 2024 में इसी तरह की निराशा उबल पड़ी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रशासन पर वर्षों से लगे आरोप–भ्रष्टाचार, विपक्ष का दमन और अधिनायकवाद–अपने चरम पर पहुँच गए। विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने शासन को ध्वस्त कर दिया। आज, देश का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम प्रशासन कर रहा है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। राजनीतिक अनिश्चितता, सांप्रदायिक तनाव और बढ़ता इस्लामी प्रभाव किसी भी प्रगति को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर रहे हैं। भारत और दुनिया की नजरें आगामी बांग्लादेश चुनावों पर भी टिकी हैं। श्रीलंका 2022 में अपने पतन के झटकों से जूझ रहा है। आर्थिक पतन और ईंधन की कमी के बीच राजपक्षे शासन के पतन ने द्वीप को संकट में डाल दिया। आईएमएफ द्वारा बड़े पैमाने पर दिए गए बेलआउट ने अस्थायी राहत प्रदान की, लेकिन कर वृद्धि और मितव्ययिता की दर्दनाक प्रक्रिया ने जनता के धैर्य की परीक्षा ली है। राष्ट्रपति (एकेडी) अब एक नाजुक सुधार प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी ऊँची है और संस्थानों में विश्वास कम है, नए सिरे से अशांति एक निरंतर खतरा बनी हुई है।

पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा है। अप्रैल 2022 में, शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान के साथ टकराव के बाद, प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया गया था। 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए–जिनमें से कई निराश युवाओं द्वारा संचालित थे। राज्य ने कड़ी कार्रवाई की, और खान की पार्टी, पीटीआई, तब से काफी हद तक दबा दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दब रही है, मुद्रास्फीति आसमान छू रही है, और सीमा पार हमलों की एक श्रृंखला के बाद भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के पड़ोस में शासन का पतन। पाकिस्तान में कभी आशाजनक लोकतांत्रिक आंदोलन कमजोर जरूर हुआ है, अगर पूरी तरह से पटरी से नहीं उतरा है। अफगानिस्तान शायद पतन की सबसे स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी ने देश को मानवाधिकार और शासन संकट में डाल दिया है। लड़कियों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है; असहमति को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया है।

इस बीच, म्यांमार में, 2021 में लोकतांत्रिक प्रतीक आंग सान सू की को सत्ता से बेदखल करने वाले सैन्य तख्तापलट ने देश को गृहयुद्ध में धकेल दिया। सेना ने जनता की प्रतिक्रिया का गलत आकलन किया–देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, क्रूर दमन और सामूहिक हत्याओं का सामना करना पड़ा। राज्य की हिंसा का सामना कर रहे हजारों नागरिकों ने हथियार उठाए और प्रतिरोध समूह बनाए जो अब देश के घने जंगलों से अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं। जवाबी कार्रवाई में, सेना ने विद्रोहियों को जड़ से उखाड़ने के लिए अंधाधुंध बमबारी और तोपखाने के हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरे समुदाय तबाह हो गए हैं।

म्यांमार के आंतरिक युद्ध ने एक गंभीर शरणार्थी संकट को जन्म दिया है जो भारत तक फैल गया है।

भारत के लिए ये क्रमिक संकट तत्काल रणनीतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं:

- नेपाल की खुली सीमा घुसपैठ और प्रवासन को लेकर चिंताएँ पैदा करती है।
- बांग्लादेश की अशांति क्षेत्र में कट्टरपंथी तत्वों को सशक्त बना सकती है।
- श्रीलंका के बंदरगाह भारतीय और चीनी प्रभाव के लिए युद्धक्षेत्र बने हुए हैं।
- पाकिस्तान की अस्थिरता क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।
- अफगानिस्तान और म्यांमार आतंकवाद और शरणार्थियों की आमद के दोहरे खतरे पेश करते हैं।

कुछ ही वर्षों में, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान, सभी ने या तो शासन-पतन देखा है या फिर सत्तावादी सुदृढ़ीकरण। प्रत्येक उथल-पुथल एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है–न केवल उन देशों के लिए, बल्कि भारत की क्षेत्रीय कूटनीति, सुरक्षा स्थिति और मानवीय जुड़ाव के लिए।

रॉयटर्स के अनुसार, 65,000 से ज्यादा शरणार्थी, जिनमें से ज्यादातर चिन जातीय समूह से हैं, भारत भाग आए हैं–कई मिजोरम में शरण मांग रहे हैं। इस तख्तापलट ने 3,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और लगभग 1.7 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुँचा दिया है, जिससे इस क्षेत्र का सबसे बुरा मानवीय संकट और गहरा गया है। पूरे दक्षिण एशिया में, एक आम बात निर्विवाद हैः युवाओं के गुस्से, बढ़ती असमानता और क्षीण होती लोकतांत्रिक संस्थाओं से उपजा, जड़ जमाए बैठे अभिजात वर्ग के प्रति असंतोष। जैसा कि शिकागो विश्वविद्यालय के पॉल स्टैनिलैंड कहते हैं, यह संकट संरचनात्मक है; लोग अब शासक वर्ग को सुरक्षित या समृद्ध भविष्य देने में सक्षम नहीं मानते।हालाँकि, स्वतःस्फूर्त विद्रोहों में अक्सर मजबूत नेतृत्व का अभाव होता है। नेपाल और बांग्लादेश में, अंतरिम सरकारों ने इस खालीपन को भर दिया है, लेकिन दीर्घकालिक सुधारों के बिना, वही अभिजात वर्ग सत्ता में वापस आ सकता है। कमजोर गठबंधन और राजनीतिक शून्य प्रगति को बाधित कर रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति : भारत की रफ्तार और वैश्विक दौड़

विनयशील शर्मा

दुनिया आज जिस सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है, वह है जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए विश्व भर में प्रयास हो रहे हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) न केवल एक तकनीकी क्रांति हैं, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ विकास का भी बड़ा साधन बनकर उत्तर भारत पर भी पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारतीय बाजार को ईवी निर्माण और निवेश के लिए एक बड़ी संभावना के रूप में देख रही हैं।

भारत में ईवी की वर्तमान स्थिति : भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाज़ार है। यहाँ हर वर्ष करोड़ों वाहन बिकते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कुल बिक्री में लगभग 2–3 प्रतिशत ही है, लेकिन यह तेजी से बढ़ रही है। दोपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, खासकर ओला इलेक्ट्रिक, एथर, हीरो और टीवीएस जैसे ब्रांड, आम उपभोक्ताओं के बीच

● स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य की ओर दुनिया तेजी से बढ़ रही है
● भारत भी ईवी क्रांति की ओर अग्रसर, पर ढांचागत चुनौतियाँ अब भी बरकरार

लोकप्रिय हो रहे हैं। चारपहिया श्रेणी में टाटा मोटर्स अग्रणी है, जबकि महिंद्रा और विदेशी कंपनियाँ भी अपने नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 30 प्रतिशत नई वाहन बिक्री इलेक्ट्रिक वाहनों की हो।

भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं–

1. फेम योजना (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ इलेक्ट्रिक

व्हीकल्स): उपभोक्ताओं को सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन निर्माण पर प्रोत्साहन।

2. राज्य स्तरीय ईवी नीतियाँः दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों ने रोड टैक्स माफी, रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट और सब्सिडी का प्रावधान किया है।

3. राष्ट्रीय बैटरी मिशनः बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता लाने और विदेशी निर्भरता घटाने की पहल।

4. नवीन ऊर्जा पर जोरः सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर ईवी चार्जिंग को अधिक स्वच्छ बनाने का प्रयास।

चुनौतियाँ :

1. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी – महानगरों को छोड़ अधिकांश शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं। लंबी दूरी की यात्रा अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

2.बैटरी लागत और आयु– लिथियम-आयन बैटरी महँगी हैं और भारत अभी तक इन्हें बड़े पैमाने पर आयात करता है। इससे वाहनों की कीमत अधिक रहती है।

3. बिजली उत्पादन का स्रोत– यदि चार्जिंग के लिए बिजली कोयले से बनेगी, तो प्रदूषण घटाने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

4. उपभोक्ता धारणा– ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में लोग अब भी इलेक्ट्रिक वाहनों की विश्वसनीयता और चार्जिंग को लेकर आशंकित हैं।

5. कचरा प्रबंधन– पुरानी बैटरियों का निस्तारण और रीसाइक्लिंग एक बड़ी चुनौती है।

पर्यावरणीय और आर्थिक लाभः

ईवी के प्रसार से भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के स्थान पर बिजली आधारित वाहन वायु प्रदूषण घटाने में मदद करेंगे। बैटरी निर्माण और चार्जिंग नेटवर्क से नए उद्योग और लाखों रोजगार सृजित होंगे। स्टार्टअप्स को नवाचार का अवसर मिलेगा और भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बन सकेगा।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थितिः

भारत अभी शुरुआती चरण में है। चीन और यूरोप ने जिस गति से एश क्रांति को अपनाया है, भारत को उस स्तर तक पहुँचने के लिए निवेश और नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता है।

बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता और अनुसंधान पर जोर दिए बिना भारत आयात पर निर्भर रहेगा। हालांकि, भारत की सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल घरेलू बाज़ार और युवा उपभोक्ता हैं, जो नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रिक वाहन केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले समय की अनिवार्यता हैं। भारत यदि समय रहते चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और उपभोक्ता विश्वास पर काम करता है, तो यह वैश्विक ईवी क्रांति का अगुवा बन सकता है।

यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी हरित और टिकाऊ विकास की दिशा देगा। 'आज की तैयारी ही कल की ताकत है।' भारत जितनी जल्दी इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियों का समाधान करेगा, उतनी ही तेजी से वह भविष्य की इस स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का लाभ उठा पाएगा।

AllNewsPaperPaid

साहित्य

कश्मीरी कहानी

बात मरने वाले की

■ अख्तर मुहीउद्दीन

यह कहकर उसने अजीब तरह से सिर हिलाया। चिलम बाएँ हाथ से थामी, जो उसने फिरन के दामन से बाहर निकाला था, 'मैं हैरान हूँ कि इनकी अक्ल को हो क?या गया है? अरे भाई, बात तो बिल्कुल सीधी है। एक पत्ता भी उसकी मरजी के बिना हिल नहीं सकता, जिसने यह सारी दुनिया पैदा की है। उस बच्चे की तकदीर में इतना ही दाना-पानी था, इसलिए यह सब होना ही था। दोष न कारवाले का है और न ही बच्चे की माँ का। म्यूनिसिपैलिटी या पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। करनेवाला बस वही है और रहनेवाला भी बस उसी का नाम है।'

ये बच्चे तो नहीं थे, पर दौड़ने से इनकी साँस फूल गई थी। प्रत्येक की यही कोशिश थी कि वह दूसरों को पीछे छोड़कर सबसे पहले मेरे पास पहुँचे। भागम-भाग में इन्होंने एक-दूसरे के पाँव कुचले थे। किसी-किसी को ठोकर भी लगी थी और उँगलियाँ लहूलुहान हो गई थीं। सभी मेरे कमरे में घुसे, कोई पहले और कोई बाद में और घुसते ही चिल्लाने लगे--'आपको वही और सिर्फ वही लिखना होगा, जो मैं कहूँगा, क्योंकि वही और सिर्फ वही सच है।'

मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने आँखें झुका लीं। देखकर सब चुप हो गए। उन्होंने शायद मेरे माथे पर पड़े बल भी देखे होंगे।

आखिर मैंने स्वयं एक व्यक्ति से पूछा, 'कहो भाई, क्या बात है?' वह खुश हुआ। उसे शायद एहसास हुआ कि अब उसी की बात दस्तावेज बनेगी। दम साधकर और फिर साँस छोड़कर वह धीरे-धीरे बोलने लगा। जैसे बोलने से पहले शब्दों को तौल रहा हो, 'लोगों की मत मारी गई है। इतनी दौलत हाथ लगी है कि आँखें होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं दिखता है। सड़क पर चलते नहीं, उसे रौंदते हैं। जाने कौन जहन्नुमी था? जाने कहाँ से खटारा कार मिली थी, जिसे वह बेहिसाब दौड़ा रहा था। मैं पहले ही जानता था कि वह कोई अनर्थ कर डालेगा और हुआ भी वही। गली से एक बच्चा बाहर आया। बिल्कुल नव-प्रस्फुटित कली-सा। और उसे ही कुचल डाला इस जहन्नुमी कारवाले ने।'

सुनकर मुझे जाने क्या हो गया और मुँह से अचानक चीख-सी निकल पड़ी, 'क्या कहा?'

उसने कहा, 'और कह ही क्या रहा हूँ? यह बच्चा कार के नीचे आ गया। लोग कहते हैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मर गया। बेचारा मर गया।'

यह कहकर उसने ठंडी साँस भरी। शायद उसकी आँखों से आँसू भी बह रहे थे। चूँकि वह अचानक उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे से बाहर चला गया, इसलिए मैं ठीक से उसकी आँखें देख नहीं सका। हाँ, मैंने दूसरे व्यक्ति की ओर नजर डाली--यह देखने के लिए कि उस पर भी मेरी तरह कोई असर हुआ है या नहीं! मगर वह अपनी घनी मूँछों की ओट में मंद-मंद मुसकरा रहा था। मैं उसकी मुसकराहट का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वह बोल उठा, 'सब बकवास करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आबादी बढ़ गई है। आप नहीं देखते कि चौक में ही कितने लोग होते हैं! आबादी बढ़ने के कारण ही आदमी की कोई कद्र नहीं रही है। माताओं की लातों से उनके ही बच्चे कुचले जाते हैं। महँगाई की मार में बड़े परिवार को कैसे पाल सकती हैं, सो भी आज की माँएँ! कारवाला ठीक से सीधी सड़क पर जा रहा था। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। अचानक एक बच्चा गली से दौड़ता हुआ आया। क्या पता माँ ही लाठी लेकर पिटाई करने के लिए पीछा कर रही हो! आफत की आँखें ही कहाँ होती हैं? कारवाले ने ब्रेक लगाई, लेकिन लगा नहीं। आखिर मशीन ही ठहरी। बचाने की बहुत कोशिश की बेचारे कारवाले ने मगर बेसुध। बच्चा पहियों के नीचे आ गया। कोई यह नहीं सोचता कि जरा उसकी माँ से पूछे कि अगर तुझे इस बच्चे की जरूरत नहीं थी तो इसकी मौत बेचारे कारवाले के मत्थे क्यों मढ़ी? हजरत, कहें क्या? जमाना बहुत खराब हो गया है।'

उसने कहा और कुछ इस तरह सिर झटककर बाहर निकला, जैसे जमाना खराब करने में मेरा भी हाथ हो! मैंने उससे कहना चाहा--मेरे भाई, जमाना जरूर खराब है, पर मेरे किए नहीं है। .. मगर उसने मुझे यह कहने के लिए भी समय नहीं दिया। इस तरह बाहर चला गया, जैसे मेरे यहा... तशरीफ लाकर उसने मेरी सात पीढ़ियों पर एहसान किया हो, या यह भी हो सकता है कि भागमभाग में उसके पैर का अँगूठा ही कट गया हो और उससे खून बह रहा हो।

'बस बोलते जाते हैं। न कुछ जानते हैं, न कुछ करते हैं।' यह तीसरा बोल रहा था। ऐसे बोल रहा था, जैसे अपने साथ ही बात कर रहा हो। नजरें नीची किए हुए। थोड़ा-सा खखारकर उसने मेरी ओर देखा और फिर बात आगे बढ़ाई, 'हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा करप्शन है, साहब। इसके रहते आप मोटरवाले या बच्चेवाली माँ पर क्या लांछन लगाएँगे? किसी का कोई दोष नहीं है। दोष है तो बस एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ किसी भी अधिकारी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जब ऐसी दुर्घटना होगी तो आप किसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगें? साफ बात है कि मोटरवाला सीधी सड़क पर अपनी मोटर चला रहा था। नहीं चलाता मोटर? क्या मोटर के आगे इंजन के बदले घोड़ा जोतता? या मोटर को सड़क पर नहीं, किसी मैदान में ले जाकर चलाता? बच्चा गली से दौड़ता निकला। बच्चा जो ठहरा, दौड़ेगा ही। उसकी माँ ने उससे थोड़े ही कहा था कि बेटा दौड़कर जा और मोटर के नीचे आ जा! अरे साहब, दौड़ना बच्चे की वृत्ति है। अब आप पूछेंगे कि दोष किसका है? आखिर एक हत्या हो गई, सो क्या अकारण हो गई? नहीं साहब! दोष है और म्यूनिसिपैलिटी का है। वहाँ ब्लाइंड कॉर्नर था। मोटरवाले को गली नहीं दिखी और बच्चे को मोटर नजर नहीं आई। एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या गुलाब खिलता? मगर कौन पूछता है म्यूनिसिपैलिटीवालों से? खैर, हमें क्या है? हमने अपनी जिंदगी गुजार दी है।' यह कहकर वह इस अंदाज से चला, जैसे मेरे कमरे से निकलकर सीधा कब्र में जाकर इत्मीनान से लेटेगा और सोचेगा कि अब जो होगा सो होगा, उसे कुछ नहीं होगा।

चौथे ने कहा, 'देख लिया? यह था एक और बतक्कड़ लाल बुझक्कड़। म्यूनिसिपैलिटी! अबे ओ म्यूनिसिपैलिटी क्या करती? ब्लाइंड कॉर्नर कई जगह होते हैं, पर हर जगह एक्सीडेंट नहीं होते हैं। साहब, मैंने खुद देखा है। विदेशों में भी ब्लाइंड कॉर्नर होते हैं, लेकिन वहाँ इंतजाम भी होता है। वहाँ के इंतजाम के क्या कहने! हमारे यहाँ इतनी पुलिस है कि हर प्राणी के पीछे नकीर- मुनकीर की तरह दो-दो जने लगे हैं। दो ही क्यों! ज्यादा भी हो सकते हैं। मगर कायदा? न अफसरों में अक्ल, न जवानों में काम करने का शौक। बस सभी का सारा ध्यान सिर्फ अपनी- अपनी जेब की तरफ। क्या ही अच्छा होता, अगर वहाँ ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही होता! कार के देखते ही वह हाथ उठाकर उसे धीरे-धीरे चलने का इशारा करता। दूसरा हाथ उठाकर बच्चे को गली के मुहाने पर ही रोकता। न कारवाले से चूक होती, न बच्चा ही मरता। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था या ग्यारहवाँ? क्या फर्क पड़ता है उससे? क्यों साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? सारा कुसूर ट्रैफिक पुलिस का है। मेरी राय है कि इस मामले में हमें अपना जोरदार विरोध प्रकट करना चाहिए।'

इतना कहकर वह कुछ इस प्रकार कमरे से निकला कि मुझे लगा, वह तुरंत चौक में जाकर पुलिस के खिलाफ लेक्चर झाड़ेगा। इधर मेरे समीप बैठा पाँचवाँ व्यक्ति हुक्के की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ मुझसे कह रहा था, 'इन मूर्खों की बातें दर्ज करते-करते हाथ थक गए होंगे आपके!'

यह कहकर उसने अजीब तरह से सिर हिलाया। चिलम बाएँ हाथ से थामी, जो उसने फिरन के दामन से बाहर निकाला था, 'मैं हैरान हूँ कि इनकी अक्ल को हो क?या गया है? अरे भाई, बात तो बिल्कुल सीधी है। एक पत्ता भी उसकी मरजी के बिना हिल नहीं सकता, जिसने यह सारी दुनिया पैदा की है। उस बच्चे की तकदीर में इतना ही दाना-पानी था, इसलिए यह सब होना ही था। दोष न कारवाले का है और न ही बच्चे की माँ का। म्यूनिसिपैलिटी या पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। करनेवाला बस वही है और रहनेवाला भी बस उसी का नाम है।'

इतना कहकर वह तंबाकू पीने लगा। छठा व्यक्ति भी कुछ कहना चाहता था। मगर जब उसने देखा कि पाँचवाँ व्यक्ति उठने का नाम ही नहीं ले रहा है तो वह चुप रहा। शायद वह अपनी बात बाद में कहेगा।

■ भगवत रावत

ताल तो भोपाल ताल

'ताल तो भोपाल ताल बाक़ी सब तलैयाँ'
इसी कहावत से जाना जाता था पूरे देश में भोपाल
वह तो करमजली गैस क्या फूटी चौरासी में
कि सारी दुनिया कहने लगी उसे 'गैस ट्रेजेडी वाला भोपाल'
पचास साल पहले आया जब बसने भोपाल में तो
यह पता लगा पाना मुश्किल था कि ताल के भीतर
बसा है भोपाल या भोपाल के भीतर बसा है ताल
दरअस्ल तब भोपाल का दिल और दिमाग ही हुआ
करता था भोपाल ताल
कभी कोई जब अपनी उदासी में जा बैठता उसके किनारे
तो वह ऐसे ऐसे लतीफ़े उसे सुनाता
कि वह हँसे बिना नहीं रह सकता था
और जब कोई उससे बातचीत के मूड में
उसके किनारे बैठा हो तो वह
उसे अपने ऐसे-ऐसे रहस्य बताता
कि वह हैरत में आए बिना रह नहीं सकता था
कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि कभी-कभी
देर रात गए भोपाल का ताल कमला पार्क छोड़कर
इब्राहिमपुरा और लखीमपुरा की गलियों से होता हुआ
चिन्तामणि चौक के पटियों तक पहुँच जाता था
और किसी को पता नहीं चलता था
बहरहाल, भोपाल का ताल तो आज भी है
पर जबसे उसे घेरना शुरू कर दिया ऊँचे-ऊँचे मकानों ने
तब से उसकी लहरों ने उस तरह मचलना छोड़ दिया
अब सपना-सा लगता था भोपाल का ताल
लोग अब उसे दूर से देखने आते हैं
या मशीनी बोटों पर सैर करते हैं
डोंगिया मुश्किल से दिखती है अब भोपाल के ताल पर
अब दो घड़ी उसके किनारे बैठकर उसके हाल-चाल
कोई नहीं पूछता
इस दुख में कई सालों से
भदभदा से बाहर ही नहीं निकला भोपाल का ताल
आप जब भी आएँ भोपाल
मुझे मिलें ना मिलें
सारी आपाधापी छोड़कर
भोपाल के ताल के पास ज़रूर जाएँ
उसके पास बैठकर उसका हल जानें
यक़ीन माने वह आपको इस तरह गले लगाएगा
कि आप भीतर से बाहर तक पूरी तरह भीग जाएँगे
और आपको पता ही नहीं चलेगा
कि कब आप मन ही मन गुनगुनाने लगे हैं —
ताल तो भोपाल ...!

वे इस पृथ्वी पर

वे इस पृथ्वी पर
कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग हैं ज़रूर
जो इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर
कच्छपों की तरह धारण किए हुए हैं
बचाए हुए हैं उसे
अपने ही नरक में डूबने से
वे लोग हैं और बेहद नामालूम घरों में रहते हैं
इतने नामालूम कि कोई उनका पता
ठीक-ठीक बता नहीं सकता
उनके अपने नाम हैं लेकिन वे
इतने साधारण और इतने आमफ़हम हैं
कि किसी को उनके नाम
सही-सही याद नहीं रहते
उनके अपने चेहरे हैं लेकिन वे
एक दूसरे में इतने घुले-मिले रहते हैं
कि कोई उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाता
वे हैं, और इसी पृथ्वी पर हैं
और यह पृथ्वी उन्हीं की पीठ पर टिकी हुई है
और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि उन्हें
रत्ती भर यह अंदेशा नहीं
कि उन्हीं की पीठ पर
टिकी हुई यह पृथ्वी ।

प्याज की एक गाँठ

चार रुपए किलो प्याज
आवाज लगाई
बशीर भाई ने
मैं चौंका
वे हँस कर बोले
ले जाइए साहब
हफ्ते भर बाद
यही भाव याद आएगा
अल्लाह जाने
यह सिलसिला
कहाँ तक जाएगा
जेब में हाथ डालते हुए
मैंने कहा
आधा किलो

सुन कर बशीर भाई कुछ बोले नहीं
और एक की जगह
आधा किलो तौलते हुए मेरे लिए
ऐसा लगा
जैसे कुछ मुश्किल में पड़ गए

उनकी तराजू का
भारी वाला पलड़ा
हमेशा की तुलना में
आज कुछ कम नीचे झुका
प्याज की एक गाँठ

और उतारें या न उतारें
इस सोच में
उनका हाथ
ग्राहक से रिश्ता तय करता था
एक क्षण को
हवा में रुका
और आखिरकार
बशीर भाई जीत गए
मैं रास्ते भर
झोले में डाली
प्याज की उस एक गाँठ को
आँखों में लिए-लिए
घर लौटा।

मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों, पीड़ा और पुनर्जीवन की आकांक्षा का दस्तावेज़

■ शैलेन्द्र शरण

पंकज सुबीर का कविता संग्रह 'उम्मीद की तरह लौटना तुम' एक ऐसे समय में आया है, जब साहित्य और विशेषकर कविता से समाज की अपेक्षाएँ लगातार बढ़ी हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति, तकनीकी शोर और राजनीतिक-सामाजिक जटिलताओं के बीच कविता अपने लिए न केवल एक स्थान तलाश रही है बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी संवेदनाओं को जगाने का कार्य भी कर रही है। पंकज सुबीर का यह संग्रह इन्हीं मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों, पीड़ा और पुनर्जीवन की आकांक्षा का दस्तावेज़ है।

'उम्मीद की तरह लौटना तुम'- यह शीर्षक भावनात्मक आग्रह नहीं है, बल्कि जीवनदृष्टि का उद्घोष है। यहाँ 'उम्मीद' का प्रतीक बहुआयामी है। यह संग्रह विछोह और संघर्ष के बाद पुन: उठ खड़े होने और भविष्य के प्रति आस्था का एक आयाम है।

पंकज सुबीर की आत्मीय भाषा, व्यक्तिगत संघर्ष के बावजूद लोक-संवेदना से संपन्न है। वे कठिन शब्दावली या जटिल बिंबों में कविता को उलझाते नहीं, बल्कि सहज-सरल भावों के माध्यम से पाठकों के हृदय तक पहुँचते हैं। शैली संवादात्मक है, जिसमें बातचीत करते हुये वे सभी को अपने साथ समेट लेते हैं। उनकी कविताओं में गद्य-कविता का आभास वर्तमान आधुनिक हिंदी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है।

इस संग्रह में कई स्तरों पर विषयों का विस्तार स्पष्ट होता है। आत्मीय रिश्ते और प्रेम को वे निजी अनुभव के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व के सार के रूप में देखते हैं। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और उसकी वापसी ही 'उम्मीद की तरह लौटना' है। कविताओं में समकालीन समाज की विडंबनाएँ, अन्याय और विषमताएँ भी उपस्थित हैं। लेकिन कवि केवल निराशा व्यक्त नहीं करता, वह समाधान की दिशा में उम्मीद जगाता है।

प्रकृति के माध्यम से जीवन और संवेदना की गहराई को पकड़ना उनके साथ आत्मसात होना इस किताब की बहुदा कविताओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। प्रकृति कविताओं में प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि आत्मीय साथी की तरह आती है। इन कविताओं में समय-समय पर पंकज सुबीर आत्म से संवाद करते है, जो पिता की अचानक अनुपस्थिति से उपजे प्रश्नों के उत्तर पा लेने की गहन आकांक्षा है। यह संवाद जीवन के मूल प्रश्नों जैसे मृत्यु, अस्तित्व, समय, स्मृति तथा भविष्य के लिए चिंतन की ओर ले जाता है।

पंकज सुबीर की कविताओं में एक प्रमुख गुण उनकी संवेदनात्मक गहराई है। वे मामूली-सी घटना या भाव को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वह बड़े जीवन-दर्शन में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, बिछोह की पीड़ा को वे केवल आँसू और दर्द तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे पुन: मिलन और लौटने की आशा में ढाल देते हैं। उनका भाव-संसार एक तरलता लिए हुए है, जहाँ व्यक्तिगत दुख भी उनकी कविताओं में आकर सामूहिक अनुभव बन जाता है।

इस संग्रह में संबंधों की गरिमा और उनकी संवेदनाओं को विशेष स्थान मिला है। लेकिन यह संवाद केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज में रिश्तों की उपस्थिति और उसकी भूमिका का भी सम्मान करता है। कवि इस रिश्ते को 'उम्मीद' के रूप में देखता है तथा जीवन में उजास और कोमलता लाने वाली शक्ति के रूप में भी।

पंकज सुबीर की कविताएँ अपेक्षाकृत छोटी और गहन हैं। कहीं-कहीं उनमें सूक्तियों जैसी संक्षिप्तता है, तो कहीं गद्यात्मक विस्तार। यह विविधता संग्रह को एकरूपता से मुक्त कर देती है और पाठक को ताज़गी का अनुभव कराती है। कविताओं का विचार और भाव का प्रवाह, बाँधे रखता है।

आज के समय में जब समाज हिंसा, अविश्वास और विघटन की ओर बढ़ रहा है, तब कविता का दायित्व है कि वह मनुष्य में मनुष्यता को बचाए रखे। पंकज सुबीर की कविताएँ यही करती हैं। वे बार-बार कहती हैं कि निराशा की कोई अंतिम मंज़िल नहीं है, बल्कि आशा ही जीवन का स्थायी सत्य है। यही कारण है कि उनका काव्य-स्वर समकालीन परिदृश्य में सार्थक और प्रासंगिक है।

संग्रह पढ़ते हुए हम एक आत्मीय यात्रा पर निकल जाते हैं। अपने खोए हुए रिश्तों को याद करते हैं, कभी वर्तमान समाज की जटिलताओं से रू-ब-रू होते हैं, अंतत: एक उजाले की ओर लौटते हैं। संग्रह की यह एक बड़ी उपलब्धि है कि वह भीतर तक छू लेता है और विचार मंथन के लिए प्रेरित करता है।

'उम्मीद की तरह लौटना तुम' केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक मानसिक-आध्यात्मिक यात्रा है। यह जीवन के अंधकार में एक मद्धम लौ में जलते दीपक की तरह है, जो आश्वस्त करता है कि चाहे कितनी ही कठिन घड़ियाँ आएँ, मनुष्य अंतत: उम्मीद और प्रेम की ओर लौटेगा। पंकज सुबीर की कविताएँ पाठक के भीतर छिपी आद्रता को जाग्रत करती हैं और एक बेहतर मनुष्य बनने का आह्वान करती हैं।

पंकज सुबीर का यह संग्रह हिंदी कविता की परंपरा में उम्मीद, प्रेम और मानवीय संवेदना के स्वर को और प्रखर करता है। यह संग्रह आग्रह करता है प्रत्येक कठिनाई, हर विफलता और सर्वथा अँधेरे के बाद 'उम्मीद की तरह' हमें लौटना ही होगा। यह संग्रह इसलिए भी सार्थक है, कि यह कविता से सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन का साहस और दिशा पाने के लिए भी प्रेरित करता है।

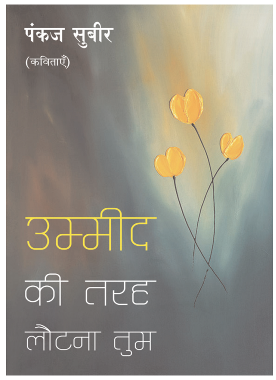

कविता संग्रह- 'उम्मीद की तरह लौटना तुम'
पंकज सुबीर, समीक्षक- शैलेन्द्र शरण
प्रकाशक : शिवना प्रकाशन, सीहोर (म.प्र.)
मूल्य- 300 रुपये

(लघुकथा)

गुड़िया

■ बसंत राघव

'पापा पता है क्या हुआ, जैसे ही आपका कॉल आया मैं जस्ट आपको ही कॉल करने वाली थी।' गुड़िया आगे बताने लगी 'हुआ क्या पापा कि चंद मिनट पहले, जब मैं बड़े पापा का स्टेटस देख रही थी ,उसमें दादा जी का फोटो लगा हुआ था। मेरे मन में एक मिनट के लिए खयाल आया कि मैं तो दादा जी से इतना कनेक्टेड थी ही नहीं। उनका प्रगाढ़ प्रेम तो केवल अपने पोते के लिए ही बरसता था। उनकी जान तो तिलस्मी कथाओं की तरह पोते में ही बसती थी। मैं तो उनके लिए सिर्फ एक बेजान गुड़िया थी, सर्वथा उपेक्षित! उनके जीवन से तिरोहित एक गुड़िया भर! फिर क्यों अचानक मैं उस स्टेटस को होल्ड कर देखने लगीं? ठीक दूसरे सेकंड सोचने लगी ,यह स्माइल तो हूबहू मेरे पापा की तरह है। हैं तो वे मेरे पापा के पापा ही न । सोचते -सोचते मुझे उन पर बहुत प्यार आने लगा। साथ ही आने लगीं कड़वी- मीठी यादें।'

समय के साथ गुड़िया बड़ी तो हो गई पर उसके भीतर की टीस अभी तक गई नहीं ! गुड़िया के एक-एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे।

गजलें

1

दिल है अपना तो ग़म पराए हैं
हाए क्या क्या फ़रेब खाए हैं

तार अश्कों का किस तरह टूटे
हम भी इक बार मुस्कुराए हैं

तकिया था ज़ाद-ए-राह पर अपना
राहज़न कितने काम आए हैं

मैं ये समझा था हम-सफ़र होंगे
आह कितने मुहीब साए हैं

भूल बैठे हूँ वो कहीं ऐ दिल
आज क्यूँ इतने याद आए हैं

2

ख़ाक उड़ती है रात-भर मुझ में
कौन फिरता है दर-ब-दर मुझ में

मुझ को ख़ुद में जगह नहीं मिलती
तू है मौजूद इस क़दर मुझ में

मौसम-ए-गिर्या एक गुज़ारिश है
ग़म के पकने तलक ठहर मुझ में

बे-घरी अब मिरा मुक़द्दर है
इश्क़ ने कर लिया है घर मुझ में

आप का ध्यान ख़ून के मानिंद
दौड़ता है इधर-उधर मुझ में

हौसला हो तो बात बन जाए
हौसला ही नहीं मगर मुझ में

■ रहमान फ़ारिस

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

आईसीसी से जुड़ा भारत इसलिए पाक से निभाता है क्रिकेट रिश्ते

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

अभी कुछ दिनों पूर्व दुबई में खेले गए एशिया क्रिकेट कप के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया था। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ था, ज़्यादातर मौकों पर भारत अपने दुश्मन देश को जंग के मैदान से क्रिकेट के मैदान तक में पटकनी देता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार उस समय हॉकी से लेकर क्रिकेट तक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले होते रहे थे, जब दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव या जंग जैसे हालात रहे थे। पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर आज मोदी की सरकार, कोई इन अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से किनारा नहीं कर सकती है। यह बात सब जानते और समझते हैं, लेकिन कुछ कथित बुद्धिजीवी और विपक्ष के नेता एशिया कप में भारत-पाक के बीच के मुकाबले ही आड़ लेकर मोदी सरकार को देश विरोधी साबित करने में लगे हैं। इसके लिए जनता को भड़काया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए बाध्य था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेना किसी भी क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी और समझौते का हिस्सा है। यदि भारत खेलने से इंकार करता तो कई स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, जिसमें आर्थिक, राजनैतिक और खेल जगत की प्रतिष्ठा प्रभावित होती। इस मुद्दे पर भारत में विरोध मुख्यतः राजनीतिक है, पर इसके पीछे आर्थिक, कूटनीतिक और खेल प्रबंधन की मजबूरियां भी हैं। एशिया कप जैसा टूर्नामेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) द्वारा आयोजित होता है, जिसमें सदस्य देशों को अपनी टीम भेजनी पड़ती है और पूरे मैच शेड्यूल का पालन करना होता है। अगर भारत भाग नहीं लेता या पाकिस्तान के साथ खेलने से इंकार करता, तो भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता और भविष्य के आईसीसी इवेंट्स में भारत की भागीदारी पर सवाल उठते। वहीं आर्थिक दृष्टि से, भारत-पाक मैच सबसे अधिक आकर्षण पैदा करता है, जिससे ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और रेवेन्यू में भारी नुकसान होता। भारत की छवि वैश्विक क्रिकेट जगत में नकारात्मक होती और आईसीसी सख्त कदम उठाता, जैसे जुर्माना या बैन। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत-पाक मैच सबसे बड़े दर्शक संख्या, हाईएस्ट टीवी रेटिंग्स और स्पॉन्सरशिप डील्स का केंद्र है। भारत के न खेलने से आईसीसी और एसीसी को करोड़ों रुपये का नुकसान होता। आईसीसी में भारत की वित्तीय हिस्सेदारी घट जाती। अन्य टेलीविजन नेटवर्क और ब्रॉडकास्टर्स को री-नेगोशिएशन करनी पड़ती। दरअसल, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि खेल प्रतियोगिताओं को लेकर भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान से द्विपक्षीय मैच नहीं, पर बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में सरकार की अनुमति से खेलना ही पॉलिसी है। द्विपक्षीय सीरीज या पाक में टूर्नामेंट की बीजेपी/सरकार इजाजत नहीं देती, पर एशिया कप, वर्ल्ड कप जैसे टाइटल्स में भाग लेना ज़रूरी है, ताकि भारत की क्रिकेट रणनीति, रेपुटेशन और ग्लोबल पोजिशन सुरक्षित रहे। बहरहाल, भारत में इस मैच को लेकर भारी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक बयानबाजी की लहर देखी गई। प्रमुख विपक्षी दलों से लेकर राजनीतिक संगठनों आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस आदि विरोध में सड़क पर उतर आए। पाक क्रिकेटर्स के पुतले जलाए गए।

चुनौतियां और विवाद – ट्रेड वार, नीति मतभेद और भू-राजनीतिक तनाव

आरती कुमारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्म दिवस पर फोन करना वैसे तो राजनीतिक शिष्टाचार में आता है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है, परंतु जिन परिस्थितियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बातचीत करने का बहाना खोजा है, उनके मध्य दोनों राष्ट्र – अध्यक्षों के मध्य इस प्रकार की ' चर्चा' होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और अमेरिका के संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं । रूस, चीन और भारत का एक साथ आना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे वह हतप्रभ रह गए हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत इतनी बड़ी भूमिका में आ सकता है ? – जिससे अमेरिका ही अलग-थलग पड़ जाएगा। इसके परिणामस्वरुप अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किये हैं। उनकी असफल विदेश नीति के चलते लोगों ने उनसे त्यागपत्र देने की बात कही है।उनके अपने निकटस्थ लोगों ने भी भारत के साथ संबंधों में आई तल्खी को लेकर ट्रंप प्रशासन को सचेत किया है । पिछले दिनों यह चर्चा भी चलती रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने का प्रयास किया ,परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया। इन सब बातों के चलते यदि अब ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से उनके जन्मदिवस के अवसर पर टेलीफोन से बातचीत की है तो इसे ' बातचीत करने का एक बहाना ' मानना चाहिए। निश्चित रूप से इस समय उन्होंने एक ' विजेता प्रधानमंत्री' से बातचीत की है। जिसने अमेरिका को उसकी औकात बताने का साहस किया है। और पहली बार उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग कर देने में सफलता प्राप्त की है। अमेरिका पर इस बात का भी नैतिक दबाव है कि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देते हुए इस समय रूस यूक्रेन युद्धविराम के लिए भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसके साथ ही इसराइल से अपने बहुत ही भावपूर्ण संबंध होते हुए भी भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपना हाथ उठाया है। ऐसे में अमेरिका यह भली प्रकार जानता है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। फिर भी यह बात मानी जा सकती है कि राजनीति में आप किसी से भी बहुत देर ' कुट्टी' करके नहीं बैठ सकते। राजनीति में कुंठाओं के लिए स्थान नहीं होता। क्योंकि कुंठाएं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। संकीर्णताओं और कुंठाओं को त्यागकर उनसे ऊपर उठकर बातचीत का कूटनीतिक संवाद निरंतर स्थापित रखना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से दोनों देशों के शासनाध्यक्षों का बातचीत करना सुखद है। हमने यह भी देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ वार में जितना अधिक आक्रामक होकर भारत के बारे में अनाप-शनाप बका, उतना ही उनका राजनीतिक नुकसान हुआ। भारत ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति को धोकर रख दिया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़बोलापन उनके लिए स्वयं एक आफत बन गया। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर संवाद स्थापित करने की ओर संकेत करते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह उम्मीद जताई है कि अंततः अमेरिका और भारत साथ आएंगे, क्योंकि यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देश अतीत की कड़वाहटों को बुलाकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने संबंधों का निर्धारण करेंगे। यह एक अच्छा संकेत है। जिससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका भी अब यह भली प्रकार जान गया है कि वह 21वीं सदी के सशक्त भारत के साथ सम्मानपूर्ण ढंग से बातचीत करके ही उसकी मित्रता का लाभ ले सकता है। यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 सितंबर को ही यह वक्तव्य दिया था कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं की बाधाओं को दूर करने पर बातचीत जारी रखेंगे। उनका यह वक्तव्य अमेरिका भारत संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट तो ये नहीं कहा कि भारत को लेकर उनसे कुछ भूल हुई है, जिसे वह सुधारना चाहते हैं , परंतु उनके वक्तव्य का एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है। भारत की वैश्विक मंचों पर निरंतर उपयोगिता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि भारत के बारे में लोगों की स्पष्ट धारणा यह है कि यह देश युद्धोन्मादी देश नहीं है। यह शांति चाहता है और शांति की वास्तविक अवधारणा को स्थापित करने के लिए उसके पास एक स्पष्ट चिंतन है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की इस गंभीर जिम्मेदारी को भली प्रकार जानते हैं। साथ ही वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति लोगों की इस स्वाभाविक धारणा को भी जानते हैं। इसलिए वह भारत को खोना नहीं चाहते। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आईटी, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा और तकनीकी निवेश में इन दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरा सहयोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गतिरोध को स्थाई शत्रुता में परिवर्तित करने के संकेत न देकर नरमी का संकेत देकर अमेरिकी राष्ट्रपति को यह स्पष्ट किया है कि दोनों देशों की जन अपेक्षाओं का सम्मान करना उनका उद्देश्य है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि दो देशों के शीर्षस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वों के टकराव से इतिहास में अनेक बार भयंकर जनहानि हुई है। आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की व्यक्तिगत अहंकारी भावना के कारण ही यूक्रेन युद्ध में टूट चुका है। इसलिए व्यक्तिगत अहंकार को सीमित रखकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर काम करना राजनीति की अनिवार्यता होती है। हमें प्रत्येक देश से अपने राष्ट्रीय हितों का सम्मान करवाना आना चाहिए, अर्थात झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यदि कोई देश हमारे राष्ट्रीय हितों का सम्मान कर रहा है अर्थात आपके सामने झुक गया है या झुकने का संकेत दे दिया है या झुकने को तैयार हो गया है तो उससे आगे जाकर उस देश से शत्रुता माल लेना अच्छा नहीं है। हम सबके लिए यह बहुत ही अच्छी सूचना है कि भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक उपलब्ध कराई है। हां, इतना अवश्य है कि वह पाकिस्तान को लेकर भारत के साथ दोरंगी चाल खेलता रहा है । पाकिस्तान को अपेक्षा से अधिक सहयोग और समर्थन देना अमेरिका की कूटनीति हो सकती है या उसकी विदेश नीति का एक अंग हो सकता है । परंतु यह भारत के लिए कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस बिंदु पर भारत को सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें जितना चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है, उतना ही अमेरिका से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सीट के लिए एक बार अमेरिका तैयार हो सकता है, परंतु चीन नहीं। इस दृष्टिकोण से भारत को अपनी विदेश नीति को अत्यंत सावधानी के साथ साधने की आवश्यकता है। हमें अपनी दूरगामी रणनीति और विदेश नीति को निर्धारित करते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उसमें किन-किन शक्तियों का हाथ रहा है ? इससे रहस्य का पर्दा बहुत कुछ हट गया है। धीरे-धीरे जो शेष है, वह भी हट जाएगा। वहां पर ' मोदी – मोदी' के नारे लगे हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के समर्थन में भी नारे लगे हैं। इसके साथ ही वहां की नई प्रधानमंत्री श्रीमती कार्की द्वारा भी भारत के प्रति सहयोगी और मित्रता पूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, किंतु इन सबका वास्तव में क्या अर्थ है ? यह देखना अभी शेष है। ये सभी नारे या गतिविधियां हवाई बातें भी हो सकती हैं और इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व भी हो सकता है। राजनीति में विभ्रम पैदा करना भी कूटनीति का एक अंग होता है। वास्तविकता बहुत कुछ देर बाद जाकर स्पष्ट होती है। कहने का अभिप्राय है कि नेपाल की घटनाओं से हमें बहुत अधिक सतर्क रहना है। किसी प्रकार की भ्रांति नहीं पालनी है। हां, यदि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने में भारत को अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। नेहरू की उस मूर्खता को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जब उन्होंने 1947 में नेपाल के तत्कालीन महाराजा के नेपाल के भारत में विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यदि आज की तारीख में नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में ही भारत के साथ आना चाहता है तो भारत को इस कार्य में नेपाल की सहायता करनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो अमेरिका को एशियाई मामलों में हस्तक्षेप करने से दूर रखा जा सकेगा। इसके साथ ही नेपाल और भारत स्थाई रूप से एक साथ आकर काम करने पर सहमत हो सकेंगे। यदि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है और भारत उसमें अपना सहयोग देता है तो इससे चीन की वास्तविकता का भी पता चल जाएगा कि वह वास्तव में ही भारत के साथ मित्रता पूर्ण संबंध चाहता है या फिर उसकी सोच में कोई दोगलापन है ? वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है, परंतु इसी मुद्दे को लेकर जब भारत और पाकिस्तान में तनाव होता है तो अमेरिका दोगला हो जाता है। तब वह पाकिस्तान की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। उसका यह दोगलापन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके चरित्र को उजागर कर देने के लिए पर्याप्त है। भारत को यह सोचना होगा कि अमेरिका चाहे कितना ही निकट आने का नाटक करे, परंतु उसका राजनीतिक दोगलापन उसके स्वभाव में सम्मिलित होने के कारण उसका ' राष्ट्रीय चरित्र' है। स्वभाव है। जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। यदि ऐसा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के इस टेलीफोन को एक अच्छा संकेत मानकर भी आप भविष्य के अमेरिका भारत संबंधों का एक निर्णायक मोड़ नहीं कह सकते। ....मंजिल अभी दूर है।

"डार्क मैटर" का रहस्य - क्या ग्रह बन सकता है - "छोटे ब्लैक होल?"

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

ब्रह्माण्ड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। जितना अधिक इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। सितारों, ग्रहों और गैलेक्सियों के बीच एक ऐसा अदृश्य तत्व मौजूद है जो पूरे ब्रह्माण्ड को संभाले हुए है। यह है "डार्क मैटर"। वैज्ञानिकों के अनुसार, "डार्क मैटर" ब्रह्माण्ड का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि सामान्य पदार्थ मात्र 5%। बाकी का 68% हिस्सा "डार्क एनर्जी" का है। दिलचस्प बात यह है कि "डार्क मैटर" को देख नहीं सकते, केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को महसूस कर सकते हैं।\ हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी ने "डार्क मैटर" से जुड़े एक बेहद चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा किया है। शोध के अनुसार, बृहस्पति (जुपिटर) जैसे विशाल गैस ग्रहों के भीतर "डार्क मैटर" जमा होकर उन्हें छोटे ब्लैक होल में बदल सकता है। यह दावा वैज्ञानिकों और आम लोगों, दोनों के लिए रोमांचक है, क्योंकि यदि यह सिद्ध हो गया तो ब्रह्माण्ड की संरचना और विकास की समझ पूरी तरह बदल जाएगी। "डार्क मैटर" को समझने से पहले यह जानना होगा कि यह आखिर है क्या। सामान्य पदार्थ (जिससे शरीर, पृथ्वी, सूर्य और गैलेक्सियाँ बनी हैं) इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड का अध्ययन किया तो पाया कि दृश्य पदार्थ से मिलने वाला गुरुत्वाकर्षण ब्रह्माण्ड की गतियों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। गैलेक्सी की बाहरी तारों की गति, गैलेक्सी क्लस्टर्स की संरचना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सबने इशारा किया है कि कोई अदृश्य पदार्थ है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पूरे ब्रह्माण्ड को थामे हुए है। इसी रहस्यमयी पदार्थ को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है "डार्क मैटर"। सौरमंडल के बाहर अब तक 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुका है। इन ग्रहों का अध्ययन केवल जीवन की संभावना जानने के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रह्माण्ड के रहस्यों को सुलझाने के लिए भी किया जाता है। कैलिफोर्निया की स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया है कि "डार्क मैटर" के भारी कण (Massive Particles) लंबे समय तक जुपिटर जैसे विशाल ग्रहों के भीतर जमा हो सकता है। समय के साथ यह कण एक केंद्र में इकट्ठा होकर इतना घना क्षेत्र बना सकता है कि ग्रह स्वयं ही छोटे ब्लैक होल में बदल जाए। इसका अर्थ यह है कि अगर यह थ्योरी सही हुई, तो हर बड़ा ग्रह "डार्क मैटर" के लिए एक प्रकार का "जाल" बन सकता है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना और द्रव्यमान 318 गुना अधिक है। इतना विशाल ग्रह डार्क मैटर को अपनी ओर खींचने और उसे भीतर समाहित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यदि जुपिटर जैसे ग्रहों के भीतर डार्क मैटर के कण फंसकर इकट्ठा होने लगें तो धीरे-धीरे उनका घनत्व इतना अधिक हो सकता है कि वे ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ब्लैक होल बनने की सामान्य प्रक्रिया तारों के ढहने से जुड़ी होती है। जब सूर्य से कई गुना बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से ढहकर ब्लैक होल में बदल जाता है। लेकिन अगर "डार्क मैटर" ग्रहों में इकट्ठा होकर ब्लैक होल बनाए, तो यह बिल्कुल नई और अनोखी प्रक्रिया होगी। "डार्क मैटर" कणों का ग्रह में प्रवेश- "डार्क मैटर" हर जगह फैला हुआ है। जब ग्रह अपनी कक्षा में घूमता हैं, तो "डार्क मैटर" कण उनके भीतर प्रवेश करता रहता है। कणों का जमावड़ा- धीरे-धीरे यह कण ग्रह के केंद्र में जमा होने लगता है। घनत्व में वृद्धि- समय के साथ घनत्व इतना बढ़ जाता है कि वह सामान्य गुरुत्वाकर्षण को पछाड़ देता है। ब्लैक होल का जन्म- ग्रह का केंद्र ध्वस्त होकर ब्लैक होल का रूप ले सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्पेस टेलीस्कोप्स और नए मिशन इस थ्योरी की जांच कर सकता है। यदि किसी ग्रह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ा हुआ दिखे या वहां से अनजान रेडिएशन निकलता हो, तो यह "डार्क मैटर" की गतिविधि का प्रमाण हो सकता है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) और भविष्य के मिशन जैसे रोमन स्पेस टेलीस्कोप इस रहस्य से पर्दा उठाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि "डार्क मैटर" ग्रहों को ब्लैक होल में बदल सकता है, तो इसके गहरे प्रभाव होंगे। यह स्वीकार करना होगा कि ग्रह भी ब्लैक होल बनने की क्षमता रखता है। इससे पता चलेगा कि "डार्क मैटर" किस प्रकार के कणों से बना है और वे कैसे व्यवहार करता है। अगर "डार्क मैटर" ग्रहों को निगल सकता है, तो भविष्य में पूरी गैलेक्सियों की संरचना बदल सकता है।

मेष राशिफलः आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आपका दिन अच्छा है, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही आई. टी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी आज जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। आज कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे। साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे।

वृषभ राशिफलः आज आप व्यापार में नई प्लानिंग से कार्य करेंगे। आज आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा , जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी। आज आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में अधिक धन लाभ होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी।

मिथुन राशिफलः आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आज आप जरूरतमंद की तरफ मदद का हाथ बढ़ायेंगे, जिससे उनका भी जीवन सहज हो सके। इस राशि के जो छात्र फैशन डिजायनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें आज कुछ नया डिजाईन करने को मिल सकता है। आज व्यापार में लाभ होने की संभावना है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

कर्क राशिफलः आज आपको आर्थिक रूप से अपने करीबियों से मदद मिलेगी। आज करियर में आपको अपने सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आज आपको नकारात्मक सोच से भी बचना होगा। आज आप परिवार के साथ किसी टूर का प्लान बनायेंगे। आज लेन-देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आज कामकाज की अधिकता आपके सेहत पर असर डाल सकती है।

सिंह राशिफलः आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा। इस राशि के नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आज आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आज सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तथा आज आपके मनोबल में वृद्धि होगी।

कन्या राशिफलः आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनायेंगे। आज आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा और आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे।

तुला राशिफलः आज आप माता-पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जायेंगे। आज परिवार का माहौल भी खुशनुमा बन रहेगा। आज आपको व्यापार में बड़ी डील मिलने से धन लाभ होगा। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत बिजी रहेंगे। आज आप ऑफिस में बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जिससे आपके प्रमोशन के चांस बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक राशिफलः आज आपका दिन उत्तम बना रहेगा। इस राशि के कारोबारियों को धन लाभ होने की संभावना है। आज ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप जीवनसाथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनायेंगे।

धनु राशिफलः आज आपको बच्चो से अच्छी खबर मिलेगी। इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। आज व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। आज जीवनसाथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा।

मकर राशिफलः आज आप जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। आज दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको ख़ुशी मिलेगी। आज आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आपको रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। साथ ही कार्य क्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के स्पोर्ट्स में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को आज स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा।

कुंभ राशिफलः आज जीवनसाथी के सहयोग से आपका काम पूरा हो जायेगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया भी प्राप्त होगा। इस राशि के टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। साथ ही किसी काम में आपको सफलता मिलेगी। आज आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे लेकिन आज आपको जल्दबाजी में फैसला करने से बचना चाहिए।

मीन राशिफलः आज मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आज आर्ट्स स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जायेगी। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को कामकाज में सहकर्मियों .का साथ मिलेगा, जिससे आपका काम आसानी से हो जायेगा।

आतंकवाद पर सहानुभूति : न्याय के बीच एक जरूरी सवाल

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया पत्र, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती का तर्क यह है कि मलिक ने हिंसा छोड़कर राजनीतिक मार्ग अपनाया है और वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं इसलिए उनके कष्टों पर विचार होना चाहिए। वस्तुतः यह सिर्फ एक राजनीतिक निवेदन भर नहीं है; यह हमारे नैतिक विवेक, न्याय के सिद्धांत और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता का बड़ा परीक्षण भी है कि क्या आतंकवादियों पर दया दिखाना उचित है? यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों का सबसे प्रमुख और जाना-माना मामला 1989 में हुए रुबैया सईद अपहरण से जुड़ा है। उस वर्ष 8 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया गया था। रुबैया उस वक्त मेडिकल इंटर्न थीं और हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थीं, तभी उन्हें एक बस में जबरन उतार कर जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। यह अपहरण पूरी तरह योजनाबद्ध था, जिसमें यासीन मलिक की मुख्य भूमिका मानी जाती है। रुबैया सईद ने कोर्ट में प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यासीन मलिक को अपने अपहरणकर्ताओं में एक के रूप में पहचाना है। इस अपहरण के बदले में आतंकवादियों ने पांच आतंकियों की रिहाई की मांग की थी, जिन्हें सरकार को छोड़ना पड़ा था। यह घटना न केवल जम्मू-कश्मीर में तनाव की आग भड़काने वाली साबित हुई बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती थी। यासीन मलिक के खिलाफ अन्य गंभीर आरोपों में 1990 में भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों पर हमला शामिल है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में भी आरोपी हैं। इन मामलों में मलिक को उम्रकैद की सजा मिली है और वह वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सजा के बावजूद यासीन मलिक की गतिविधियां और उनके समर्थकों की कई बार मानवीय दृष्टिकोण से उनकी रिहाई की मांग उठती रही है, जिस पर राजनीतिक विवाद भी होता रहा है। पर हकीकत यही है कि यासीन के खिलाफ लगे गंभीर आरोप और आतंकवादी गतिविधियों की गवाही इसकी गंभीरता दर्शाती है । सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी की कथित 'बदली हुई' पहचान और बीमारी उसके पूर्वकृत्यों की स्मृतियों को मिटा देती है? क्या सहानुभूति का मतलब अपराधों के नकारात्मक प्रभावों को भुला देना हो सकता है? वास्तव में जो इस तरह की मानवीयता के आधार पर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद केवल कानूनी शब्दावली का मसला नहीं है, यह मानवता के विरुद्ध एक हिंसक हमला है। जब आतंकवादी निर्दोष नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं, तब किसी भी समाज का तंत्र सुरक्षा संकट का सामना करता है। उन परिवारों की जिंदगियाँ बिखर जाती हैं जिनके अपनों को खोया गया। 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा जैसे हमले और लंबे वर्षों से कश्मीरी सन्दर्भ में हुए अनगिनत रक्तरंजित मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का परिणाम केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं होता, यह पूरे समाज की आस्था और सुरक्षा पर चोट करता है। इन हत्याओं से जुड़े जख्मों का इलाज सिर्फ शब्दों से, या किसी नेता की सहानुभूति से नहीं हो सकता है, इसके लिए न्याय प्रक्रिया, जवाबदेही और पीड़ितों के अधिकारों की संवेदनशील रक्षा अनिवार्य है। यासीन मलिक जैसे मामलों में दो अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़ी बातें सामने आती हैं, एक राज्य की यह जिम्मेदारी थी कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दोषियों को ऐसी सजा दिलवाने की पहल करता, जो कानून के अनुरूप होती। दूसरा- समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी कि वह पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा रहे। यह होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की बीमारी या किसी भी वक्त के पश्चात् अपनाया गया राजनीतिक रास्ता, अनसुलझे और गंभीर आरोपों की जांच-परख और सम्भवतः दंड प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकता। क्या पूर्व अपराधों को केवल इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है कि आरोपी ने अब राजनीतिक बहस का रास्ता चुना है? यह सही है कि किसी भी अपराधी को सुधार का अवसर दिया जाना न्याय व्यवस्था का एक स्तम्भ है, पर आतंकवाद की हद तक पहुँच चुके मामलों में यह प्रश्न उठता है कि क्या वही दमन, हिंसा और निर्दोषों की हत्याएँ 'सुधार' के दायरे में आ सकती हैं। जब कोई हिंसा का औजार बन चुका व्यक्ति ऐसी क्रूरता का माध्यम रहा हो, तब पहले यह देखा जाना चाहिए कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों की गंभीरता क्या है, क्या तथ्य और साक्ष्य हैं, और क्या वह सच्चाई से सामना करने तथा दायित्व निभाने को तैयार है? सिर्फ कथन से यह तय नहीं होना चाहिए कि अपराधी ने मन बदल लिया है। हमारे समाज को यह भी याद रखना होगा कि सहानुभूति की भावना अनिवार्य रूप से मानवता का परिचायक है, पर जब यह सहानुभूति उन लोगों के प्रति जताई जाए जिनके कर्मों ने हजारों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी हो, तब यह सहानुभूति पीड़ितों के प्रति अन्याय की शक्ल धारण कर लेती है। शत्रुता और हिंसा के अपराध कहाँ खत्म होते हैं और इंसानियत कहाँ फिर से शुरू होती है, यह सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक नेता, किसी भी सरकार या किसी भी न्यायिक निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता, त्वरित और निष्पक्ष जांच, पीड़ितों की भागीदारी और कानून के अनुरूप न्याय दिलाने का मार्ग अपनाया जाए। यहां कुल कहना यही है कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जो मांग प्रतिबंधित जेकेएलएफ सुप्रीमो मोहम्मद यासीन मलिक को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है, उसका मानवीय आधार ही अनुचित है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मानवीय आधार नहीं हो सकता है। भले ही यह एक बहस का विषय हो, पर यासीन मलिक जैसे मामलों में सहानुभूति, न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। बीमारी और मानवीय कष्ट पर सहानुभूति दिखाना मानवतावादी रवैया है किंतु वह अपराधों की भूल और पीड़ितों के दर्द को मिटाने का औजार नहीं बन सकता। वास्तव में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की यह सहानुभूति उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है, जिन्होंने अपनी जानें और अपनों को खोया है और यदि उनके कहे अनुसार सरकार सच में इस आतंकवादी को छोड़ती है, तो यह आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के ऊपर आज सबसे बड़ा अन्याय होगा।

पाकिस्तान और सऊदी अरब में सुरक्षा समझौते में कहा गया कि दोनों में से किसी भी एक मुल्क पर कोई हमला होता है तो इसे दोनों मुल्कों के खिलाफ अंजाम आक्रमण समझा जाएगा। तत्कालीन नजरिए से देखें तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पाक-सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत बड़ा सैन्य और कूटनीतिक झटका है। हां, ये जरूरी है कि इस समझौते से पाकिस्तान को सऊदी से वित्तीय और तेल सहायता मिल सकती है, जो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की शक्ति बढ़ाएगी। ऐसे में भारत को इसे गंभीरता से लेना होगा और बदलती भू-सामरिक स्थिति को साधने के लिए अपनी सैन्य क्षमता और ज्यादा बढ़ानी होगी। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से देखा, समझा और परखा जाए तो पाक-सऊदी सुरक्षा करार निश्चित तौर पर भारत के लिए खतरनाक संकेत भी है। हालांकि, सऊदी अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते मज़बूत बने रहेंगे और वे क्षेत्रीय शांति के लिए योगदान देते रहेंगे। फिर भी यदि यह समझौता क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है तो यह सभी के लिए लाभदायक होगा, लेकिन यदि यह टकराव को बढ़ावा देता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। पाक-सऊदी सुरक्षा समझौते का विश्लेषण करता *आजकल* का खास अंक...

पाक-सऊदी सुरक्षा करार के मायने

विश्लेषण

प्रभात कुमार रॉय
विदेश मामलों के जानकार

डिफेंस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब में करार अंजाम दिया गया है कि दोनों में से किसी भी एक मुल्क पर अंजाम दिए गए सैन्य आक्रमण को दोनों मुल्कों के खिलाफ अंजाम दिया गया आक्रमण समझा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब विगत अनेक वर्षों से भारत का शीर्ष आर्थिक और रणनीतिक साझीदार है। यक्ष प्रश्न है कि यदि दशकों पुरानी अपनी नृशंस जेहादी फितरत के वशीभूत होकर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद जारी रखेगा तो सऊदी अरब क्या पाकिस्तान के साथ भारत के विरुद्ध मैदान-ए-जंग में उतर

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा 17 सितंबर को एक स्ट्रैटेजिक म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए गए हैं। डिफेंस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब में करार अंजाम दिया गया है कि दोनों में से किसी भी एक मुल्क पर अंजाम दिए गए सैन्य आक्रमण को दोनों मुल्कों के खिलाफ अंजाम दिया गया आक्रमण समझा जाएगा। तत्कालीन नजरिए से दृष्टिपात करें तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि पाक-सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत बड़ा सैन्य और कूटनीतिक झटका है। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से देखा, समझा और परखा जाए तो पाक-सऊदी सुरक्षा करार निश्चित तौर पर भारत के लिए खतरनाक संकेत प्रस्तुत कर रहा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत विरोधी आचरण अख्तियार करने के तत्पश्चात और ट्रंप द्वारा भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को कहीं अधिक महत्व प्रदान करने के कारणवश, पाकिस्तान वस्तुतः अचानक पश्चिम एशिया में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुल्क बन गया है। खाड़ी मुल्क अपनी सुरक्षा की खातिर अब पाकिस्तान, तुर्कीए और चीन की तरफ झुकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अभी तक अमेरिका की सुरक्षा पनाह में कायम बने रहे खाड़ी मुल्कों के लिए ये तीनों ही देश अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन और तुर्कीए तो पूरी तरह पाकिस्तानी पक्ष के साथ सन्नद खड़े रहे थे। अब लगता है कि पाकिस्तान के कट्टर समर्थकों की कतार में अमेरिका का अंध अनुसरण करते हुए सऊदी अरब भी बाकायदा शामिल हो गया है।

रणनीतिक साझीदार मुल्क

भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब विगत अनेक वर्षों से भारत का शीर्ष आर्थिक और रणनीतिक साझीदार मुल्क रहा है। यक्ष प्रश्न है कि यदि मुस्तकबिल में दशकों पुरानी अपनी नृशंस जेहादी फितरत के वशीभूत होकर पाकिस्तान यकीनन भारत के विरुद्ध अपनी आतंकवादी कार्रवाइयां जारी रखेगा और जेहादी आतंकवाद का प्रतिकार और प्रतिशोध लेने के लिए पाकिस्तान पर भारत पुनः सुरक्षात्मक आक्रमण भी अंजाम देगा, तो सऊदी अरब क्या पाकिस्तान के साथ भारत के विरुद्ध मैदान-ए-जंग में उतर जाएगा? यह मुमकिन है कि सऊदी अरब अपने फौजी दस्तों को भारत के विरुद्ध आक्रमणकारी युद्ध में पाकिस्तान के पक्ष में कदापि नहीं भेजें, किंतु सऊदी अरब का पेट्रो डॉलर का अकूत खजाना पाकिस्तानी फौज को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत विशाल आर्थिक इमदाद तो कर ही सकता है।

अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी

सऊदी अरब के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी विद्यमान रही है। डिफेंस एग्रीमेंट के पश्चात सऊदी अरब आधुनिकतम सैन्य टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को उपलब्ध करा सकता है। पाकिस्तान की फौज के लिए अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी की उपलब्धता बड़ी सौगात सिद्ध होगी और यह सैन्य स्थिति भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। खाड़ी मुल्कों में सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है और इसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट क्यों अंजाम दिया है, जटिल प्रश्न है इसका समुचित उत्तर है कि अमेरिका पर अब खाड़ी मुल्कों को अधिक यकीन कायम नहीं रह गया है। इस्लामी दुनिया की नजरों में डोनाल्ड ट्रंप की कयादत में अमेरिका वस्तुतः इजरायल का अंध समर्थक देश बनकर उभरा है। दो दिनों में गाजा युद्ध को खत्म करने का दावा करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गाजा में युद्ध विराम के लिए राजी नहीं कर सके हैं। सऊदी अरब इस्लामी मुल्कों का सर्वोच्च लीडर देश बन जाने की बड़ी ख्वाहिश पाले रखता है और इस मामले में उसका मुकाबला सदैव तुर्कीए के साथ रहा है।

अमेरिका दुश्मन करार

हाल ही में हमास सरगनाओं को कत्ल करने की खातिर कतर पर अंजाम दिए गए इजरायली आक्रमण ने पश्चिमी एशिया स्थिति को बहुत बिगाड़ कर रख दिया है। कतर में अमेरिका का अल उदेद नामक एयरबेस विद्यमान है। इसके बावजूद 9 सितंबर को कतर पर अंजाम दिए गए इजरायली आक्रमण पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 से ही खाड़ी के देशों में अमेरिका का किरदार एक सैन्य सुरक्षा प्रदान करने वाले मुल्क का बना रहा है, किंतु इजरायल बनाम गाजा की जंग में अमेरिका की भूमिका पर पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में हलचल मची हुई है। अमेरिका को इस्लामी मुल्कों का दुश्मन करार दिया जाने लगा है। पश्चिम एशिया के मुल्कों का जनमत अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो गया है। विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत द्वारा सऊदी अरब और अन्य खाड़ी मुल्कों से अपने कूटनीतिक ताल्लुकातों को शक्तिशाली बनाने के लिए गहन और गंभीर प्रयास किए गए। भारत द्वारा सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक संबंध को रणनीतिक संबंध के उच्च शिखर तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्ष माह अप्रैल में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। आखिरकार क्या परिणाम निकला परस्पर संबंधों को ताकतवर बनाने का, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दामन थाम लिया? क्या अब वो भविष्य में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा? इस्लामी मुल्क भविष्य में अपनी हिफाजत के लिए पश्चिमी मुल्कों के नॉटो सैन्य संगठन की तर्ज ओ तरीके पर एक अपना इस्लामी सैन्य संगठन तशकील करने के विषय में संजीदगी से विचार विमर्श करने में जुटे हुए हैं। इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान ही एक अकेला ऐसा मुल्क है, जिसके पास परमाणु अस्त्रों की ताकत है।

परमाणु अस्त्रों की क्षमता

अपनी परमाणु अस्त्रों की क्षमता के कारण पाकिस्तान अब अमेरिका से हताश निराश हुए खाड़ी मुल्कों का दुलारा और प्यारा मुल्क बन गया है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सेंट्रल ट्रीटी सैन्य संगठन का सदस्य देश बनाया गया, जिसे बगदाद पैक्ट भी कहा गया। जेहादी सरगना ओमामा बिन लादेन को वर्षों तक पाक फौज की निगरानी पनाह देने वाले पाक हुक्मरानों को अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने गले से लगाने लगे हैं। भारत ने उन विकट हालात का वीरता और बलिदान देकर कामयाबी से मुकाबला कर लिया और जेहादियों को परास्त किया जबकि अमेरिका, पाकिस्तान और पेट्रो डॉलर उसके बड़े शत्रु बने हुए थे। अब तो भारत बहुत ताकतवर है और ग्लोब्ल साऊथ के देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। ब्रिक्स की शक्ति भारत के साथ सन्नहित है। हर हाल में भारत फतेहयाब होकर रहेगा।

पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौते से भारत रहे सतर्क

रणनीति

विवेक शुक्ला
वरिष्ठ स्तंभकार

लुटियंस दिल्ली के दिल में भारत के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय साउथ ब्लॉक में इन दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते का भारत पर किस तरह का असर होगा, इस विषय पर विभिन्न कोणों से अध्ययन हो रहा होगा। इस समझौते को 'स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' नाम दिया गया है, जिसमें एक प्रमुख धारा यह है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता नाटो-शैली का है, जहां हमले की स्थिति में दोनों देश एक-दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समझौते की पृष्ठभूमि में हाल की क्षेत्रीय घटनाएं, जैसे इजरायल का कतर पर हमला और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी में आई कमजोरी, प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भारत के लिए यह समझौता एक दोधारी तलवार है। एक ओर, भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। भारत सऊदी से 100 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार करता है।

भारत मुख्य रूप से तेल आयात करता है सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उसके संबंध मजबूत रहेंगे और यह समझौता भारत के खिलाफ नहीं है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी यात्रा के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई थी। खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जो रेमिटेंस का बड़ा स्रोत हैं। बेशक, यह समझौता भारत की मध्य पूर्व नीति को चुनौती देता है। पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, जो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने कहा कि भारत इस विकास का अध्ययन करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। भारत के लिए अवसर भी हैं। यह समझौता भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर देता है। क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे गठबंधनों को मजबूत करना, अंडमान-निकोबार द्वीपों पर रक्षा बुनियादी ढांचा विकसित करना और नौसेना गश्त बढ़ाना आवश्यक है। भारत ओमान, यूएई और बहरीन जैसे मध्यमार्गी खाड़ी देशों से संबंध मजबूत कर सकता है। ऊर्जा विविधीकरण के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर जोर देना चाहिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। 1960 के दशक से ही पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य प्रशिक्षण, सैनिकों की तैनाती और रक्षा सहायता प्रदान करता आया है। हालांकि, यह नया समझौता पहले के अनौपचारिक संबंधों को औपचारिक रूप देता है, जो क्षेत्रीय तनावों के कारण आवश्यक हो गया था। हाल ही में इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया, जो सऊदी अरब की सीमा से सटा हुआ है। इस हमले में अमेरिका की चुप्पी ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर संदेह पैदा कर दिया। अमेरिका के पास मध्य पूर्व में करीब 40,000-50,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन इजरायल के हमलों पर वाशिंगटन की निष्क्रियता ने सऊदी अरब को वैकल्पिक सुरक्षा भागीदारों की तलाश करने पर मजबूर किया। इसी संदर्भ में पाकिस्तान, जो मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश है, सऊदी अरब के लिए एक आकर्षक सहयोगी बन गया। समझौते में रक्षा उद्योग सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सैन्य सह-उत्पादन शामिल हैं, जो दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेंगे। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि यह समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने वाला है। मध्य पूर्व में इजरायल की आक्रामकता और ईरान के साथ तनाव के बीच सऊदी अरब को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी। पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक लाभ का स्रोत है, क्योंकि सऊदी अरब से तेल आपूर्ति और वित्तीय सहायता मिल सकती है। अब जान लेते हैं कि यह समझौता दोनों देशों के लिए क्यों अहम है? सबसे पहले, सऊदी अरब के लिए यह अमेरिकी निर्भरता से मुक्ति का कदम है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता इस समझौते को और मजबूत बनाती है। पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक संकट से उबरने का अवसर है। पाकिस्तान को सऊदी से तेल आपूर्ति, निवेश और सैन्य सहायता मिल सकती है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण हैं। इस समझौते से पाकिस्तान को सऊदी की वित्तीय और तेल सहायता मिल सकती है, जो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की शक्ति बढ़ाएगी। यदि यह समझौता क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है, तो यह सभी के लिए लाभदायक होगा, लेकिन यदि यह टकराव को बढ़ावा देता है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, जो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है।

रक्षा सहयोग के साथ ही एक रणनीतिक संदेश

कूटनीति

महेंद्र तिवारी
स्वतंत्र पत्रकार

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुआ सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता दक्षिण एशियाई राजनीति और भारत–सऊदी रिश्तों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस समझौते को पश्चिम एशिया और एशियाई राजनीति के कई जानकार केवल रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश मानते हैं।

अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुलेगमेन ने कहा कि यह केवल सैन्य सहयोग का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान का यह दिखाना है कि वह चीन, तुर्की और अब सऊदी जैसे बड़े सहयोगियों के साथ खड़ा है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इसे भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने वाली दीवार मानना जल्दबाजी होगी। पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार जहाकतनवीर ने भी याद दिलाया कि सऊदी–पाक रक्षा समझौता कोई नई बात नहीं है। अतीत में ऐसे कई समझौते हुए हैं जो ज्यादातर सऊदी की सुरक्षा तक सीमित रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान की सेना को कई बार सऊदी हितों के लिए किराए की सेना कहा गया है। सीधे भारत के खिलाफ सैन्य सहयोग की संभावना फिलहाल बेहद कम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरा रहा है।

ईरान–इराक युद्ध के दौरान (1980–88) पाक ने सऊदी को सुरक्षा का भरोसा दिया था। 1965, 1971 और कारगिल 1999 के भारत–पाक युद्धों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वित्तीय और राजनयिक मदद दी, पर उसने कभी भारतीय मोर्चे पर अपनी सेना नहीं भेजी। 2014–15 में सऊदी ने इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसका नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहील शरीफ को सौंपा गया था। इन घटनाओं से यह साफ है कि सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता परस्पर जरूरतों और रणनीतिक लाभ पर आधारित रहा है। इस नए डिफेंसएग्रीमेंट ने इस रिश्ते को एक नया आयाम दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्तों की बात करें तो सऊदी ने कभी भी भारत विरोधी आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया।

इसके उलट, दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार, निवेश और प्रवासी भारतीयों के माध्यम से मजबूत आर्थिक और सामाजिक संबंध हैं। सऊदी अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे और वे क्षेत्रीय शांति के लिए योगदान देते रहेंगे। कुल मिलाकर, यह रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक राहत, सऊदी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी, और भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है।

यह रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक राहत, सऊदी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी, और भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है।

सार्वभौम उदारता त्यागकर अब कठोरता दिखाए भारत

विमर्श

विकेश कुमार बडोला
स्वतंत्र स्तंभकार

अंतराष्ट्रीय कूटनीतियां आधुनिक युग में संतुलन की स्थिति में हैं ही नहीं। विदेश स्तर की कूटनीतियों का यह असंतुलन भारत के लिए प्रतिदिन समस्या खड़ी कर रहा है। नवीन समस्या पाकिस्तान तथा सऊदी अरब के मध्य गत 17 सितंबर को हस्ताक्षरित हुए एक रणनीतिक रक्षा अनुबंध के परिप्रेक्ष्य में उभर रही है। दोनों देशों ने हस्ताक्षरित अनुबंध प्रारूपों का आदान-प्रदान करने की समयावधि में एक संयुक्त वक्तव्य दिया है कि उनमें से किसी भी देश पर किसी भी प्रकार के आक्रमण को दोनों ही देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।

विचारणीय 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा अनुबंध' पर सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। दो मुस्लिम देशों के बीच हुआ यह अनुबंध भारत के लिए कई संदर्भों में चिंतनीय है। अभी तक इस अनुबंध पर भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ही वक्तव्य आया है। उनके अनुसार, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कार्य करेगा तथा सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिका की पहल पर भारत विरोधी दो मुस्लिम देशों की इस नई गुटसापेक्षता द्वारा भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि सऊदी से भारत के द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। चाहे द्विपक्षीय स्थिर संबंध हों, ऊर्जा सुरक्षा हो, निवेश का बड़ा प्रवाह हो अथवा वहां रह रहे भारतीयों द्वारा उस देश के चहुंदिश विकास में उच्च स्तर की पदाधिकारिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए जाने का सत्य हो, किंतु अब परिस्थिति भिन्न हो चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में ही दोनों देशों का परस्पर व्यापार 42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हुआ था, जिसमें से हमने वहां से 31.42 बिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया तो यहां से वहां 11.56 बिलियन यूएसडी मूल्य का निर्यात संपन्न हुआ। भारत कच्चे तेल तथा पेट्रो उत्पादों की बड़ी मात्रा के लिए अरब देश पर निर्भर है। विगत में दोनों देशों के विशिष्ट संबंधों का परिलक्षण तब दिखा था जब 2016 में

भारत उन देशों के प्रति सार्वभौम उदारता प्रदर्शित करना बंद करे, जो द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकाल तक संभाले रखने की तुलना में स्वार्थ व एकाधिकार की नीतियों के कारण उन्हें तोड़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं

सलमान बिन ने नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग अब्दुल अजीज सैश' प्रदान किया था। भारतीय नेतृत्व के प्रति इस सीमा तक सम्मान प्रदर्शित करने के बाद भी आज अकस्मात अमेरिकी दबाव में सऊदी की वैश्विक दक्षिण में भारत के प्रति एक विरोधी छवि उभर कर सामने आई है। हालांकि अभी पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए रक्षा अनुबंध की विस्तृत रूपरेखा सामने नहीं आई है, किंतु इतना तो निश्चित है कि यदि पाकिस्तान के साथ रक्षा-सुरक्षा रणनीतिक समझौते के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों की ओर से किसी शत्रु देश का संकेत उभरता है, तो पाकिस्तान के संदर्भ में तो वह भारत ही हुआ, और सऊदी के पाकिस्तान के साथ होने के संकेतन का अर्थ भी यही है कि वह भी अप्रत्यक्ष रूप में भारत का शत्रु ही हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के सामने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को नवाकार देने की चुनौती उभर आयी है।

गत आठ-नौ माह में भारत के संबंध अमेरिका के साथ जिस ढंग से असंतुलित हुए हैं, उस कारण भारत के प्रति सऊदी की द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति में भी परिवर्तन आ चुका है। सामरिक सुरक्षा हेतु अमेरिकी कृपा पाने के लिए सऊदी ने भारत के प्रति अपनी कूटनीतिक स्थितियां उसी प्रकार ढाल ली हैं, जैसे अमेरिका ने उससे अपेक्षा की है, और निश्चित रूप में अमेरिकी शासन मध्य एशिया में खाड़ी के अग्रणी देशों में से एक सऊदी को भारत के अनुकूल बनाये नहीं रखना चाहता। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की समयावधि में पाकिस्तान के बहाने भारत व अमेरिका के संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ था, इसीलिए अमेरिका उसी के माध्यम से सऊदी को भारत के प्रतिरोध में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है।

अरब देश भारत विरोधी पाकिस्तान वाले गुट में सम्मिलित होने की अमेरिकी मंशा का विरोध नहीं कर सकता है और तब तक तो कदापि नहीं कर सकता है, जब तक वह अपनी सामरिक आवश्यकताओं के लिए अधि सीमा तक अमेरिका पर ही निर्भर है। भारत के प्रति अमेरिका, चीन, सऊदी अरब तथा अन्य देशों का जो कूटनीतिक भेदभाव परिलक्षित हो रहा है, उससे हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी होगी कि अब भविष्य में भारत कम से कम उन देशों के प्रति सार्वभौम उदारता प्रदर्शित करना बंद करे, जो पारस्परिक द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकाल तक संभाले रखने की तुलना में स्वार्थ व एकाधिकार की नीतियों के कारण उन्हें तोड़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

समझौते से बढ़ सकती हैं भारत की सैन्य मुश्किलें

सैन्य चुनौती

डॉ. एन. के. सोमानी
वरिष्ठ पत्रकार

ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह से पिट चुका पाकिस्तान अब अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए सैन्य समझौतों की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब के साथ किया गया स्ट्रेटेजी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व वाले समझौतों और गठबंधनों का हिस्सा रहा है लेकिन सऊदी अरब के साथ हुआ समझौता उस बाध्यकारी खंड के कारण अहम हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों में से किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह के हमले को दोनों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा।

समझौते की शब्दावली एक तरह से नाटो के खंड 5 की 'कॉपी' है, जिसमें कहा गया है कि एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य उससे अपनी तरह से निबटेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान-सऊदी अरब सुरक्षा समझौते को मीडिल ईस्ट में नाटो का आरंभ कहा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि जल्दी ही कुछ और देश भी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत ने समझौते पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत का कहना है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्यन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह किसी न किसी तरह भारत को दुनिया के बड़े देशों से अलग-थलग कर दे। पाक नेताओं और फिल्ड मार्शल असीम मुनीर के विदेश दौरों का सिलसिला पाकिस्तान की इस कोशिश का ही परिणाम है। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, हम संबंधों को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह समझौता किसी खास देश या घटना विशेष की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और गहन सहयोग का संस्थागत रूप है। हम क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने का प्रयास करेंगे। भारत और सऊदी के बीच अरसे से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा

निसंदेह समझौते के बाद पाकिस्तान की ताकत और अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत को स्ट्रेटेजी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को गंभीरता से लेना होगा तथा अपनी सैन्य क्षमता और ज्यादा बढ़ानी होगी।

व्यापारिक साझेदार है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सऊदी और उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत अहम देश है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से भी दोनों देश रक्षा सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद, उग्रवाद और वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत और सऊदी अरब के संबंध खासे मजबूत हुए हैं। मोदी अब तक तीन बार (2016, 2019 और अप्रैल 2025) सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। साल 2016 में जब पीएम मोदी पहली दफा सऊदी की यात्रा पर गए, उस वक्त सऊदी अरब ने उन्हे अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। साल 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर आए तो पीएम मोदी खुद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। भारत यात्रा पर आए सऊदी प्रिंस ने उस वक्त कहा था कि पिछले 70 सालों में सऊदी अरब को खड़ा करने में भारत की भी अहम हिस्सेदारी रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे आतंकवाद का पोषण करने वाले देश के साथ इस तरह के समझौते के लिए क्यों राजी हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सऊदी परमाणु शक्ति संपन्न भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता महसूस करने लगा है। सच तो यह है कि पिछले दिनों इजरायल द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर किए मिसाइल हमलों ने खाड़ी देशों के भीतर इस कदर भय उत्पन्न कर दिया है कि उनका वाशिंगटन पर भरोसा डगमगा गया है।

माना जा रहा है कि सऊदी सीधे तौर पर भारत पर हमला नहीं करेगा लेकिन जिस तरह से यूरोप के देश यूक्रेन को सैन्य मदद कर रहे हैं, उसी तरह सऊदी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य मदद दे सकता है। सऊदी अरब की सेना भले ही छोटी हो लेकिन उसके जखीरे में अमेरिका, चीन और रूस से खरीद किए हुए अत्याधुनिक हथियार हैं। अब पाकिस्तान ने सऊदी के साथ पैक्ट कर भारत-अमेरिका सहित मिडिल ईस्ट को बड़ा संकेत दे दिया है। निसंदेह समझौते के बाद पाकिस्तान की ताकत और अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत को स्ट्रेटेजी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को गंभीरता से लेना होगा और बदलती भू-सामरिक स्थिति को साधने के लिए भारत को अपनी सैन्य क्षमता और ज्यादा बढ़ानी होगी।

अंतरिम इंसाफ

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> हिंदू सबसे प्राचीन धर्म है, जबकि ईसाई धर्म और इस्लाम के अनुयायी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। हम भले ही खुद को धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु मानते हों, लेकिन दुनिया भारत को यहां के कानूनों, सरकारी कार्यों और लोगों के सामाजिक व्यवहार के चश्मे से देखेगी। वक्फ (संशोधन) अधिनियम के पारित होने से दुनिया की नजर में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जब संसद में पारित अधिनियम के किसी एक प्रावधान को रद्द कर देता है, तो यह कम से कम सरकार और सांसदों के लिए एक *नसीहत* की तरह होता है। जब किसी विधेयक का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि उसके प्रावधान संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी सरकार संसद में उसे पारित करा लेती है और अंततः उसे रद्द कर दिया जाता है, तो यह सरकार की *मंशा पर सवाल* उठाता है। इससे भी बदतर स्थिति पर गौर कीजिए : जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है और उसका विरोध होता है, तो उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाता है; समिति के कई सदस्य असहमति पत्र लिखकर अन्य आधारों के साथ यह तर्क देते हैं कि संसद ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए सक्षम नहीं है; फिर भी सरकार सभी आपत्तियों को दरकिनार कर विधेयक पारित कर देती है; और बाद में न्यायालय द्वारा उस अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया जाता है या उन पर रोक लगा दी जाती है। यह सरकार के लिए *सबसे बड़ी शर्मिंदगी* और विधि मंत्रालय पर गंभीर सवाल है।

संविधान से ऊपर नहीं

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की यही कहानी है। 15 सितंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर *रोक* लगा दी। फिर भी सरकार ने साहस दिखाया और खुद को बधाई दी कि न्यायालय ने मुसलिम पर्सनल ला के एक अभिन्न अंग में 'सुधार' के उसके प्रयासों का समर्थन किया है।

कृपया मेरे स्तंभ 'मुसलमानों के प्रति दुर्भावना' (जनसत्ता, 6 अप्रैल, 2025) पर गौर करें। मैंने संसद में उठाए गए कई सवालों का जिक्र किया था। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ विधेयक के प्रावधानों का हठपूर्वक बचाव किया गया। शुक्र है, अब सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे सवालों के अंतरिम जवाब दे दिए हैं :

1. इस अधिनियम के तहत वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसने *कम से कम पांच वर्षों* तक इस्लाम का पालन किया है। हमने पूछा कि कोई व्यक्ति यह कैसे 'प्रदर्शित' कर सकता है कि वह इस्लाम का पालन कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने धारा-3 के खंड (आर) के एक भाग पर तब तक *रोक* लगा दी है, जब तक कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र विकसित करने के वास्ते नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं। (किसी अन्य धर्म के व्यक्तिगत कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।)

2. यदि किसी वक्फ को समर्पित संपत्ति पर 'सरकारी' संपत्ति होने का दावा किया जाता है, तो इस प्रश्न का निर्धारण सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा; जब तक संबंधित अधिकारी यह सब निर्धारित नहीं कर लेता, तब तक संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा; और यदि वह निर्धारित करता है कि यह 'सरकारी' संपत्ति है, तो उसे राजस्व अभिलेखों में सुधार करना होगा। हमने पूछा कि क्या यह सरकार का अपने ही मामले में न्यायाधीश बनने जैसे मामला नहीं होगा? सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 3सी की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रावधानों पर *रोक* लगा दी।

3. राजस्व अभिलेखों में 'सुधार' के बाद वक्फ उस संपत्ति पर अपना अधिकार खो देगा। हमने पूछा कि क्या यह कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से वक्फ संपत्ति का विनियोग (वास्तव में जब्त करना) नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक न्यायिक अपीलीय न्यायाधिकरण और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर *अंतिम* निर्णय नहीं किया जाता, तब तक अभिलेखों में *सुधार नहीं* किया जाएगा तथा वक्फ को संपत्ति से *बेदखल नहीं* किया जाएगा, और किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जाएगा।

4. संशोधन अधिनियम में- मेरे विचार से शरारतपूर्ण ढंग से- यह प्रावधान किया गया था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुसलिमों की नियुक्ति की जा सकती है, और यहां तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी। हमने पूछा कि क्या अन्य धर्मों की संस्थाओं को संचालित करने वाले कानूनों में भी इसी तरह के प्रावधान शामिल किए जाएंगे? क्या हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं में मुसलमानों या ईसाइयों की नियुक्ति की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आपत्तिजनक प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई, बल्कि अंतरिम आदेश को 'केंद्रीय वक्फ परिषद के बाईस सदस्यों में से अधिकतम चार गैर-मुसलिम' और 'राज्य वक्फ बोर्ड के ग्यारह सदस्यों में से अधिकतम तीन गैर-मुसलिम होने', तक सीमित कर दिया, और साथ ही निर्देश दिया कि 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक मुसलमान की नियुक्ति का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए'।

विनम्रता का अभाव

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर समग्र रूप से या कम से कम इसके प्रमुख प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की अर्जी पर तीन दिन तक बहस सुनी। न्यायालय द्वारा स्थगन अर्जी पर तीन दिन तक सुनवाई करना असामान्य था। जब मामला अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध होगा, तब आगे की दलीलें सुनी जाएंगी। इस बीच, सरकार के स्वभाव को देखते हुए, ऐसा लगता है कि वह अपने घावों को सहलाएगी और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए नई योजना बनाएगी, ताकि अपने हिंदुत्व के एजंडे को आगे बढ़ा सके।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम में दुर्भावना साफ दिखाई देती है। यदि सरकार संविधान के अनुच्छेद-26 का ईमानदारी से पालन करे, तो:

'प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को यह अधिकार होगा -

(क) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का;

(ख) धार्मिक कार्यों में अपने मामलों का खुद प्रबंधन करने का;

(ग) ...; और

(घ) .. ।'

देश के बहु-जातीय और बहु-धार्मिक स्वरूप को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने में वास्तव में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति- विशेषकर हिंदुओं को- वक्फ (संशोधन) अधिनियम के *खिलाफ* खड़ा होना चाहिए।

भारत की प्रतिष्ठा कम हुई

वर्ष 2025 के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार, भारत की आबादी में मुसलिम समुदाय की संख्या 20.2 करोड़ और ईसाई समुदाय की संख्या 3.2 करोड़ है। हिंदू सबसे प्राचीन धर्म है, जबकि ईसाई धर्म और इस्लाम के अनुयायी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। हम भले ही खुद को धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु मानते हों, लेकिन दुनिया भारत को यहां के कानूनों, सरकारी कार्यों और लोगों के सामाजिक व्यवहार के चश्मे से देखेगी। वक्फ (संशोधन) अधिनियम के पारित होने से दुनिया की नजर में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है।

न्याय की गति

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> हिंदू-मुसलिम दंगों के बाद अगर सरकारें नहीं चाहती हैं कि उनका हाथ भी दंगों में पाया जाए तो जांच समिति का गठन किया जाता है जो वर्षों लगाती है अपनी रपट पेश करने में। तब तक लोग भूल जाते हैं दंगों का कारण। जाहिर है कि रपट का महत्त्व समाप्त हो चुका होता है तब तक। लेकिन दिल्ली वाले दंगों के बाद रपट आने से पहले ही उमर खालिद और उनके कुछ नौजवान साथियों को जेल में बंद कर दिया गया था।

पिछले सप्ताह 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक खबर ने साबित किया कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा, जिनका उन दंगों से कोई वास्ता नहीं था। कई लोगों का मानना है कि यही कारण है कि उमर खालिद को पांच वर्ष जेल में रखने के बाद भी उन पर मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। जब कोई मुकदमा बनाने लायक ठोस सबूत ही न हो, तो अक्सर मामला इस तरह लटकाया जाता है और इसको कहा जाता है कि सजा देने की प्रक्रिया ही सजा बन जाती है।

उमर खालिद के साथ लगता है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनको बार-बार जमानत नहीं दी जाती है, इसलिए कि सरकार की तरफ से अदालत को बताया जाता है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया है अभी तक कि वे आरोप क्या हैं और उनका आधार क्या है। जिन लोगों के बयानों पर इस पूर्व विद्यार्थी नेता के खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं, उनके नाम गोपनीय रखे गए हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' की खबर के मुताबिक, दिल्ली दंगों के बाद जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनमें कई ऐसे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने बेबुनियाद केस दर्ज किए हैं। पांच में से एक मामले ऐसे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। ऊपर से यह भी पाया गया है कि जिन छियानबे लोगों को बरी किया है अदालतों ने, उनमें तिरानबे ऐसे हैं, जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वैसे भी कई लोगों को शुरू से शक था कि उमर खालिद के खिलाफ पुलिस के इल्ज़ाम गलत थे, लेकिन अब शक यकीन में बदलता जा रहा है। जब आतंकवाद जैसे आरोप लगाते वक्त इस तरह की गलती कर सकती है पुलिस, तो गलती बहुत गंभीर होती है।

तीन दशकों बाद हुए थे दिल्ली में दंगे, जिनमें तिरपन लोग मारे गए थे। इनमें से छत्तीस मुसलिम थे और पंद्रह हिंदू, लेकिन गिरफ्तार ज्यादातर मुसलिम ही किए गए थे। मैं दिल्ली में थी उन दिनों, इसलिए कह सकती हूं कि दंगे शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के भड़काऊ भाषणों के बाद, लेकिन पकड़े गए ज्यादातर मुसलिम। उस समय मेरे कुछ मुसलिम दोस्तों ने मजाक करते हुए कहा था कि कितना अजीब है कि मुसलमानों पर दोष लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने मकान, दुकानें और मस्जिद खुद जलाए थे।

याद कीजिए कि ये दंगे हुए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे और उनका खूब शान से स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए शुरू से मुझे शंका थी कि पुलिसवालों ने जल्दबाजी में लोगों पर आरोप लगाए दंगाई होने के। शायद इसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी में मुसलिम लोगों को पकड़कर उन पर दंगाई होने के आरोप लगाए थे। जल्दबाजी में उमर खालिद और उनके कुछ साथियों को भी पकड़ा गया और आरोप लगाया गया दंगों का 'मास्टरमाइंड' होने का।

किसी ने कभी दंगा शुरू होते हुए देखा हो तो अच्छी तरह जानता है कि दंगों के अक्सर कोई पर्दे के पीछे छिपे हुए संचालक नहीं होते हैं। जो भी होता है, वह सबके सामने होता है, लेकिन समस्या अपने देश में यह है कि जब इन दंगों में शामिल दिखते हैं आला राजनेता या उनकी चापलूसी करने वाले, तो उनको पुलिस हाथ तक नहीं लगाती है। पत्रकारिता में मुझे कोई पचास साल हुए हैं। इस लंबे सफर के दौरान मैंने कई दंगे देखे हैं अपनी आंखों के सामने शुरू होते हुए। दिल्ली में सिखों का जब जनसंहार हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो संचालक थे कांग्रेस पार्टी के आला नेता, जिन्होंने टीवी पर आकर 'खून का बदला खून' जैसे नारे लगाए थे हत्या के अगले दिन। इन नारों में संदेश था कि बदला लिया जाएगा। उसी रात अपने मोहल्ले में मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के झुंड घूमते देखे, जो आक्रामक नारे लगा रहे थे।

यानी उस जनसंहार के निर्देशक कौन थे, सब जानते थे, लेकिन उनको दंडित आज तक नहीं किया गया है, बावजूद इसके कि कई आला जांच समितियां बिठाई गई हैं, जिनके सामने गवाही दी गई थी, नाम लिए गए थे। दिल्ली के दंगों के पीछे भी कई राजनेता शामिल थे। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन जगहों पर पहुंचकर धमकी दे रहे थे मुसलिम महिलाओं को, जो कई हफ्तों से धरने पर बैठी थीं नागरिकता कानून संशोधन विधेयक या सीएए के खिलाफ। वहां भी लोग कभी गिरफ्तार नहीं हुए। उनके बदले मुसलमानों को मुसलिम बहुल रिहाइशी इलाकों से पकड़-पकड़ कर जेल में डाला गया।

हिंदू-मुसलिम दंगों के बाद अगर सरकारें नहीं चाहती हैं कि उनका हाथ भी दंगों में पाया जाए तो जांच समिति का गठन किया जाता है जो वर्षों लगाती है अपनी रपट पेश करने में। तब तक लोग भूल जाते हैं दंगों का कारण। जाहिर है कि रपट का महत्त्व समाप्त हो चुका होता है तब तक। लेकिन दिल्ली वाले दंगों के बाद रपट आने से पहले ही उमर खालिद और उनके कुछ नौजवान साथियों को जेल में बंद कर दिया गया था। वास्तव में दोषी थे ये लोग, तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन क्या उनको पांच साल तक ऐसे बंद रखना ठीक है जब उन पर मुकदमा ही नहीं शुरू हुआ है?

अनुमान लगाया जाता है कि हमारी जेलों में बंद लोगों में से पचहत्तर फीसद से ज़्यादा कैदी ऐसे हैं, जिन पर कोई मुकदमा चलाया ही नहीं गया है। यानी 5,73,220 कैदियों में से 4,34,302 ऐसे हैं, जिनको 'अंडरट्रायल' कहा जाता है। यही मुख्य कारण है कि अपने देश के आम आदमी को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं हो पाता है। खतरे की घंटी कब बजेगी हमारे शासकों के कानों में?

उधार की बौद्धिकता

संदर्भ

राकेश सिन्हा

> अतिशय भौतिकता कभी भी सामाजिक-सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा नहीं दे सकती है। वह अंतत: समाज को व्यक्ति केंद्रित बनाती है। ऐसे में हल्की बातें, विलासितापूर्ण गतिविधियां और पहचान मूलक सतही विचार लोगों को पसंद आने लगते हैं। जबकि मानसिक उन्नति के लिए गंभीर साहित्य, विचारपूर्ण समाजशास्त्र, सारगर्भित कला-कृतियां और प्रकृति प्रेम आवश्यक होता है। भौतिकवाद इन सबको रोकता है। इसलिए उपलब्धता के बीच में मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।

अमेरिका में राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की दिन दहाड़े हत्या ने एक साथ कई सवालों को जन्म दिया है। इनमें सबसे प्रमुख सवाल है राजनीतिक विमर्श में बढ़ती असहिष्णुता। इसका सीधा तात्पर्य है- प्रतिकूलता और शत्रुता के बीच का अंतर समाप्त हो जाना। पूरी दुनिया में यह प्रवृत्ति अमरबेल की तरह बढ़ती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अतिरेक युग में प्रवेश कर चुके हैं। पश्चिम की परंपरा ही चित या पट की रही है। आक्सफोर्ड, कैंब्रिज और हावर्ड विश्वविद्यालयों में गैर पश्चिम दुनिया को देखने एवं परखने की कोशिशें तो होती रही हैं, पर वे दूसरों से जो अपेक्षा करते हैं, उसे अपनी ही सभ्यता में लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसी को कहते हैं- चिराग तले अंधेरा। उन्होंने बौद्धिकता की केंद्रीकृत धारा को आगे बढ़ाया। यह स्वाभाविक तौर पर एकरूपतावादी हो जाता है। भारत की परंपरा में बौद्धिकता केंद्रीकृत नहीं रही है। तभी तो आध्यात्मिक ग्रंथों के भी अनेक रूप और कभी-कभी तो परस्पर विरोधी संस्करण रहे हैं। रामायण इसका एक उदाहरण है। इसके लगभग 300 अलग-अलग व्याख्या के संस्करण हैं। यह विकेंद्रीकृत बौद्धिकता का परिणाम है ।

पश्चिम जगत में बहुलता श्रृंगार के रूप में है। थोड़ा भी असंतुलन उनके लिए असहनीय हो जाता है। भौतिक समृद्धि से वे अपनी कमियों को ढकते रहे हैं। वहां नस्लवाद और रंगभेद, दोनों ही खूब प्रचलित हैं। ऐसा नहीं होता तो सेसिल रोड्स जो घोर नस्लवादी थे, उनकी मूर्ति तो दक्षिण अफ्रीका में तोड़ दी गई, पर समानता का डंका पीटने वाले आक्सफोर्ड के एक कालेज में उनकी मूर्ति सम्मान के साथ स्थापित है। अमेरिका में 75 फीसद अश्वेतों के साथ भेदभाव होता है। अमेरिका मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) के समानता मूलक दर्शन को दुनिया के सामने जरूर परोसता है, लेकिन वे जिन अश्वेतों के हक के लिए लड़ते रहे, उन्हें सम्मान एवं बराबर अवसर नहीं मिल पा रहा है।

अतिशय भौतिकता कभी भी सामाजिक-सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा नहीं दे सकती है। वह अंततः समाज को व्यक्ति केंद्रित बनाती है। ऐसे में हल्की बातें, विलासितापूर्ण गतिविधियां और पहचान मूलक सतही विचार लोगों को पसंद आने लगते हैं। जबकि मानसिक उन्नति के लिए गंभीर साहित्य, विचारपूर्ण समाजशास्त्र, सारगर्भित कला-कृतियां और प्रकृति प्रेम आवश्यक होता है। भौतिकवाद इन सबको रोकता है। इसलिए उपलब्धता के बीच में मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में चार फीसद वयस्क नींद की गोली का इस्तेमाल करते हैं और चौबीस फीसद मानसिक रोग से ग्रस्त हैं।

भौतिक विकास का यदि सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं से तालमेल टूट जाता है, तब परिणाम नकारात्मक होने लगता है। पैसा, पद एवं प्रतिष्ठा की होड़ छद्म संस्कृति पैदा करती है। इसके परिणामस्वरूप परंपरागत एवं प्रगतिशील सामाजिक संस्थाएं, जो वैकल्पिक चेतना का सृजन करती हैं, वे भी अप्रासंगिक होने लगती हैं। अमेरिका में परिवार संस्था का पतन इसी का परिणाम है। वहां पति-पत्नी के बीच संबंध विच्छेद की दर काफी ज्यादा है। बच्चों के लालन पालन में कठिनाइयां इसका एक पक्ष है। इससे कही अधिक चिंताजनक यह है कि वहां बड़ी संख्या में बच्चे सामाजिकता के बोध से वंचित रह जाते हैं। सफल बनने की होड़ में वे सार्थक मनुष्य की परिकल्पना खो देते हैं। अमेरिका में जीवन भर अरबों रुपए कमाने वाले लोग अपने अंतिम पड़ाव के दौरान दान लेने वालों की पात्रता ढूंढ़ते हैं। मनुष्य को मशीन बनाकर काम करवाने के बाद वे दानवीर कर्ण बनना चाहते हैं। परिवार के बिखराव की कहानी लिखना, दानकर्ता बनकर तात्कालिक शोहरत पाना या बैंकों में ढेर सारा पैसा छोड़कर दुनिया से अलविदा हो जाना, भौतिकता की अंधेरी गली के यात्रियों का यही हस्र होता है।

एक रपट के मुताबिक, आज अमेरिका में प्रत्येक आधे घंटे में एक हत्या और प्रत्येक चार मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है। यह सामाजिक-मानसिक असंतुलन का परिणाम है। संविधान चाहे जितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उसकी श्रेष्ठता तो सामुदायिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन से सृजित मूल्यों पर निर्भर करती है। यह सृजन जितना कमजोर पड़ेगा, देश और राज्य उसी अनुपात में यांत्रिक बनता जाएगा। आज दुनिया भर में देश या राज्य जीवंत कम, यांत्रिक अधिक हो गए हैं। अमेरिका में परिवार और समुदाय आदि परंपरागत संस्थाओं को 'नाईट क्लबों' ने विस्थापित कर दिया है। वहां कथित स्वतंत्रता के चरम के बीच समय व्यतीत होता है। मन और शरीर जब आकांक्षाओं में बेलगाम हो जाता है, तो उसे ययाति के नाम से संबोधित करते हैं। ययाति एक राजा था, जो बेहद आकांक्षी था। मगर, अंततः उसे भी संतुष्टि नहीं मिली। रोमन साम्राज्य बौद्धिकता के बल पर बढ़ा, लेकिन जब भौतिकता ही समाज का सम्राट बन गया, तब समाज में विरोधाभास, अंतर्विरोध, असंतुलन और बिखराव बढ़ने लगा। उसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि, वैचारिक पुरुषार्थ को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था ।

अमेरिका में हजारों प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन वहां नैतिक और सामाजिक साक्षरता का सूचकांक संतोषजनक नहीं है। प्रबुद्ध संस्थाएं भी बड़ी संख्या में हैं, वे मनुष्य को संवैधानिक तो बना पा रही हैं, लेकिन बुनियादी प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अमेरिका बाहर की दुनिया से बौद्धिकता उधार लेकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में कंप्यूटर विज्ञान में साठ फीसद गैर अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, तो इंजीनियरिंग में यह संख्या 57 फीसद और जीव एवं कृषि विज्ञान में 50 फीसद है। असल में अमेरिका बौद्धिक रिक्तता का शिकार है।

बयानवीरों का दौर

बाखबर

सुधीश पचौरी

> हर दिन राजनीतिक भाषा में ऐसी कड़वाहट बढ़ती जाती है। इधर से 'गोली' चलती है तो उधर से 'गोला'..! ऐसे में सभी बयानवीरों की बन आती है। वे कुछ का कुछ बोलकर दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ऐसे सभी बयान शाम की टीवी बहसों में 'जान' डालते हैं।

सप्ताह की शुरुआत एक नए 'राग' से हुई। विपक्ष के बड़े दल की एक राज्य इकाई ने एक दिन एक ऐसा 'एआइ निर्मित' वीडियो जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां उन्हें नसीहत देती दिखाई देती थीं। एक सत्ता प्रवक्ता कहिन कि यह एक दिवंगत मां का अपमान है, उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है और घोर निंदनीय है। बहसों में कई विपक्षी प्रवक्ता पहले इसे 'निंदनीय' कहते, फिर तुरंत कहने लगते कि प्रधानमंत्री ने भी अतीत में विपक्ष के नेताओं का अपमान किया है... इस-इस-इस को ये-ये कहा है.. ये कहा... ये कहा..! एक ने तो यह कहा कि वे अपने बेटे को नसीहत दे रही हैं..! देर तक विपक्ष और सत्ता पक्ष में 'तू तू मैं मैं' जमी रही।

फिर एक दिन पाकिस्तान के एक मंत्री ने 'भारत-पाक युद्ध' के संदर्भ में भारत के रुख को यह कह कर पुष्ट किया कि भारत ने शुरू में ही 'किसी तीसरे के हस्तक्षेप' के लिए इनकार कर दिया था। इसके बाद कई चर्चक भारत सरकार की विदेशी नीति के बल्ले-बल्ले करते नजर आए। वे लोग सन्नाटे में रहे जो कल तक कहते थे कि ट्रंप ने उनतीस बार कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया... भारत इसका सीधा जवाब क्यों नहीं देता..!

इसी बीच वक्फ कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने 'पक्ष' और 'विपक्ष' दोनों को ही 'कुछ खुश, कुछ नाखुश' कर इस 'गरम मौसम' को कुछ ठंडा किया... सत्तापक्ष ने कहा कि हम जीते... विपक्ष ने कहा कि हम जीते..! यानी सब जीते... कानून जीता, जनतंत्र जीता!

इस बीच दुबई में खेलती भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तान को हरा देने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का पाक के कप्तान से हाथ न मिलाने की घटना ने बड़ी खबर बनाई। जवाब में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद आफरीदी द्वारा भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने को लेकर अपनी नाराजगी दिखाते हुए भारत के विपक्ष के नेता की राजनीति को 'समावेशी' बताकर यहां की राजनीति पर कटाक्ष किया तो सत्ता प्रवक्ताओं ने आफरीदी की जगह विपक्ष के नेता को ही अधिक निशाने पर लिया।

फिर भाजपा ने प्रधानमंत्री का पचहत्तरवां जन्मदिन मनाया और कई चैनलों ने उनके जीवन पर 'वृत्त चित्र' दिखाए। यों पक्ष और विपक्ष के सभी नामचीन नेताओं ने भी उनको बधाइयां दीं। आमिर खान और शाहरुख खान समेत बहुत से कलाकारों ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की, लेकिन कुछ ने उन्हें 'आत्मप्रचारवादी' कहा।

फिर एक दिन 'वोट चोरी' की कक्षा में देर तक समझाया जाता रहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में इतने वोट हटाए और इतने जोड़े गए। लंबे इंतजार के बाद भी कथित 'हाइड्रोजन बम' इस दिन न आया। 'वोट चोरी' के आरोपों का चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया कि जिन वोटों को हटाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आयोग मुकदमा कर चुका है। फिर एक चैनल पर एक पुराने नामी चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक विपक्षी नेता द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप आधारहीन हैं। बिना पूरी प्रक्रिया के वोट नहीं हटाया जा सकता।

इसके बाद शुरू हुआ 'जेन-जी पीढ़ी' का आह्वान कि जैसा आंदोलन नेपाल में हुआ, वैसा यहां भी हो, जल्दी हो, जनतंत्र बचाएं, संविधान बचाएं... हमें बचाएं..!

विपक्षी नेता जी इन दिनों जब भी आते हैं, कुछ न कुछ चौंकाने वाले एलान करते आते हैं। जैसे उस दिन कहे थे कि मैं 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाला हूं। मगर देर तक नहीं आया। यानी 'रहस्य' बना रहे, क्योंकि 'रहस्य' बिकता है। हालांकि लोग उम्मीद करते रहे कि किसी बड़े रहस्य पर से पर्दा उठेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि नेता जी के मुताबिक आने वाले दिनों में वे कुछ ऐसा कर सकते हैं।

अगले दिन फिर सर जी ने कहा कि जेन-जी आएंगे... संविधान बचाएंगे... मैं आपके साथ हूं..! तुरंत एक स्वघोषित 'राष्ट्रवादी' ने 'जेन-जी' के इस आह्वान को लेकर आक्रमण कर दिया कि अगर 'जेन-जी' आई तो सबसे पहले वह इनका घर जलाएगी... उनका घर जलाएगी... हमारे राष्ट्रवादी उसे दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे..!

हर दिन राजनीतिक भाषा में ऐसी कड़वाहट बढ़ती जाती है। इधर से 'गोली' चलती है तो उधर से 'गोला'..! ऐसे में सभी बयानवीरों की बन आती है। वे कुछ का कुछ बोलकर दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ऐसे सभी बयान शाम की टीवी बहसों में जान डालते हैं। पक्ष और विपक्ष देर तक भिड़े रहते हैं और अंत में हर ऐसा वाक्‌युद्ध अगले वाक्‌युद्ध के बीज बोकर विदा लेता है। ऐसी सभी बहसें बस एक ही तरह का गाना गाती हैं, जिसका मतलब सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा तीखी और चोट पहुंचाने वाली भाषा में हमला करो। यह सिरा कहां जाएगा, यह किसी को नहीं पता।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ट्रंप का आत्मघाती फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एच-1 बी वीजा की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि का फैसला भारतीय आइटी कंपनियों के साथ अमेरिकी हितों को भी चोट पहुंचाने वाला है। उनके इस फैसले से भारतीय आइटी कंपनियों के साथ अमेरिकी कंपनियों पर भी बुरा असर पड़ेगा और इनमें आइटी सेक्टर से इतर क्षेत्र की कंपनियां भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि उनके फैसले की आलोचना अनेक अमेरिकी ही कर रहे हैं। यदि ट्रंप यह सोच रहे हैं कि एच-1बी वीजा धारकों की फीस एक हजार डालर से एक लाख डालर सालाना करने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियां अमेरिका के युवाओं को नौकरी देने के लिए बाध्य हो जाएंगी तो यह उनकी भूल है, क्योंकि इन कंपनियों को जैसे और जितने सक्षम युवा पेशेवर चाहिए, वे अमेरिका में हैं ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति यह भी भूल रहे हैं कि अमेरिका के आर्थिक विकास में अप्रवासियों का बहुत योगदान है और यह केवल पेशेवर लोगों का ही नहीं, बल्कि कामगारों का भी है। यह ठीक है कि इन कामगारों में अच्छी-खासी संख्या अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे लोगों की है, लेकिन यदि ऐसे सभी लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा तो अमेरिका में काम-धंधा ठप होने की नौबत आ जाएगी। निःसंदेह अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले ने भारतीय आइटी कंपनियों के समक्ष फौरी तौर पर परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन वे इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगी। यदि उनके साथ अमेरिकी कंपनियां भी अपना कारोबार बाहर ले जाती हैं या आउटसोर्स करती हैं तो इससे कुल मिलाकर अमेरिका को ही नुकसान होगा। चूंकि एच-1 बी वीजा धारकों के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय हैं, इसलिए अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को झटका लगेगा, लेकिन भारतीय कारोबारी उनके लिए देश में ही काम के अवसर पैदा कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। उन्हें ट्रंप के फैसले को आपदा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारतीय कंपनियों को देश में ही अपना कारोबार बढ़ाने के जतन इसलिए भी करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप कुछ और ऐसे कदम उठा सकते हैं, जिनके निशाने पर भारत हो। उन्होंने भले ही टैरिफ के मामले में लचीला रवैया अपनाते हुए भारत से शीघ्र व्यापार समझौता होने की संभावना जताई हो, लेकिन वे भारतीय हितों के विपरीत काम करते दिख रहे हैं। वे केवल यही दबाव नहीं बना रहे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, बल्कि उन्होंने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम किया है। ट्रंप अपने फैसलों को इस रूप में रेखांकित कर रहे हैं कि उनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे, लेकिन आठ माह का उनका कार्यकाल उनकी नाकामी ही बयान कर रहा है।

बाढ़ पीड़ितों की चिंता

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी अब कम हो रहा है, पर समस्याएं भी हैं। जलजमाव वाले क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल, मवेशियों के चारे, चिकित्सा आदि की जरूरत है। प्रशासन व्यवस्था कर भी रहा है, पर यह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा कम हो सके। पश्चिम चंपारण में गंडक का जलस्तर कम हुआ तो योगापट्टी प्रखंड में कटाव शुरू हो गया है। लोग अपने घरों को उजाड़कर सामान यत्र-तत्र ले जा रहे हैं। बाढ़ और कटाव से विस्थापन राज्य की एक बड़ी समस्या रही है। गांव के गांव उजड़ जाते हैं। जमीन नदी में चली जाती है। जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके आवास आदि का वैकल्पिक प्रबंध तुरंत किया जाना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। यह बहुत ही संकट की घड़ी होती है। ऐसे स्थलों को चिह्नित करते हुए विस्थापन का शिकार हुए लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, वैशाली आदि के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लोग यत्र-तत्र रह रहे हैं। राजधानी पटना में भी कई परिवारों ने सड़क किनारे अस्थायी आवास बना रखा है। अभी पर्व-त्योहार का समय है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। उन्हें राशन-पानी, चिकित्सा सुविधा आदि में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसकी चिंता की जानी चाहिए। सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए। कई जगहों पर लोग कर भी रहे हैं, यह सराहनीय है।

प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाढ़ पीड़ितों तक हर हाल में जरूरी सुविधाएं पहुंचे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सैम पित्रोदा का ताजा बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा?

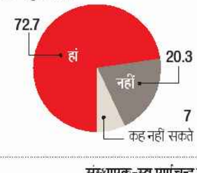

आज का सवाल
क्या ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा पर शुल्क बढ़ाना भारत के लिए आपदा के साथ एक अवसर भी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

लोकतंत्र के खतरे में होने का हौवा

संजय गुप्त

राहुल गांधी आरोप तो लगा देते हैं, पर यह नहीं बताते कि वोट चोरी हो रही है तो भाजपा झारखंड में क्यों हार गई या लोकसभा में बहुमत से पीछे क्यों रह गई?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मामला उठाकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इस बार उन्होंने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट से कांग्रेस के 6,018 वोट काटे जाने का आरोप लगाया और एक प्रेस कांफ्रेंस में प्रजेंटेशन देकर यह समझाया कि किस तरह मोबाइल फोन के जरिये कांग्रेसी वोटरों के वोट काटे गए। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह वोट चोरी के एक मामले को सामने रखा था और उसे एटम बम की संज्ञा दी थी। वे वोट चोरी के एक और मामले को सामने लाएंगे और उसे हाइड्रोजन बम बताएंगे। राहुल का चुनाव आयोग पर निशाना नया नहीं है। वे एक अर्से से यही कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी का मामला उछाल चुके हैं और बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन को भी वोटों की चोरी बता चुके हैं। पहले वे चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की हवा निकल गई तो वोट चोरी के अपने आरोपों को एक अभियान बनाने में जुट गए। वे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उनकी मानें तो मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोप को धार देने के लिए कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट से कांग्रेसी वोटरों के वोट काटे जाने का जो मामला सामने रखा, उससे यह प्रतीति हुई कि 6,018 वोटरों के नाम सचमुच हटा दिए गए, लेकिन कुल 24 वोट काटे गए और वे भी उनके, जिनके कटने चाहिए थे। अन्य वोट काटने की नाकाम कोशिश हुई थी। इस मामले में खुद चुनाव आयोग ने एफआइआर दर्ज कराई और इसकी जांच कर्नाटक सीआइडी कर रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग कर्नाटक सीआइडी को वोट काटे जाने के मामले में बार-बार मांगे जाने के बाद भी वांछित जानकारी नहीं दे रहा है, पर चुनाव आयोग के अनुसार 2023 के इस मामले में जो जानकारी मांगी गई थी, वह सीआइडी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस हिसाब से गेंद सीआइडी के पाले में है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन के जरिये उस तरह वोट काटे या जोड़े नहीं जा सकते, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं। किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने और जोड़ने की एक तय प्रक्रिया होती है और उसमें चुनाव कर्मचारी शामिल होते हैं। वे अपने स्तर पर छानबीन कर किसी का नाम जोड़ते या हटाते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार गड़बड़ी भी होती है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार बीएलओ और अन्य चुनाव अधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार के तहत काम करते हैं। यदि किसी का नाम हटाने या जोड़ने में कोई खामी होती है तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी यही साबित करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, ताकि चुनाव आयोग को बदनाम कर सकें और यह माहौल बना सकें कि भाजपा छल-छद्म से चुनाव जीतती है।

भारत में 96 करोड़ वोटर हैं और इतने बड़े देश में कहीं पर भी मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है और होती भी है। राहुल गड़बड़ी के जो भी उदाहरण दे रहे हैं, वे कुछ सौ या हजार वोटों के हैं। यह सही है कि मतदाता सूची सही से तैयार होनी चाहिए, पर क्या कांग्रेस इसकी गारंटी ले सकती है कि उसके केंद्र की सत्ता में रहते समय चुनाव आयोग की ओर से तैयार मतदाता सूचियां दुरुस्त होती थीं? कांग्रेस इसलिए खिसियाई है, क्योंकि उसके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है। उसने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद यह माना था कि अब आगामी सभी चुनावों में उसकी जीत होगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो हताशा में उसने अपनी हार का ठीकरा भाजपा और चुनाव आयोग पर फोड़ना शुरू कर दिया। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि इससे उसका गिरता वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा या फिर क्षेत्रीय दलों पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रीति-नीति के कारण। राहुल यह समझने को तैयार नहीं कि भाजपा क्यों जीतती है? जहां भाजपा की जीत में प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावी नेता की छवि भी कारगर साबित होती है, वहीं राहुल के लिए अपने दम पर कांग्रेस को चुनाव जिताना कठिन हो रहा है।

राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी के कारण लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन वे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाकर खुद ही लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वे संविधान की दुहाई दे रहे हैं, पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को नीचा दिखा रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में राजनीतिक दलों, नौकरशाही, संवैधानिक संस्थाओं और अदालतों की एक बड़ी भूमिका होती है, पर राहुल तो बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं और संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आयोग की साख नष्ट करने में तुले हैं। लोकतंत्र कायदे-कानून से चलता है। किसी की भी मनमानी लोकतंत्र को कमजोर करती है। राहुल मनमानी ही कर रहे हैं। वे यह चाह रहे हैं कि वोट चोरी पर उनकी ओर से जो कहा जा रहा है, उसे सत्य मान लिया जाए। वे अपने कथित पुख्ता प्रमाणों के साथ अदालत भी नहीं जा रहे हैं। लोकतंत्र तब पटरी से उतरता है, जब उसकी संस्थाओं पर संकीर्ण स्वार्थों के लिए हमला बोला जाता है या फिर उन पर अनुचित दबाव बनाकर उन्हें कमजोर किया जाता है। आपातकाल में कांग्रेस ने यही किया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संस्था के कामकाज पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यह काम भी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। राहुल उलटे-सीधे आरोप लगाकर सनसनी तो फैला देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि वोट चोरी हो रही है तो भाजपा झारखंड में क्यों हारी या फिर लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे क्यों रह गई? क्या उनके रवैये को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? उन्होंने जिस तरह जेन-जी अर्थात नई पीढ़ी को वोट चोरी के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा, उससे तो यही लगता है कि वे अपने अपुष्ट आरोपों के आधार पर लोगों को बरगलाकर अराजकता फैलाना चाह रहे हैं।

अवधेश राजपूत

response@jagran.com

जब साहित्य का हुआ जेन-जी से सामना

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

साहित्य जगत में चिंता है कि समय रहते जेन-जी को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वर्षों से बनाई उसकी स्थापनाएं ढह जाएंगी

पिछले दिनों पड़ोसी देश में क्रांति हो गई। यह क्रांति पिछली क्रांतियों से थोड़ा अलग रही। इसका श्रेय 'जेन-जी' को दिया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया की नव-संतानों ने रील और वीडियो बना-बनाकर लोकतांत्रिक सरकार को ढहा दिया। 'जेन-जी' ने पहले अपने हाथ में ली हुई डिजिटल-मशाल से आग सुलगाई, फिर सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। सरकार ने भी इस आग में पर्याप्त घी डाला और जी का जंजाल बने कई जेन-जियों को मौत की नींद सुला दी। कई विचारक और विश्लेषक उस क्रांति को अपने यहां भी घसीटकर लाना चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ बदलाव से मतलब है, चाहे जैसे आए, पर हाय तुरंत इसका तोड़ भी आ गया कि अपने यहां लोकतंत्र की बुनियाद वैसी नहीं है। जरा ज्यादा ही मजबूत है। यहां लोग अपने संघर्ष सड़क के बजाय इंटरनेट मीडिया पर ही निपटा लेते हैं। उनकी क्रांति ड्राइंग रूम से उठती है और बेडरूम आते-आते थक जाती है। इस दौरान दो-चार 'मीम' जरूर बन जाते हैं। ये रीलबाज युवा सड़कों, नदियों और खाइयों में गिर-गिरकर अपनी आहुति दे रहे हैं। सरकार को इन्हें निपटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। स्वयं निपटे जा रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र सुरक्षित है।

वहां 'जेन-जी' के इस अप्रत्याशित कौतुक से अपने देश की सियासत में ज्यादा हलचल भले न हुई हो, पर साहित्यिक गलियारों में खलबली मच गई। ये नई पीढ़ी न जाने कौन-सी बला बनकर खड़ी हो जाए। बुजुर्गों को चिंता सताने लगी कि यह संक्रमण साहित्य में आ गया तो उनका क्या होगा? 'जेन-जी' कुछ और नहीं, आधुनिक हरकारे हैं। साहित्य जगत में चिंता है कि समय रहते जेन-जी को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वर्षों से बनाई उसकी स्थापनाएं ढह जाएंगी। हम स्तंभकार बेरोजगार हो जाएंगे। इसी पसोपेश में राजधानी के बड़े साहित्यकारों ने एक 'चिंतन-बैठक' आहूत कर ली। इसमें वे सभी लेखक शामिल थे, जो साहित्य के लिए चिंताजनक थे। विषय था, 'साहित्य का संक्रमण-काल।'

इस गंभीर गोष्ठी में मुख्य तीन वक्ता थे। पहले कनिष्ठ वक्ता ने बोलना शुरू किया, 'साथियों, पहली बार हम संकट में हैं। कृपया हम का मतलब साहित्य समझना। लिखना तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, अब ये जेन-जी हमारे दिखने पर भी टोका-टाकी करने लगी है। हम अपने प्रिय की ईमानदार आलोचना तक नहीं कर पा रहे हैं। यह पीढ़ी उसे प्रशंसा समझ लेती है। देखते ही देखते हमारी कारगुजारियां वायरल हो जाती हैं। इससे बड़ा संक्रमण क्या होगा भला?' उनकी बात सुनकर दूसरे वक्ता समय से पहले ही बोलने लगे, 'मित्रों, हमने यह आयोजन इसलिए नहीं किया कि हम संकट में हैं। साहित्य के बारे में नहीं कह सकता। पिछले तीस वर्षों से किसी तरह साहित्य को संक्रमित होने से बचा रखा था। आजकल 'जेन-जी' नामक नई आफत आई है। हमें कुछ नहीं तो सियासत से सबक लेना चाहिए। वहां 'जेन-जी' शांति से काम कर रही है!'

शीर्ष वक्ता बड़ी देर से कसमसा रहे थे। भोजन का समय हो चुका था, पर बीज-वक्तव्य उन्हें देना था। माइक संभालते ही वह टूट पड़े, 'मेरी साहित्य के प्रति निष्ठा असंदिग्ध है। इसका उदाहरण मेरी हवाई यात्रा है। संक्रमण को बचाने के लिए मैं कितनी जल्दी में हूं, इससे पता चलता है। मेरी कविताओं में कबीरी-धार है। वही उलीचने यहां आया हूं।' यह सुनते ही उपस्थित श्रोताओं में भगदड़ मच गई। लोगों को लगा कि बाजार में कोई नया व्यंजन आया है। उन्होंने मंच के नीचे अपनी अंजुरी लगा दी। आयोजकों के बार-बार एलान के बाद भी श्रोता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसी दृश्य को कुछ 'जेन-जियों' ने रील बनाकर वायरल कर दिया।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | भारत का स्मार्टफोन बाजार

(आंकड़े प्रतिशत में)

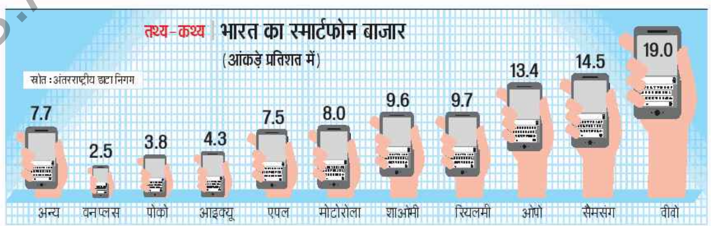

ऊर्जा

शक्ति

'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' यानी ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है, का उद्घोष कर जब आदि शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन कर अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठापना कर रहे थे, तभी एक दिन गंगा स्नान के लिए जाते हुए उन्होंने मार्ग पर दिवंगत पति को गोद में लिए एक स्त्री को देखा। जब हटने को कहा तो उसने शव की ओर संकेत किया। 'मृत देह स्वयं नहीं हट सकती' आचार्य शंकर के ऐसा कहने पर उसने कहा- एकमात्र सत्य अपने ब्रह्म से कहो, वह जरूर हटाएगा। यह सुनते ही उनका भ्रम दूर हो गया। वे उसके चरणों में गिर गए। वह अखिल ब्रह्मांड संचालिका शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा थीं, जो उन्हें अपनी सत्ता का अहसास कराने आई थीं। शक्ति की अखंड सत्ता को पहचान कर उन्होंने पंच देवोपासना में मां दुर्गा को प्रमुख स्थान दिया। शक्ति के बिना शिव भी शव के समान हैं। लोक में इसी भाव की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा, जो सभी जीवों में स्त्रीत्व की उपस्थिति का बोध कराता है।

शक्ति ही सृजन का कारण है और विनाश का भी। यही समस्त कार्य व्यवहारों की साधिका है। इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, किंतु शक्ति का अर्जन जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सदुपयोग। आज दुनिया ने अपनी मेधा शक्ति के बल पर विविध शक्तियों का अर्जन तो कर लिया है, किंतु सदुपयोग न होने से विपरीत परिणाम आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वस्तुतः शक्ति का दुरुपयोग मानव के विकृत चिंतन का परिणाम होता है। मनीषियों ने शक्ति के उपयोग के आधार पर ही सज्जन और दुर्जन को परिभाषित किया है। सज्जन की शक्तियां सदैव जगत कल्याण के लिए होती हैं, जबकि दुर्जन की परपीड़ा के लिए। इस नवरात्र मां की आराधना कर विविध शक्तियों को अर्जित करें तथा मानवता के विस्तार के लिए उनके सदुपयोग का संकल्प लें। इसी में शक्ति उपासना की सार्थकता है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

सिद्दा का जवाब

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया (सिद्दा) यूं तो कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ और राजनीतिक रूप से भारी-भरकम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लाइमलाइट तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ले जा रहे हैं। राहुल गांधी भी रेवंत रेड्डी की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, खासकर जातिगत सर्वे के बाद। ऐसे में सिद्दा ने अब बैलेट पेपर के जरिए बाजी पलटने की कोशिश की है। दरअसल उनकी सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकारी अधिकारियों की ओर से इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव में न सिर्फ गड़बड़ी की आशंका बढ़ेगी, बल्कि खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल सिद्दा की इस चाल को कांग्रेस के अंदर भी उनकी राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है।

आरजी और जेन-जी

कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दल वोट चोरी का नैरेटिव जनता के बीच खड़ा करने के प्रयास में महीनों से जुटे हैं। उसका कितना असर हुआ, यह तो बिहार चुनाव परिणाम के साथ सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस बीच नेपाल में सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरी जेन-जी से भारत की जेन-जी का कनेक्शन जोड़कर कांग्रेस के आरजी यानी राहुल गांधी ने अपने लिए फजीहत जरूर मोल ले ली। आरजी ने तराना छेड़ दिया कि यहां भी जेन-जी बदलाव के लिए खड़ी होगी, लेकिन उनके लिए यह मामला सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा हो गया। शुक्रवार को ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, जिसमें कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआइ की करारी हार हो गई। अब इंटरनेट मीडिया पर सबसे अधिक सक्रिय रहने वाली जेन-जी के सामने ही विरोधी खेमा राहुल गांधी को ट्रोल कर रहा है कि इस चुनाव में तो जेन-जी ही वोटर थी, उसने तो करारा जवाब दे दिया।

राजरंग

हाल बड़ा, दर्शन छोटे

इंतजाम तो सब किया गया था। गाना था, बजाना था, शानदार खाने और पीने के भी इंतजाम थे, लेकिन इसके बावजूद जब हाल नहीं भरा, तो सबके चेहरे लटक गए। हुआ यह कि उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने पिछले हफ्ते एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम- इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की सालाना बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की काफी प्रतिष्ठा है। बीआइएस ने इसका आयोजन भारत मंडपम में किया। बस गलती यह हो गई कि आयोजन के लिए मुख्य हाल का चयन किया गया, जो अभी तक पीएम के कार्यक्रम में ही भरता है। विदेशी मेहमानों ने समय पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन मंत्री जी के आने में देरी होने लगी। बताया गया कि हाल के भरने का इंतजार किया जा रहा है। जल्दबाजी में भीड़ का इंतजाम भी नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। कार्यक्रम हुआ, लेकिन हाल का बड़ा हिस्सा खाली ही रहा। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हाल के चयन में भी सतर्कता बरती जाए।

अभी और कौन से बम फूटेंगे

मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से फोड़े जा रहे 'बमों' को चुनाव आयोग अब तक भले ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करता आ रहा है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी हाइड्रोजन बम एवं दूसरे बमों को फोड़ने की बात की है, उससे चुनाव आयोग की चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। चुनाव आयोग वैसे भी इस सियासी बमबारी में दोहरी चुनौती झेल रहा है। पहली किसी भी छोर से किए जाने वाले हमलों का तुरंत ही तथ्यात्मक जवाब देने की है, दूसरी खुद की छवि को बचाए रखने की चुनौती भी है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इन हमलों को देखते हुए देश भर के अपने अमले को अलर्ट मोड पर रखा है।

X पोस्ट

2005 में मैं एक विश्वस्तरीय बिजनेस स्कूल खोलने के लिए भारत लौटी। कई लोगों ने मेरे इस फैसले पर, व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर, सवाल उठाए। जैसी कि उम्मीद थी, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए यहां का सफर कठिन है, लेकिन बनाने और रचने के लिए बहुत कुछ है। एच1बी वीजा की खबर से निराश या हताश न हों। भारत घर है। आइए भारतीय सपने को साकार करें।
प्रो. शमिका रवि@ShamikaRavi

भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे मोलभाव में दोनों तरफ से बहुत से पासे फेंके जाएंगे अभी। अगर प्रतिवर्ष जारी हो रहे एच1बी वीजा का तीन चौथाई भारतीयों को जाता है, तो इसके पीछे उनका कौशल है। अगर कंपनियों को उन पर भरोसा होगा तो वे यह रकम अदा करेंगी। अगर भारतीयों को इस फैसले से घाटा है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। अनुपम के. सिंह@anupamnawada

भारत विविधताओं का देश है। इन दिनों एक कतार आइफोन17 के लिए लग रही है तो दूसरी, दो बोरी खाद के लिए। प्रभाकर कुमार मिश्र@PMishra_Journo

जनपथ

'जेन-जी' को भड़का रहे बजा-बजाकर गाल,
चहें बनाना झूठ से भारत को नेपाल।
भारत को नेपाल बनाकर चाहें सत्ता,
सत्ता का अंगूर मगर इनके हित खट्टा!
पढ़ ना पाते आप युवाओं का ही मन जी,
तो राहुल के साथ खड़ा क्यों होगा 'जेन-जी'!!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 160

****

दैनिक जागरण
विचार समाज की दिशा-दशा को निर्धारित करते हैं

ट्रंप का आत्मघाती फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एच-1 बी वीजा की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि का फैसला भारतीय आइटी कंपनियों के साथ अमेरिकी हितों को भी चोट पहुंचाने वाला है। उनके इस फैसले से भारतीय आइटी कंपनियों के साथ अमेरिकी कंपनियों पर भी बुरा असर पड़ेगा और इनमें आइटी सेक्टर से इतर क्षेत्र की कंपनियां भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि उनके फैसले की आलोचना अनेक अमेरिकी ही कर रहे हैं। यदि ट्रंप यह सोच रहे हैं कि एच-1बी वीजा धारकों की फीस एक हजार डालर से एक लाख डालर सालाना करने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियां अमेरिका के युवाओं को नौकरी देने के लिए बाध्य हो जाएंगी तो यह उनकी भूल है, क्योंकि इन कंपनियों को जैसे और जितने सक्षम युवा पेशेवर चाहिए, वे अमेरिका में हैं ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति यह भी भूल रहे हैं कि अमेरिका के आर्थिक विकास में अप्रवासियों का बहुत योगदान है और यह केवल पेशेवर लोगों का ही नहीं, बल्कि कामगारों का भी है। यह ठीक है कि इन कामगारों में अच्छी-खासी संख्या अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे लोगों की है, लेकिन यदि ऐसे सभी लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा तो अमेरिका में काम-धंधा ठप होने की नौबत आ जाएगी।

निःसंदेह अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले ने भारतीय आइटी कंपनियों के समक्ष फौरी तौर पर परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन वे इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगी। यदि उनके साथ अमेरिकी कंपनियां भी अपना कारोबार बाहर ले जाती हैं या आउटसोर्स करती हैं तो इससे कुल मिलाकर अमेरिका को ही नुकसान होगा। चूंकि एच-1 बी वीजा धारकों के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय हैं, इसलिए अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को झटका लगेगा, लेकिन भारतीय कारोबारी उनके लिए देश में ही काम के अवसर पैदा कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। उन्हें ट्रंप के फैसले को आपदा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारतीय कंपनियों को देश में ही अपना कारोबार बढ़ाने के जतन इसलिए भी करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप कुछ और ऐसे कदम उठा सकते हैं, जिनके निशाने पर भारत हो। उन्होंने भले ही टैरिफ के मामले में लचीला रवैया अपनाते हुए भारत से शीघ्र व्यापार समझौता होने की संभावना जताई हो, लेकिन वे भारतीय हितों के विपरीत काम करते दिख रहे हैं। वे केवल यही दबाव नहीं बना रहे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, बल्कि उन्होंने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम किया है। ट्रंप अपने फैसलों को इस रूप में रेखांकित कर रहे हैं कि उनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे, लेकिन आठ माह का उनका कार्यकाल उनकी नाकामी ही बयान कर रहा है।

अस्पतालों में हड़ताल

बिहार में सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ी। उपचार की व्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन यह दुखदायी है कि प्रतिदिन राज्य के विभिन्न हिस्से से इन अस्पतालों में हड़ताल की खबरें आती रहती हैं। इसका कारण उपचार से जुड़े डाक्टरों और उनकी मदद करने वाले कर्मियों के साथ खराब व्यवहार होना बताया जाता है। यह मरीजों के स्वजन की ओर से होता है। कभी-कभी सरकारी अधिकारी और जन प्रतिनिधि भी खराब व्यवहार करते हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के सामने अपने दुख को प्रकट करने का एकमात्र माध्यम यही रहता है कि वे हड़ताल पर चले जाएं। इसका प्रभाव उन मरीजों पर पड़ता है, जिनकी पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं रहती है। समय-समय पर सरकार की ओर से भी अस्पतालों की समग्र सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। स्वजन से भी अपेक्षा की जाती है कि वे संयत और गरिमापूर्ण व्यवहार करें, लेकिन जब किसी स्तर पर मामूली चूक होती है, मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। बेहतर हो कि मरीजों को इससे मुक्त रखा जाए, क्योंकि तमाम सुविधाओं के बावजूद सरकारी अस्पतालों के प्रति संपन्न लोगों का विश्वास नहीं जम पाया है। यहां तक कि सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारी भी उपचार के लिए निजी अस्पतालों का ही रुख करते हैं। इसलिए जब अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती हैं तो निरीह-गरीब ही भुगतते हैं। सरकार को भी चाहिए कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी करे। यही अपेक्षा मरीजों को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों से भी की जा सकती है।

सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी करे

लोकतंत्र के खतरे में होने का हौवा

संजय गुप्त

राहुल गांधी आरोप तो लगा देते हैं, पर यह नहीं बताते कि वोट चोरी हो रही है तो भाजपा झारखंड में क्यों हार गई या लोकसभा में बहुमत से पीछे क्यों रह गई?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मामला उठाकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इस बार उन्होंने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट से कांग्रेस के 6,018 वोट काटे जाने का आरोप लगाया और एक प्रेस कांफ्रेंस में प्रजेंटेशन देकर यह समझाया कि किस तरह मोबाइल फोन के जरिये कांग्रेसी वोटरों के वोट काटे गए। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह वोट चोरी के एक मामले को सामने रखा था और उसे एटम बम की संज्ञा दी थी। वे वोट चोरी के एक और मामले को सामने लाएंगे और उसे हाइड्रोजन बम बताएंगे। राहुल का चुनाव आयोग पर निशाना नया नहीं है। वे एक अर्से से यही कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी का मामला उछाल चुके हैं और बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन को भी वोटों की चोरी बता चुके हैं। पहले वे चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की हवा निकल गई तो वोट चोरी के अपने आरोपों को एक अभियान बनाने में जुट गए। वे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उनकी मानें तो मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोप को धार देने के लिए कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट से कांग्रेसी वोटरों के वोट काटे जाने का जो मामला सामने रखा, उससे यह प्रतीति हुई कि 6,018 वोटरों के नाम सचमुच हटा दिए गए, लेकिन कुल 24 वोट काटे गए और वे भी उनके, जिनके कटने चाहिए थे। अन्य वोट काटने की नाकाम कोशिश हुई थी। इस मामले में खुद चुनाव आयोग ने एफआइआर दर्ज कराई। इसकी जांच कर्नाटक सीआइडी कर रही है। राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग कर्नाटक सीआइडी को वोट काटे जाने के मामले में बार-बार मांगे जाने के बाद भी वांछित जानकारी नहीं दे रहा है, पर चुनाव आयोग के अनुसार 2023 के इस मामले में जो जानकारी मांगी गई थी, वह सीआइडी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस हिसाब से गेंद सीआइडी के पाले में है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन के जरिये उस तरह वोट काटे या जोड़े नहीं जा सकते, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं। किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने और जोड़ने की एक तय प्रक्रिया होती है और उसमें चुनाव कर्मचारी शामिल होते हैं। वे अपने स्तर पर छानबीन कर किसी का नाम जोड़ते या हटाते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार गड़बड़ी भी होती है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार बीएलओ और अन्य चुनाव अधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार के तहत काम करते हैं। यदि किसी का नाम हटाने या जोड़ने में कोई खामी होती है तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी यही साबित करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, ताकि चुनाव आयोग को बदनाम कर सकें और यह माहौल बना सकें कि भाजपा छल-छद्म से चुनाव जीतती है।

भारत में 96 करोड़ वोटर हैं और इतने बड़े देश में कहीं पर भी मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है और होती भी है। राहुल गड़बड़ी के जो भी उदाहरण दे रहे हैं, वे कुछ सौ या हजार वोटों के हैं। यह सही है कि मतदाता सूची सही से तैयार होनी चाहिए, पर क्या कांग्रेस इसकी गारंटी ले सकती है कि उसके केंद्र की सत्ता में रहते समय चुनाव आयोग की ओर से तैयार मतदाता सूचियां दुरुस्त होती थीं? कांग्रेस इसलिए खिसियाई है, क्योंकि उसके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है। उसने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद यह माना था कि अब आगामी सभी चुनावों में उसकी जीत होगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो हताशा में उसने अपनी हार का ठीकरा भाजपा और चुनाव आयोग पर फोड़ना शुरू कर दिया। यदि कांग्रेस यह समझ रही है कि इससे उसका गिरता वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा या फिर क्षेत्रीय दलों पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रीति-नीति के कारण। जहां भाजपा की जीत में प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावी नेता की छवि भी कारगर साबित होती है, वहीं राहुल के लिए अपने दम पर कांग्रेस को चुनाव जिताना कठिन हो रहा है।

राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी के कारण लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन वे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाकर खुद ही लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वे संविधान की दुहाई दे रहे हैं, पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को नीचा दिखा रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में राजनीतिक दलों, नौकरशाही, संवैधानिक संस्थाओं और अदालतों की एक बड़ी भूमिका होती है, पर राहुल तो बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं और संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आयोग की साख नष्ट करने में तुले हैं। लोकतंत्र कायदे-कानून से चलता है। मनमानी लोकतंत्र को कमजोर करती है। राहुल मनमानी ही कर रहे हैं। वे यह चाह रहे हैं कि वोट चोरी पर उनकी ओर से जो कहा जा रहा है, उसे सत्य मान लिया जाए। वे अपने कथित पुख्ता प्रमाणों के साथ अदालत भी नहीं जा रहे हैं। लोकतंत्र तब पटरी से उतरता है, जब उसकी संस्थाओं पर संकीर्ण स्वार्थों के लिए हमला बोला जाता है या फिर उन पर अनुचित दबाव बना उन्हें कमजोर किया जाता है। आपातकाल में कांग्रेस ने यही किया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संस्था के कामकाज पर सवाल उठ सकते हैं, पर यह जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। राहुल उलटे-सीधे आरोप लगाकर सनसनी तो फैला देते हैं, पर यह नहीं बताते कि वोट चोरी हो रही है तो भाजपा झारखंड में क्यों हारी या फिर लोकसभा में बहुमत से पीछे क्यों रह गई? क्या उनके रवैये को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? उन्होंने जिस तरह जेन-जी अर्थात नई पीढ़ी को वोट चोरी के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा, उससे तो यही लगता है कि वे अपने अपुष्ट आरोपों के आधार पर लोगों को बरगलाकर अराजकता फैलाना चाह रहे हैं।

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

जब साहित्य का हुआ जेन-जी से सामना

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

साहित्य जगत में चिंता है कि समय रहते जेन-जी को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वर्षों से बनाई उसकी स्थापनाएं ढह जाएंगी

पिछले दिनों पड़ोसी देश में क्रांति हो गई। यह क्रांति पिछली क्रांतियों से थोड़ा अलग रही। इसका श्रेय 'जेन-जी' को दिया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया की नव-संतानों ने रील और वीडियो बना-बनाकर लोकतांत्रिक सरकार को ढहा दिया। 'जेन-जी' ने पहले अपने हाथ में ली हुई डिजिटल-मशाल से आग सुलगाई, फिर सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। सरकार ने भी इस आग में पर्याप्त घी डाला और जी का जंजाल बने कई जेन-जियों को मौत की नींद सुला दी। कई विचारक और विश्लेषक उस क्रांति को अपने यहां भी घसीटकर लाना चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ बदलाव से मतलब है, चाहे जैसे आए, पर हाय तुरंत इसका तोड़ भी आ गया कि अपने यहां लोकतंत्र की बुनियाद वैसी नहीं है। जरा ज्यादा ही मजबूत है। यहां लोग अपने संघर्ष सड़क के बजाय इंटरनेट मीडिया पर ही निपटा लेते हैं। उनकी क्रांति ड्राइंग रूम से उठती है और बेडरूम आते-आते थक जाती है। इस दौरान दो-चार 'मीम' जरूर बन जाते हैं। ये रीलबाज युवा सड़कों, नदियों और खाइयों में गिरकर अपनी आहुति दे रहे हैं। सरकार को इन्हें निपटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। स्वयं निपटे जा रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र सुरक्षित है।

वहां 'जेन-जी' के इस अप्रत्याशित कौतुक से अपने देश की सियासत में ज्यादा हलचल भले न हुई हो, पर साहित्यिक गलियारों में खलबली मच गई। ये नई पीढ़ी न जाने कौन-सी बला बनकर खड़ी हो जाए! बुजुर्गों को चिंता सताने लगी कि यह संक्रमण साहित्य में आ गया तो उनका क्या होगा? 'जेन-जी' कुछ और नहीं, आधुनिक हरकारे हैं। साहित्य जगत में चिंता है कि समय रहते जेन-जी को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वर्षों से बनाई उसकी स्थापनाएं ढह जाएंगी। हम स्तंभकार बेरोजगार हो जाएंगे। इसी पसोपेश में राजधानी के बड़े साहित्यकारों ने एक 'चिंतन-बैठक' आहूत कर ली। इसमें वे सभी लेखक शामिल थे, जो साहित्य के लिए चिंताजनक थे। विषय था, 'साहित्य का संक्रमण-काल।'

इस गंभीर गोष्ठी में मुख्य तीन वक्ता थे। पहले कनिष्ठ वक्ता ने बोलना शुरू किया, 'साथियों, पहली बार हम संकट में हैं। कृपया हम का मतलब साहित्य समझना। लिखना तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, अब ये जेन-जी हमारे दिखने पर भी टोका-टाकी करने लगी है। हम अपने प्रिय की ईमानदार आलोचना तक नहीं कर पा रहे हैं। यह पीढ़ी उसे प्रशंसा समझ लेती है। देखते ही देखते हमारी कारगुजारियां वायरल हो जाती हैं। इससे बड़ा संक्रमण क्या होगा भला?' उनकी बात सुनकर दूसरे वक्ता समय से पहले ही बोलने लगे, 'मित्रों, हमने यह आयोजन इसलिए नहीं किया कि हम संकट में हैं। साहित्य के बारे में नहीं कह सकता। पिछले तीस वर्षों से किसी तरह साहित्य को संक्रमित होने से बचा रखा था। आजकल 'जेन-जी' नामक नई आफत आई है। हमें कुछ नहीं तो सियासत से सबक लेना चाहिए। वहां 'जेन-जी' शांति से काम कर रही है!'

शीर्ष वक्ता बड़ी देर से कसमसा रहे थे। भोजन का समय हो चुका था, पर बीज-वक्तव्य उन्हें देना था। माइक संभालते ही वह टूट पड़े, 'मेरी साहित्य के प्रति निष्ठा असंदिग्ध है। इसका उदाहरण मेरी हवाई यात्रा है। संक्रमण को बचाने के लिए मैं कितनी जल्दी में हूं, इससे पता चलता है। मेरी कविताओं में कबीरी-धार है। वही उलीचने यहां आया हूं।' यह सुनते ही श्रोताओं में भगदड़ मच गई। लोगों को लगा कि बाजार में कोई नया व्यंजन आया है। उन्होंने मंच के नीचे अपनी अंजुरी लगा दी। आयोजकों के बार-बार एलान के बाद भी श्रोता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसी दृश्य को कुछ 'जेन-जियों' ने रील बनाकर वायरल कर दिया।

response@jagran.com

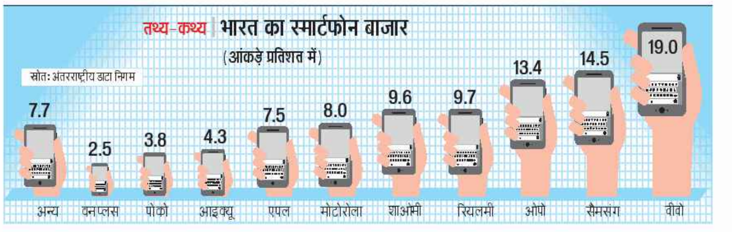

ऊर्जा

शक्ति

'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' यानी ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है, का उद्घोष कर जब आदि शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन कर अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठापना कर रहे थे, तभी एक दिन गंगा स्नान के लिए जाते हुए उन्होंने मार्ग पर दिवंगत पति को गोद में लिए एक स्त्री को देखा। जब हटने को कहा तो उसने शव की ओर संकेत किया। 'मृत देह स्वयं नहीं हट सकती' आचार्य शंकर के ऐसा कहने पर उसने कहा- एकमात्र सत्य अपने ब्रह्म से कहो, वह जरूर हटाएगा। यह सुनते ही उनका भ्रम दूर हो गया। वे उसके चरणों में गिर गए। वह अखिल ब्रह्मांड संचालिका शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा थीं, जो उन्हें अपनी सत्ता का अहसास कराने आई थीं। शक्ति की अखंड सत्ता को पहचान कर उन्होंने पंच देवोपासना में मां दुर्गा को प्रमुख स्थान दिया। शक्ति के बिना शिव भी शव के समान हैं। लोक में इसी भाव की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा, जो सभी जीवों में स्त्रीत्व की उपस्थिति का बोध कराता है।

शक्ति ही सृजन का कारण है और विनाश का भी। यही समस्त कार्य व्यवहारों की साधिका है। इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, किंतु शक्ति का अर्जन जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सदुपयोग। आज दुनिया ने अपनी मेधा शक्ति के बल पर विविध शक्तियों का अर्जन तो कर लिया है, किंतु सदुपयोग न होने से विपरीत परिणाम आ रहे हैं। वस्तुतः शक्ति का दुरुपयोग मानव के विकृत चिंतन का परिणाम होता है। मनीषियों ने शक्ति के उपयोग के आधार पर ही सज्जन और दुर्जन को परिभाषित किया है। सज्जन की शक्तियां सदैव जगत कल्याण के लिए होती हैं, जबकि दुर्जन की परपीड़ा के लिए। इस नवरात्र मां की आराधना कर विविध शक्तियों को अर्जित करें तथा मानवता के विस्तार के लिए उनके सदुपयोग का संकल्प लें।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

मानव डीएनए पर खनिजों का प्रभाव

मुकुल व्यास

भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी पर निर्भर करती है, जो कम दूरी पर भी बहुत भिन्न हो सकती है

हमारे भोजन में खनिजों की भूमिका भले ही बहुत छोटी लगती हो, लेकिन वे हमारे डीएनए पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। एक वैश्विक विश्लेषण से पता चलता है कि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और अधिकता ने मानव जीव विज्ञान को इस कदर प्रभावित किया है कि हमारे स्वास्थ्य पर आज भी उसका असर दिखाई देता है। एक नए अध्ययन में 40 तरह की आबादी में 13 खनिजों से जुड़े 276 जीनों की जांच की गई। इसमें इस बात के स्पष्ट संकेत मिले कि स्थानीय आहार और मिट्टी का प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया पर असर पड़ा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मददगार आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वे उत्तरजीविता या प्रजनन में सुधार करते हैं। विभिन्न मानव आबादियां अलग-अलग वातावरण में रहती थीं, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय दबावों के अनुरूप खुद को ढालना पड़ा।

यह पहला शोध है जो वैश्विक स्तर पर और इतने सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों से प्रेरित अनुकूलन का अध्ययन करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी पर निर्भर करती है, जो कम दूरी पर भी बहुत भिन्न हो सकती है। पौधे जमीन से खनिज ग्रहण करते हैं और जानवर पौधों को खाते हैं। भूविज्ञान चुपचाप यह तय करता है कि हमारी थाली में क्या जाता है। दुनिया में लगभग दो अरब लोग खनिजों की कमियों से प्रभावित हैं। आहार में आधुनिक सप्लीमेंट जुड़ने से पहले ये अंतर और भी बड़े होते थे। नए अध्ययन ने कुछ मध्य अमेरिकी माया समुदायों में आयोडीन से संबंधित जीनों पर प्रकाश डाला, जो आयोडीन की कमी वाली मिट्टी पर रहते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग (गायटर) हो सकता है। इस रोग में एक बढ़ी हुई थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन के कम उत्पादन का संकेत देती है।

ये अध्ययन यह समझाने में मदद करते हैं कि एक ही आहार लोगों को अलग-अलग तरीके से क्यों प्रभावित कर सकता है। जलवायु दबाव का भी प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइआक्साइड के बढ़ते स्तर से प्रमुख फसलों में जिंक और आयरन की मात्रा कम होती है, जिससे कई परिवारों के लिए पहले से ही कम पोषण संबंधी सीमाएं और कम हो सकती हैं। आज जन स्वास्थ्य के लिए आयोडीन युक्त नमक और पोषक तत्वों से संवर्धित अनाज जैसे कदमों पर जोर दिया जाता है। विज्ञानियों का कहना है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ने दुनिया भर में मानव विकास को पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रत्यक्ष रूप से आकार दिया है। यह शोधपत्र यह समझने की दिशा में पहला कदम है कि कौन सी आबादी सबसे अधिक जोखिम में हो सकती है। वैसे आपका स्वास्थ्य आहार, पर्यावरण और कई जीनों के एक साथ काम करने पर निर्भर करता है। फिर भी ये खोजें रोकथाम के तरीकों को और बेहतर बनाने में योगदान कर सकती हैं।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

सिद्दा का जवाब

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया (सिद्दा) यूं तो कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ और राजनीतिक रूप से भारी-भरकम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लाइमलाइट तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ले जा रहे हैं। राहुल गांधी भी रेवंत रेड्डी की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, खासकर जातिगत सर्वे के बाद। ऐसे में सिद्दा ने अब बैलेट पेपर के जरिए बाजी पलटने की कोशिश की है। दरअसल उनकी सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकारी अधिकारियों की ओर से इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव में न सिर्फ गड़बड़ी की आशंका बढ़ेगी, बल्कि खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल सिद्दा की इस चाल को कांग्रेस के अंदर भी उनकी राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है।

आरजी और जेन-जी

कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दल वोट चोरी का नैरेटिव जनता के बीच खड़ा करने के प्रयास में महीनों से जुटे हैं। उसका कितना असर हुआ, यह तो बिहार चुनाव परिणाम के साथ सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस बीच नेपाल में सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरी जेन-जी से भारत की जेन-जी का कनेक्शन जोड़कर कांग्रेस के आरजी यानी राहुल गांधी ने अपने लिए फजीहत जरूर मोल ले ली। आरजी ने तराना छेड़ दिया कि यहां भी जेन-जी बदलाव के लिए खड़ी होगी, लेकिन उनके लिए यह मामला सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा हो गया। शुक्रवार को ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, जिसमें कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआइ की करारी हार हो गई। अब इंटरनेट मीडिया पर सबसे अधिक सक्रिय रहने वाली जेन-जी के सामने ही विरोधी खेमा राहुल गांधी को ट्रोल कर रहा है कि इस चुनाव में तो जेन-जी ही वोटर थी, उसने तो करारा जवाब दे दिया।

हाल बड़ा, दर्शन छोटे

इंतजाम तो सब किया गया था। गाना था, बजाना था, शानदार खाने और पीने के भी इंतजाम थे, लेकिन इसके बावजूद जब हाल नहीं भरा, तो सबके चेहरे लटक गए। हुआ यह कि उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने पिछले हफ्ते एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम- इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की सालाना बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की काफी प्रतिष्ठा है। बीआइएस ने इसका आयोजन भारत मंडपम में किया। बस गलती यह हो गई कि आयोजन के लिए मुख्य हाल का चयन किया गया, जो अभी तक पीएम के कार्यक्रम में ही भरता है। विदेशी मेहमानों ने समय पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन मंत्री जी के आने में देरी होने लगी। बताया गया कि हाल के भरने का इंतजार किया जा रहा है। जल्दबाजी में भीड़ का इंतजाम भी नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। कार्यक्रम हुआ, लेकिन हाल का बड़ा हिस्सा खाली ही रहा। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हाल के चयन में भी सतर्कता बरती जाए।

अभी और कौन से बम फूटेंगे

मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से फोड़े जा रहे 'बमों' को चुनाव आयोग अब तक भले ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करता आ रहा है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी हाइड्रोजन बम एवं दूसरे बमों को फोड़ने की बात की है, उससे चुनाव आयोग की चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। चुनाव आयोग वैसे भी इस सियासी बमबारी में दोहरी चुनौती झेल रहा है। पहली किसी भी छोर से किए जाने वाले हमलों का तुरंत ही तथ्यात्मक जवाब देने की है, दूसरी खुद की छवि को बचाए रखने की चुनौती भी है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इन हमलों को देखते हुए देश भर के अपने अमले को अलर्ट मोड पर रखा है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

यह कैसा विश्व शांति दिवस

सन् 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपेक्षा की थी कि कम से कम इस मौके पर एक दिन के लिए युद्ध थम जाएंगे, आतंकवादी वारदातें नहीं होंगी और अमन को लेकर आम राय बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। अतीत की गलियों में भटके बिना सिर्फ रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल के गाजा अभियानों पर नजर डाल देखें। रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे और इजरायल का गाजा अभियान तीसरे वर्ष की दहलीज पर हैं।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

बरसों पहले वह अनंतनाग में यकायक मिल गया था। परिचय होते ही उसने अपनी दर्दनाक दास्तां बयां करनी शुरू कर दी कि सियासी कारणों से उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह कलेक्टर के यहां फरियाद लेकर पहुंचा, पर वह या कोई अन्य सरकारी अधिकारी उसे सुनने को तैयार न था।

बेबसी के उन लम्हों में अपने हाथ आसमान की ओर ऊपर उठाए और फफक पड़ा- दहशतगर्द फौज की वर्दी में और फौजी 'दाढ़ियें' बढ़ाकर जब चाहें, तब टपक पड़ते हैं। जो आता है, घर में घुसा चला आता है- या खुदा, यह अजाब हम पर कहां से आ टूटा!

आज अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस है। इस मौके पर मैं समूची दुनिया में छाई अशांति और उससे उपजी वेदनाओं की चर्चा करना चाहता हूं।

सन् 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपेक्षा की थी कि कम से कम इस मौके पर एक दिन के लिए युद्ध थम जाएंगे, आतंकवादी वारदातें नहीं होंगी और अमन को लेकर आम राय बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। अतीत की गलियों में भटके बिना सिर्फ रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल के गाजा अभियानों पर नजर डाल देखें। रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे और इजरायल का गाजा अभियान तीसरे वर्ष की दहलीज पर हैं। यहां के हुक्मरानों ने संयुक्त राष्ट्र की सदिच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी जिद पूरी न होने तक वे रुकना भी नहीं चाहते। यह हाल उन देशों का है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। रूस के पास तो 'वीटो' का अधिकार भी है।

आतंकवादियों से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है, पर जब संयुक्त राष्ट्र के विधान से बंधे देश दहशतगर्दी फैलाने लगें, तब?

पहलगाम हमला इसका जीता-जागता उदाहरण है। भारत ने इसके प्रतिकार में 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिये आतंक के तमाम अड्डों को तबाह कर दिया। भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक ने इसके तत्काल बाद पाकिस्तान स्थित अपने समकक्ष को फोन पर कहा कि हमारा अभियान पूरा हुआ। इस मुद्दे को अब यहीं विराम दिया जा सकता है, मगर पाकिस्तान ने जवाबी हमला बोल दिया। तीन दिन की इस मुठभेड़ के दौरान पूरी दुनिया सकते में थी कि दो परमाणु शक्ति संपन्न मुल्कों की यह मुठभेड़ अगर परमाणविक जंग में तब्दील हो गई, तो क्या होगा?

संघर्ष-विराम ने लोगों को राहत तो दी, पर सवाल कायम है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आया तो?

यह सवाल फिजां में फड़फड़ा ही रहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़ पड़े। एक मठ के स्वामित्व को लेकर जिस तरह भारी तोपों और अत्याधुनिक बमवर्षकों का इस्तेमाल किया गया, वह चौंकाता है। धरती के इस भू-भाग पर कूटनीतिक व व्यावसायिक प्रभुत्व के लिए अमेरिका और चीन, दोनों प्रयत्नशील हैं। कहीं यह इन महाशक्तियों के बोए अंगारे तो नहीं थे? हकीकत जो हो, पर क्या हम तीन साल पहले तक भारत-पाकिस्तान और इन दोनों पड़ोसियों की भिड़ंत की कल्पना कर सकते थे?

साफ है, धरती के वायुमंडल में बारूद घुल चुकी है। चीन-अमेरिका के बीच पनप रहा शीतयुद्ध इसे और जहरीला बनाने पर तुला है।

इस महाबला की शुरुआत हुई थी, 24 फरवरी 2022 को, जब रूस के दस्तों ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इस जंग से अब तक एक करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन खूंरेजी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों और महिलाओं से सरेआम बेअदबी, हत्या, लूट और इंसानों की तिजारत के जिन्न अतीत की कब्रगाहों से बाहर आकर यूक्रेन की खूबसूरत धरती को क्षत-विक्षत कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने भी जवाबी हमलों में रूस को खासी क्षति पहुंचाई है। कीव के प्रभावकारी प्रतिकार ने मॉस्को की सामरिक अभेद्यता की कलई खोल दी है, पर इससे आम आदमी का लुटा अमन-चैन वापस तो नहीं मिल जाता।

गाजा पट्टी का हाल इससे भी बुरा है। इजरायली दस्ते यहां के बीस लाख लोगों को दर-बदर करने पर आमादा हैं। यहां के लोग कहां जाएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। 'मुस्लिम ब्रदरहुड' के ये नारेबाज पहले भी थोथे साबित हो चुके हैं। रही बात अमीर अरब देशों की, तो उन्होंने तब गुर्राना शुरू किया, जब इजरायली जेट विमानों ने कतर पर बमबारी कर दी। कतर कोई ऐसा-वैसा मुल्क नहीं। इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा यहीं है। तेल अवीव का कहना था कि ऐसा उसने हमास की कमर तोड़ने के लिए किया। इसी बिना पर वह गाजा में पिछले 23 महीनों से कहर ढा रहा है। सवाल उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से पूछे बिना इस कारनामे को अंजाम दिया?

यही सवाल अरबी शेखों को मथ रहा है, लिहाजा बरसों बाद वे एकजुटता की कसमें खा रहे हैं। भारत-पाक झड़प के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया था। उस वक्त तुर्किये का जंगी जहाज और नौसैनिक कराची में मौजूद थे। इससे पहले वह पाक को घातक ड्रोन मुहैया करा चुका था। और तो और, अजरबैजान ने भी मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे डाले। पिछले हफ्ते चर्चा में आई सऊदी अरब और पाकिस्तान की सामरिक संधि भी चौंकाती है। साफ है, परमाणु शक्ति से इठलाता पाक मुस्लिम देशों का सर्वराकार बनने की जुगत में है और उसे समर्थन भी हासिल हो रहा है।

यह नई लामबंदी और अमेरिका का रुख-रवैया अच्छे संकेत नहीं देते। वजह? सोवियत संघ के विघटन के बाद मजबूत हुए अमेरिकी पूंजीवाद के युग में, यानी 1991 से कोविड-2019 के आगमन तक लगभग एक अरब लोग दरिद्रता के मकड़जाल से बाहर आ चुके थे। इसी दौरान, चीन व भारत का आर्थिक अभ्युदय हुआ और आसियान जैसे संगठन उभरे। सब ठीक चल रहा था कि कोरोना आ गया। इस महामारी ने *वसुधैव कुटुंबकम्* की इस पनपती धारा को अवरुद्ध कर दिया।

कोरोना काल में ही तमाम समाजशास्त्रियों ने आशंका जताई थी कि खुदगर्जी की यह प्रवृत्ति अभी और पनपेगी। वे गलत नहीं थे। संयोग से उस वक्त भी ट्रंप ओवल ऑफिस पर काबिज थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में लौटते ही जिस तरह 'टैरिफ टेरर' फैलाया है, उससे इस अलगाव और नई गोलबंदियों को बढ़ावा मिल रहा है। यूरोप, मुस्लिम देश, कम्युनिस्ट ब्लॉक, आसियान, अफ्रीकी पहचान की पहल आदि-इत्यादि। यह दुनिया कितने हिस्सों में बंटेगी? इसके क्या नुकसान होंगे?

कोई आश्चर्य नहीं। बाहरी ताकतों से युद्ध के अलावा तमाम देश इसीलिए अंदरूनी असंतोष की आग में झुलस रहे हैं। पड़ोसी नेपाल में जो हुआ, वह डराता है। इससे पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इस आग में झुलस चुके हैं। कोरोना ने सिर्फ इंसानी जिस्मों नहीं, समाजों को भी विभक्त किया है। पिछले तीन महीनों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अन्य हिस्सों में जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, वे पश्चिम की तथाकथित उदार सेक्युलर परंपरा के बरखिलाफ हैं। मौजूदा राजनीति, राजनेता और समूचा सिस्टम इसके शिकार हैं।

तय है, हम एक अजाने और अनुदार वक्त की ओर बढ़ रहे हैं। यह विश्व-शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। 1930 के दशक में इससे मिलते-जुलते समीकरण उभरे थे, जिसका अंजाम दूसरा विश्व-युद्ध था। यह दुनिया अतीत के अपराधों से कोई सबक क्यों नहीं लेती?

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीने की राह | **सुरेखा यादव** ट्रेन पायलट

भारतीय रेलवे के इतिहास का एक सुर्खरू पन्ना

देश की पहली ट्रेन पायलट सुरेखा 39 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय रेलवे से विदा हो रही हैं, तब उनके पास इस सुकून की एक बड़ी पूंजी है कि हिन्दुस्तान की हजारों बेटियों ने उनके नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया। आज ढाई हजार से अधिक महिलाएं लोको पायलट हैं।

आपने कभी गौर किया है कि किसी काम को पहली बार करने वाला हर इंसान हमारी यादों का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता, जैसे बल्ब, रेडियो और जहाज का आविष्कारक बना, जैसे पर्वत चोटियों पर और अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखने वाला शख्स बना अथवा कोई भूगोल अन्वेषी या इतिहासकार हमारे जेहन में नक्श हुआ, क्योंकि ऐसे तमाम प्रथम लोगों की खोजों ने व उनके कार्यों ने दूसरों को प्रेरित नहीं किया। मगर सुरेखा यादव ने आधी आबादी को रास्ता दिखाया कि लड़की हो, तो क्या हुआ, तुम भी ट्रेन चला सकती हो; तुम्हारे पास भी कुव्वत है, हर वह काम करने की, जिससे तुमको वंचित रखा गया है।

देश की पहली ट्रेन पायलट सुरेखा करीब 39 वर्षों की सेवा के बाद अब जब भारतीय रेलवे से विदा हो रही हैं, तब उनके पास इस सुकून की एक बड़ी पूंजी है कि हिन्दुस्तान की हजारों बेटियों ने उनके नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया और आज ढाई हजार से अधिक महिलाएं बतौर लोको पायलट देश की सेवा कर रही हैं। अब इससे सार्थक मानव जीवन और क्या होगा कि लोग आपकी मिसालें दें व देश के प्रधानमंत्री आपको गर्व से याद करें!

ठीक 60 साल पहले सतारा (महाराष्ट्र) के एक किसान दंपति सोनाबाई और रामचंद्र भोसले की जिंदगी में सुरेखा पहली संतान बनकर आईं। आई-बाबा ने उन पर भरपूर स्नेह और आशीष बरसाया। वे जानते थे कि हल का अगला सिरा ही खेत को उर्वर बनाता है। उनकी अगली संततियां सुरेखा को देखकर ही सीखेंगी। बेटी को अच्छी शिक्षा मिल सके, यह सोचते हुए प्रगतिशील विचारों के मालिक पिता ने स्थानीय सेंट पॉल कॉन्वेंट हाईस्कूल में उसका दाखिला करा दिया। सुरेखा ने अपने परीक्षा परिणामों से माता-पिता को हमेशा गौरवान्वित महसूस कराया। गणित उनका प्रिय विषय था। वह स्कूली खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती रहीं।

अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद सुरेखा को तरह-तरह के सुझाव मिले। किसी ने कहा, लड़कियों के लिए टीचर की नौकरी काफी अच्छी होती है, तो किसी ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी। सुरेखा को शिक्षण-कार्य पसंद था, मगर उन्हें लगा कि कुछ नया करना चाहिए। उन दिनों मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियां आने लगी थीं, मगर इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नगण्य थी। गणित में दिलचस्पी सुरेखा को कराड (सतारा) के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज ले गई, जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में उन्हें दाखिला भी मिल गया।

डिप्लोमा की डिग्री हाथ में थी, मगर वह और आगे पढ़ना चाहती थीं। सुरेखा गणित में स्नातक और बीएड करना चाहती थीं, ताकि वह शिक्षक बनने की योग्यता हासिल कर सकें। मगर नियति ने उनके लिए अलग चुनौती तय कर रखी थी।

इधर डिप्लोमा का प्रमाणपत्र मिला और उधर अखबार के एक इश्तिहार पर निगाह पड़ी, जिसमें भारतीय रेलवे ने एक असिस्टेंट ड्राइवर की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। किसी भी विषय के डिप्लोमाधारी उसके लिए आवेदन कर सकते थे। सुरेखा तब नहीं जानती थीं कि आज तक किसी महिला ने यह नौकरी नहीं की है।

एक जिज्ञासु अभ्यर्थी की तरह उन्होंने आवेदन कर दिया। मगर जब लिखित परीक्षा के लिए वह परीक्षा-कक्ष में दाखिल हुईं, तब उन्हें यह देखकर अचंभा हुआ कि वहां वह अकेली लड़की हैं। सोचा, शायद दूसरे कमरों में और महिला अभ्यर्थी होंगी। लिखित परीक्षा में कामयाबी के बाद जब सुरेखा इंटरव्यू देने पहुंचीं, तो वहां भी वह अकेली लड़की थीं। उस वक्त भान हुआ कि यह एक ऐतिहासिक पल है। एक महती जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस हुई। देश की आधी आबादी के लिए इस बंद दरीचे को उन्हें खोलना था।

जीवन के उस पहले साक्षात्कार को संपन्न हुए कई दिन बीत चले थे। सुरेखा ने मान लिया था कि इतिहास रचने से वह चूक गई हैं। मगर एक दिन इलाके के डाकिया ने मुस्कराते हुए उन्हें एक लिफाफा थमाया और उनकी मां से मुंह मीठा कराने को कहा। सुरेखा सुर्खरू हो गई थीं। भारतीय रेलवे ने उनमें भरोसा जताते हुए उन्हें कल्याण ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया था। जिंदगी में चौपहिया तो छोड़िए, कभी दोपहिया भी न छूने वाली सुरेखा के लिए यह सब किसी ख्वाब सरीखा था।

बहरहाल, अगले छह महीने गहन प्रशिक्षण के थे। सुरेखा ने इस दौरान ड्राइविंग, इंजन और सिग्नल से जुड़ी एक-एक बारीकी को जाना-समझा। आखिरकार, 14 फरवरी, 1989 को वह नियमित सहायक चालक बना दी गईं। उनकी पहली नियुक्ति मालगाड़ी के संचालन से जुड़ी थी। सुरेखा को सबसे पहले वाडी बंदर से कल्याण तक चलने वाली एल-50 मालगाड़ी चलाने का मौका मिला। इसके अगले ही साल वह महाराष्ट्र पुलिस में सब-इंस्पेक्टर शंकर यादव के साथ दांपत्य-सूत्र में बंध गईं। एक महिला के लिए घरेलू दायित्वों और ट्रेन परिचालन की पेशेवर चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना कतई आसान न था। मगर सुरेखा ने इसे साधा। नतीजतन, साल 1998 में उन्हें मालगाड़ी परिचालन का पूर्ण दायित्व सौंपा गया।

सदी ने करवट ली, तो भारतीय नारियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं ने भी नया चोला पहना। मालगाड़ी चलाते हुए कई साल हो गए थे, सुरेखा के मन में मुसाफिर गाड़ी चलाने की गहरी अभिलाषा थी। उनके दुर्घटनारहित कार्यकाल को देखते हुए वर्ष 2000 में उन्हें 'मोटरवुमन' बना दिया गया। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने खूब हौसला अफजाई की। उसके बाद तो वह मेल एक्सप्रेस की पायलट भी बनीं और फिर 8 मार्च, 2011 को वे पल भी आए, जब देश के सबसे जोखिम भरे रेलमार्ग पर सुरेखा ने 'दक्कन क्वीन' को दौड़ाया। अब जब 30 सितंबर को वह सेवा-मुक्त होने जा रही हैं, तब देश अपनी इस दिलेर बेटी को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है!

सुरेखा ने मान लिया था कि इतिहास रचने से वह चूक गई हैं। मगर एक दिन इलाके के डाकिया ने मुस्कराते हुए उन्हें एक लिफाफा थमाया और उनकी मां से मुंह मीठा कराने को कहा। सुरेखा सुर्खरू हो गई थीं। भारतीय रेलवे ने उनमें भरोसा जताते हुए उन्हें कल्याण ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया था।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा | **उरी एवनेरी** शांतिदूत पत्रकार व राजनेता

ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़ दीजिए

करीब अस्सी साल पहले फलस्तीन का स्वरूप यह था कि यहूदी बसने लगे थे, पर हर दूसरा या तीसरा घर किसी अरब का था। अरब तब यहूदियों के खून के प्यासे थे, तो यहूदियों ने भी तय कर रखा था कि खून बहाने में पीछे नहीं रहना है। कभी अरब सवा शेर साबित होते, तो कभी यहूदी।

दुनिया में ज्यादातर लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ईंटों-पत्थरों को एकत्र कर कोई चबूतरा बनाने की कोशिश करते हैं। सुकून का ऐसा चबूतरा, जिस पर बैठकर ईंट-पत्थर मारने वाला भी अपनी गलती पर पछता सके। ईंट फेंकने वाले को भी यह एहसास हो कि जितनी ईंटें उसने फेंकी हैं, उतनी ही ईंटें उसके अपने घर की दीवारों से निकल गई हैं।

वैसे, दुनिया बहुत विचित्र है, यहां अनेक बस्तियां ऐसी हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में खंडहर हुई जा रही हैं। तब पश्चिम एशिया में ऐसा ही हो रहा था। ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में वह 19 साल का यहूदी नौजवान भी शामिल था। यहूदियों को फलस्तीन में बसाने की लड़ाई चल रही थी। उस युवा को विरोधी पक्ष आतंकी मानता था, जबकि वह खुद को सेनानी कहता था। उसे सीधे हिंसा में शामिल नहीं किया जाता था, पर वह समूह के लिए बाकी तमाम काम करता था। अक्सर छिपकर रहना पड़ता था। तब फलस्तीन का स्वरूप यह था कि यहूदी बसने लगे थे, पर हर दूसरा या तीसरा घर किसी अरब का था। अरब तब यहूदियों के खून के प्यासे थे, तो यहूदियों ने भी तय कर रखा था कि खून बहाने में पीछे नहीं रहना है। कभी अरब सवा शेर साबित होते, तो कभी यहूदी। ईंट-पत्थर का चक्कर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। मृतकों, घायलों का तांता लगा रहता था।

उस दिन भी यही हुआ था, बड़ी संख्या में अरब मारे गए थे और यहूदी लड़ाकों में से भी चंद ही अपने पैरों पर लौटे थे। उस युवा के सामने बहुत बर्बर मंजर था, अपने ही युवा साथियों की देह पर न रक्त सूख पाता था और न उनके आंसुओं का सिलसिला टूटता था। वह युवा बेचैन हो गया, उसे समूह में शामिल हुए चार वर्ष बीत गए थे। लड़ते हुए समाधान दूर तक नहीं दिख रहा था। जिंदगी भागते हुए ही बीत रही थी। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि यह भागने-भगाने का क्रम आखिर कब टूटेगा?

उसके दिलो-दिमाग में उसका बीता हुआ कल ताजा हो गया। दस की उम्र रही होगी, जर्मनी से जान बचाकर यहूदी भाग रहे थे। उसके माता-पिता भी भागकर यहूदियों की प्राचीन भूमि फलस्तीन पहुंचे थे। जर्मनी में किसी तरह का अभाव न था, पर फलस्तीन में परिवार जल्द ही इतना गरीब हो गया कि 14 की उम्र में पढ़ाई लायक पैसों का भी टोटा पड़ गया। पढ़ाई छूट गई और पेट के लिए काम करने की शुरुआत हुई, पर काम भी कहां ढंग से हो पाया? ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले समूह में शामिल होना पड़ा। लोग बार-बार कहते थे कि यहूदी अगर अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, तो मिट्टी में मिल जाएंगे। खैर, अब तो यह बात समझ में आ गई है कि हिंसा का कोई अंत नहीं होता और न हिंसा किसी समस्या का निदान है। ऐसे में, हिंसा की मूर्खता को छोड़ देने में ही यहूदियों के साथ-साथ अरबों की भी भलाई है।

दूसरे ही दिन जब उस युवक ने अपने हिंसक संगठन इरगुन को छोड़ दिया, तो छोटे से उभरते देश इजरायल में यह चर्चा आग की तरह फैली कि उरी एवनेरी गद्दार हो गया। आलोचना और निंदा की ईंटें बरसने लगीं, पर इस बार सबको जवाब देने के लिए उरी के पास पत्थर नहीं थे, कलम थी। कलम हिंसा के खिलाफ अमन-चैन की ओर बढ़ चली। उरी ने साफ कर दिया कि उन्हें रहने के लिए अपना इजरायल चाहिए, पर ऐसा इजरायल, जहां शांति हो, अहिंसा हो और लोग प्रेम से रहें। अरब और यहूदी, दोनों को साथ रहना होगा, तो इसका एक ही उपाय है, यहां दो देश बन जाएं, एक अरबों का रहे और दूसरा यहूदियों का।

उरी के इस द्वि-देशीय दर्शन को आज भी पश्चिम एशिया में एकमात्र समाधान के रूप में देखा जाता है। उरी आजीवन अरबों और यहूदियों को समझाते रहे कि लड़कर किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचेंगे और एक-दूसरे को मिटा देने की तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। वह शांति के पक्ष में एक के बाद एक पुस्तकें लिखते चले गए। कलम की ताकत को भरपूर आजमाया और एक पत्रकार-संपादक के रूप में खूब चर्चित हुए। अपना राजनीतिक दल बनाया और इजरायली संसद के सदस्य भी बने। कई मौके आए, जब 120 सदस्यीय संसद में ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति के खिलाफ सिर्फ उरी एवनेरी को देखा गया।

युद्ध से सबक लेने पर जोर देने वाले उरी ने अमन-चैन की बहाली के लिए जोखिमों के पहाड़ उठाए। बड़े आंदोलन खड़े किए। वह फलस्तीनियों के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात से मिलने के लिए सारी हदें पार कर गए थे और उनसे मिलकर समझाया था कि अरब दुनिया में अमन को तवज्जो देने की बड़ी जरूरत है। उरी एवनेरी (1923-2018) को आज इजरायल में ही नहीं, पूरी अरब दुनिया में याद करने वाले बहुत हैं और सब भारी मन से कहते हैं, यहां अब उनके जैसा कोई नहीं है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

हिंदी के हम राजकपूर

तिरछी नजर | **सुधीश पचौरी** हिंदी साहित्यकार

हिंदी का माहात्म्य बता चुका हूं। इसी के चक्कर में मैं इस 'हिंदी सीजन' के तीन 'हिंदी दिवस' मनाकर आया हूं। इनमें से एक सरकारी संस्थान का था, दूसरा अर्द्ध-सरकारी था और तीसरा एक कॉलेज वाला!

तीनों संस्थानों ने मुझे अपने-अपने स्मृति-चिह्न दिए हैं, जिन पर बड़े-बड़े अक्षरों में संस्थान का नाम उकेरा हुआ है, ताकि जब यह लेखक अपने ड्रॉइंग रूप में उसे सजाए, तो सबकी नजर इस सम्मानित लेखक के नाम पर न पड़कर पहले उस संस्थान के नाम पर पड़े। यूं आगे की इबारत कहती है कि हिंदी दिवस के इस महान अवसर पर अध्यक्ष या मुख्य अतिथि या प्रमुख वक्ता के रूप में मुझे सम्मानित करते हुए संस्थान को बड़ा गर्व या हर्ष हो रहा है।

संस्थान को तो गर्व हो रहा है, लेकिन मेरी पूछो, तो मुझे न गर्व महसूस हो रहा है, न हर्ष। हां, यह सोचकर थोड़ी शर्म सी जरूर आ रही है कि भैये, इस हिंदी सीजन में तुझे मिला क्या? वही तीन स्मृति-चिह्न, जिनको कबाड़ी तक नहीं उठाता और वही गमले, जो मेरे अंदर पौधों का हत्यारा जैसा अपराध-बोध भरते रहते हैं व वही तीन शॉल, जो एकदम पटरी बाजार वाले हैं और पत्रम्-पुष्पम् यानी कैशम् के नाम पर ठेंगा? एक के बाद एक, तीन समारोहों में इस लेखक ने कुल 15 घंटे गवाए हैं। इनमें से कुल मिलाकर डेढ़ घंटे बोला, बाकी के 'कुछ आरजू में कट गए कुछ इंतजार में।'

सच कहूं, जो मेरा हाल है, वही हर हिंदी वाले का है। हर बरस हिंदी दिवस आता है और कुछ स्मृति-चिह्न, कुछ सस्ते शॉल-दुशाले और कुछ गमले देकर निकल लेता है। यूं तो हरेक संस्थान के पास हिंदी दिवस मनाने के लिए एक तय बजट होता है, जो हॉल के खर्चे, मंचादि की साज-सज्जा, हिंदी विद्वानों के आने-जाने, स्मृति-चिह्न, शॉल-दुशाले, गमले आदि मदों में खर्च होता है। ऐसे हर बजट में सबका हिस्सा होता है, लेकिन हिंदी के नाम पर सादर आमंत्रित हिंदी लेखकों के नाम एक धेला नहीं होता।

वे हिंदी के नाम पर लाखों खर्च करेंगे, लेकिन हिंदी वाले को एक न देंगे। कभी फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे कि ऑनलाइन आएगा, लेकिन अक्सर आएगा नहीं। आप कहेंगे कि भैये, ऐसे में आप गए ही क्यों? क्या पहले नहीं पूछ सकते थे कि हे आयोजक, यह बताएं कि आप मुझे कुछ पत्रम्-पुष्पम् देंगे या फ्री फंडिया हिंदी की सेवा कराएंगे?

आप की बात सही है। पहले ही तय कर लेना चाहिए था कि कुछ मिलेगा कि नहीं और तब आप मना भी कर सकते थे कि फ्री में क्यों जाएं? लेकिन क्या करूं? हिंदी वाला होना और हिंदी-प्रेम ही मेरा दुश्मन बन गया। हिंदी वाले की छवि ही कुछ ऐसी बन चली है कि वह तो हिंदी सेवक है, हिंदी के लिए समर्पित पुण्यात्मा। उसे तो हिंदी को देना ही है, लेना कुछ नहीं। हिंदी वाला तो ऐसा साधु-संत है, जिसके बारे में कहा गया है-

वृक्ष कबहुं नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर!
परमारथ के कारनै, साधुन धरयो शरीर!!

सच कहूं। जब तक हिंदी वाले की यह इमेज है, तब तक वह इसी तरह से छीला जाता रहेगा। अब छिलते रहो बेटा, करते रहो हिंदी-सेवा, बनते रहो हिंदी के राज कपूर और कहते रहो कि मैं तो अनाड़ी हूं जी और लुटते-बिसूरते रहो कि हाय! एक तू (कैश) ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है?

जब तक आम हिंदी वाला अपनी इस छवि को नहीं सुधारता, तब तक वह इसी तरह उल्टे उस्तरे से छीला जाता रहेगा। अब हिंदी को हिंदी-प्रेमी की नहीं, हिंदी प्रोफेशनल की जरूरत है। हिंदी वाले को मानना होगा कि हिंदी एक प्रोफेशन है, स्किल है, एक कौशल है। उसे पाने में मेहनत लगती है, उसकी भी कीमत है। वह घर की मुर्गी नहीं, जिसे दाल बराबर माना जाए। इसीलिए हे हिंदी वाले, तू हिंदी-प्रेमी न बन, हिंदी प्रोफेशनल बन!

कटाक्ष | **राजेंद्र धोड़पकर**

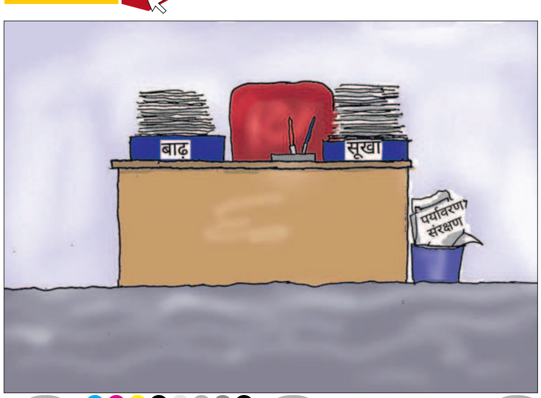

https://t.me/AllNewsPaperPaid

“ एक छोटी-सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है।
-बेंजामिन फ्रैंकलिन

जब बारिश अपने देस वापस चली जाएगी, तो सड़कें, कॉलोनी और वे तमाम शहर, जो हिमाचल, पंजाब और एनसीआर में हैं, अपने सीवेज सिस्टम को असहाय देखेंगे और आवाज लगाएंगे उन मैनहोल स्कैवेंजर्स को, जो सिर्फ आर्थिक और मानवीय जज्बा लेकर उन बंद पड़े सीवेज को खोलने और उन शहरों को बचाने उतरेंगे।

सीवेज से झांकता वह आदमी

मैनुअल स्कैवेंजिंग को 1993 में ही गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, फिर भी भारत में यह जारी है। आईआईटी, मद्रास के प्रयासों से भारत का पहला मैनहोल सफाई रोबोट भी आ चुका है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान कर रहा है।

नंदितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

ये घटनाएं न तो नई हैं और न ही आश्चर्यजनक। मानसून के मौसम में निष्ठुर बारिश ने राजधानी दिल्ली को तो डुबोया ही, उस गुरुग्राम को भी पानी-पानी कर दिया, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उन तमाम अट्टालिकाओं से घिरा किसी दंभ में डूबा रहता है। न गाजियाबाद बचा और न नोएडा। बस बचा तो वह ग्रेटर नोएडा, जिसने यह बताया कि कोई शहर अगर अपनी प्लानिंग में सीवेज सिस्टम को मजबूत नहीं बनाता, तो बारिश अगले ही पल इन शहरों को नदी का घाट बना देगी। वह बारिश हिमाचल और पंजाब भी पहुंची। पंजाब में तो सब कुछ तबाह ही कर दिया। इस बार बारिश ने लुधियाना और अमृतसर से लेकर मोहाली और जालंधर तक के शहरी केंद्रों और ग्रामीण पंजाब के खेतों को जलमग्न कर दिया है। लेकिन जब बारिश अपने देस वापस चली जाएगी, तो सड़कें, कॉलोनी और वे तमाम शहर, जो हिमाचल, पंजाब और एनसीआर में हैं, अपने सीवेज सिस्टम को असहाय देखेंगे और आवाज लगाएंगे उन मैनहोल स्कैवेंजर्स को, जो सिर्फ आर्थिक और मानवीय जज्बा लेकर उन बंद पड़े सीवेज को खोलने और उन शहरों को बचाने उतरेंगे। यह और बात है कि उन बंद सीवेज को खोलने में वे अगर जान भी गंवा बैठे, तो भला क्या हो जाएगा? क्या किसी को फर्क पड़ेगा? कोई शहर उनके लिए कृतज्ञ होगा? क्या कोई जुलूस भी निकलेगा, अगर वे उन सीवेज से न निकल पाए तो? और क्या न्याय के दरवाजे पर सर पटका जाएगा?

कुछ भी नहीं बदलता। कहानी वहीं खत्म होती है, जहां से शुरू होती है। हमेशा एक आदमी जमीन के नीचे गायब दिखता है और दूसरा सतह पर थोड़ा जमीन से बाहर नजर आता है। तीसरा आदमी उनके बीच सड़क पर कुछ उकड़ूं बैठा है, और फिर दो सीवर के गड्ढों के बीच उसके घूमने की छवि भी नजर आती है। यह भी मालूम पड़ता है कि वे सीवर में बिना किसी सहारे के चढ़ते-उतरते हैं। उनके हाथ-पैर मैल से सने हैं। उनके श्रम के साथी पास में बिखरे पड़े हैं: एक बाल्टी, कुछ छड़ें और एक जंग लगी जंजीर। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं उन असाधारण तस्वीरों की उस शृंखला की, जो सुधारक ओल्वे ने 1999 और 2000 के बीच मुंबई के सफाई कर्मचारियों की ली थीं। और आज 2025 में भी उनकी हकीकत को बयां करती वे तस्वीरें नहीं बदली हैं।

इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि एक तरफ तो हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, दूसरी तरफ मैनहोल की सफाई करते-करते कितने लोग मौत के मुंह में पहुंच चुके। वह मैनहोल, जिसमें से निकलता कार्बन मोनोऑक्साइड्स उनकी सांसों को चोक कर देता है, वह मैनहोल, जो कारखानों और मनुष्यों के कचरों और मल-मूत्रों को लेकर बहता रहता है। आजाद भारत में धर्म और जाति की दुहाई देते इस समाज को एक बार अपने आप से यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि इस मैनहोल की सफाई जैसे सबसे दुखद और सबसे बुरा काम उन मनुष्यों को क्यों करना पड़ता है, जिनको अपने जीवनयापन के लिए दुर्गंध से भरे सीवर में घुसना पड़ता है। सुलभ शौचालय के महान नायक स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक ने समाज और मनुष्य की गरिमा और स्वच्छता के लिए क्या-क्या नहीं किया, लेकिन इस देश में तो अब भी कोई न कोई सीवर को साफ करने उतरता है और फिर उससे यह आशा की जाती है कि वह सिर्फ कुछेक रुपये के बारे में सोचे, जो उसे सीवर की सफाई के बाद मिल सकते हैं।

मैनुअल स्कैवेंजिंग को 1993 में ही गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, फिर भी भारत में यह जारी है। आईआईटी, मद्रास के प्रयासों से भारत का पहला मैनहोल सफाई रोबोट भी आ चुका है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान कर रहा है। उधर मिशन गरिमा के नाम से टाटा ट्रस्ट व ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) की एक संयुक्त पहल भी शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य मुंबई के सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और मानवीय कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देते हुए उनके जीवन में गरिमा लाना है।

2015 में कोझिकोड में मैनहोल साफ करने के लिए नियुक्त सफाई कर्मचारियों और उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले एक ऑटोरिक्शा चालक की कहानी ने एमके विमल गोविंद नाम के युवा और उसके कॉलेज के दोस्तों के प्रयास से रोबोट बैंडिकूट आया। इस रोबोटिक मशीन में एचडी विजन कैमरे और गैस सेंसर हैं। मगर इतने बड़े देश में कुछेक मशीनों से क्या होगा?

'फाइबर ग्रिपर का उपयोग करके मैनहोल सफाई मशीन का डिजाइन और निर्माण' शीर्षक शोधपत्र के अनुसार, 50 फीसदी सीवर कर्मचारी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 50 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। अगर हम 2023 तक के सरकारी आंकड़ों को देखें, तो पाएंगे कि 2018-23 तक मैनहोल की सफाई करने के दौरान करीब चार सौ लोगों की मृत्यु हो गई। अभी 2025 में ही देश के विभिन्न हिस्सों से और भी सीवेज सफाई करने वालों की मृत्यु की खबर आई। 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव मल को हाथ से साफ करने, या ले जाने, निपटाने पर प्रतिबंध है। फिर भी मैनहोल में उसे साफ करने को कोई न कोई उतर ही रहा है। अगर हम फ्रांस, स्वीडन, जापान को देखें, तो पाएंगे कि मशीनों के अलावा अगर मनुष्य भी किसी सीवर लाइन के जाम होने पर मैनहोल के अंदर उतरता है, तो वह किसी जाति की उम्मीदवारी के लिए नहीं उतरता, बल्कि वह एक पेशेवर प्रशिक्षित व्यक्ति होता है।

भारत में सबसे गरीब और सबसे हाशिये पर रहने वाले व्यक्ति को बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के गंदे, बदबूदार सीवरों को खोलने या सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मैनहोल में भेजा जाता है। नतीजतन जहरीले धुएं के घुटन से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास किया जाना था। इस प्रथा से हर कोई वाकिफ है। चैतन्य तम्हाणे की कोर्ट जैसी पुरस्कार विजेता फिल्में सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा को दर्शाती हैं। इस घृणित काम के लिए मशीनों का आविष्कार किया गया है। फिर भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी है।

यों भी तो खुश हुआ जा सकता है

अल्पायां वा महत्यां वा
सेनायामिति निश्चयः।
हर्षो योधगणस्यैको
जयलक्षणमुच्यते॥

कोई सेना चाहे छोटी हो या बहुत बड़ी, विजय प्राप्त करने का असली रहस्य सिर्फ एक ही माना गया है और वह है-लड़ने वाले योद्धाओं के समूह में उमंग और जोश।
-शाङ्गर्धरपद्धतिः (1938)

प्रस्तुति : **शास्त्री कोसलेंद्रदास**

जोलांटा बर्क

सहज रूप से भी खुश हुआ जा सकता है। इसके लिए कोई कारण होना जरूरी नहीं। यही तो मनुष्य का मौलिक स्वभाव है।

खुशी महज एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण बदलावों को जन्म देती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। खुशी हमारी दूसरी भावनाओं से बहुत अलग है। यह लंबे समय से इच्छित काम को पूरा करने से जुड़ी है, जिसका नतीजा हमारी उम्मीदों से बढ़कर होता है।

खुशी अक्सर जीवन से संतुष्टि की व्यापक भावना को दर्शाती है। खुशी से एक ऐसी सच्ची मुस्कान पैदा होती है, जो अनैच्छिक होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। खुशी हमारे शरीर में भी कई तरह के बदलाव लाती है। मसलन, खुश होने पर हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और पूरा शरीर गर्म महसूस होता है। ये अनुभूतियां एड्रेनालाइन के स्राव के कारण होती हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से अधिक तैयार महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुशी यानी आनंद एक गुण भी है और अवस्था भी। यानी, जहां हममें से कुछ लोग इसे किसी सुखद परिस्थिति की वजह से अनुभव करते हैं, वहीं कुछ लोगों में अकारण भी इसी अवस्था में रहने की क्षमता होती है। कुछ शोध बताते हैं कि यह क्षमता आनुवंशिक होती है, और अनुमान है कि लगभग 30 फीसदी लोगों में 'जेनेटिक प्लास्टिसिटी' नामक क्षमता होती है। यानी वे अपने बाहरी वातावरण से असमान रूप से प्रभावित होते हैं और आनंद उत्पन्न करने की तकनीकें सीखने के बाद, उन्हें इसका अनुभव करना आसान लग सकता है। इस प्रकार, सकारात्मक अनुभवों के लिए उनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति अधिक आनंद का कारण बन सकती है। खुशी की भावना को बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन, दूसरों के साथ कुछ बांटने से हमें ज्यादा खुशी का अनुभव हो सकता है और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि दूसरों की संगति से हमारी खुशी बढ़ती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी खुशी बढ़ा सकता है।

इसलिए अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो दोस्तों के साथ डिनर पार्टी का आयोजन करें, जहां आप सब मिलकर खाना तैयार करें। दूसरों के साथ दौड़ते या टहलते समय, हमें अकेले दौड़ने या टहलने की तुलना में ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। खुशी की भावना को बढ़ाने का एक सरल तरीका यह है कि आप अपनी भावनाओं को कागज पर लिखने की आदत डालें। खुशी की अनुभूति अद्भुत है, लेकिन यह हमारे जीवन की एकल भावना नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बाकी सभी भावनाओं से घिरे होने के बावजूद भी खुश रहना सीखें।

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

राजा धर्मवर्मा की तपस्या के बाद आकाशवाणी से संस्कृत में श्लोक बोला गया, जिससे वह 'दान' तत्व को ठीक से समझ नहीं सके। इसके बाद देवर्षि नारद ने उन्हें दान के बारे में विस्तार से समझाया।

नारद ने की 'दान' तत्व की व्याख्या

धूप आने दो

राजा धर्मवर्मा ने 'दान' तत्व को समझने के लिए तपस्या की। फलस्वरूप एक आकाशवाणी हुई, जिसने दान पर एक श्लोक कहा- *द्विहेतु षडधिष्ठानं षडङ्गं च द्विपाकयुक्। चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाशं दानमुच्यते।।* अर्थात 'दान के दो हेतु, छह अधिष्ठान, छह अंग, दो फल, चार प्रकार, तीन भेद और तीन विनाश-साधन हैं।' लेकिन आकाशवाणी ने श्लोक की व्याख्या नहीं की, तो देवर्षि नारद ने धर्मवर्मा को दान तत्व का पूर्ण ज्ञान दिया।

दान के दो हेतु हैं-श्रद्धा और शक्ति। यदि श्रद्धा न हो, तो बड़े से बड़ा दान व्यर्थ है, और श्रद्धा हो तो छोटा-सा दान भी अमूल्य होता है। शरीर को कष्ट देने या धन खर्च करने से धर्म की सिद्धि नहीं होती। सच्चा धर्म, श्रद्धा से होता है। श्रद्धा ही तप, स्वर्ग, मोक्ष और संपूर्ण जगत का आधार है। श्रद्धा भी तीन प्रकार की है-सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धावाले देवताओं की, राजसी श्रद्धावाले यक्ष और राक्षसों की, और तामसी श्रद्धावाले प्रेत-पिशाचों की पूजा करते हैं। दान करते समय शक्ति का भी विचार करना चाहिए। जो धन कुटुंब-पालन से अधिक हो, वही दान के योग्य है। किसी को कष्ट देकर दिया दान, विष के समान होता है। ऐसा दान, धर्म नहीं, अधर्म है। दान के लिए आठ प्रकार की वस्तुएं वर्जित हैं-सामान्य (तुच्छ वस्तु), याचित (मांगी हुई), न्यास (धरोहर), आधि (बंधक), दान में मिली वस्तु, अन्वाहित (व्यक्ति अपने पास रखी धरोहर यदि किसी और के पास रख दे), निक्षिप्त (विश्वास पर रखा गया धन), और सान्वय सर्वस्व दान (वंशज रहते हुए सर्वस्व दान कर देना)।

● दान के छह अधिष्ठान कहे गए हैं-धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। धर्मबुद्धि से सुपात्र को दिया गया दान, धर्म-दान होता है। किसी प्रयोजन हेतु दिया दान, अर्थ-दान कहलाता है।

स्त्री, मदिरा, शिकार या जुए जैसी प्रवृत्तियों के लिए दिया दान, काम-दान है। सभा में संकोचवश दिए गए दान को लज्जा-दान कहते हैं। शुभ समाचार पाकर दिया गया दान, हर्ष-दान होता है। किसी हानि को टालने के किया दान, भय-दान कहलाता है। दान के छह अंग हैं-दाता, प्रतिग्रहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल। दाता, नीरोग, धर्मात्मा, दान की इच्छा रखने वाला हो, व्यसनरहित होना चाहिए। उसकी आजीविका अनिंदनीय व धर्मसंगत होनी चाहिए। श्रद्धा रहित, दुष्टात्मा, झूठे या आलसी व्यक्ति द्वारा किया गया दान तमोगुणी कहलाता है। दान का महत्व तभी है, जब दान लेनेवाला उसके योग्य हो। जिसका कुल, विद्या, आचार शुद्ध व सात्विक हो, जो दयालु और जितेंद्रिय हो, वही दान का अधिकारी है। जो धन या वस्तु अधर्म से अर्जित की हो, वह दान-योग्य नहीं है। दान के लिए देश भी महत्वपूर्ण है। जहां कोई वस्तु दुर्लभ हो, वहां वही वस्तु का दान योग्य है। दान में काल का भी महत्व है। उदाहरण के लिए, दुर्भिक्ष के समय अन्नदान सर्वोत्तम है, ठंड के मौसम में वस्त्रदान श्रेष्ठ है।

दान के दो फल हैं-इहलोक और परलोक। सुपात्र को दिया गया दान परलोक में फल देता है, और अपात्र को दिया दान यहीं भोगा जाता है। दान के चार प्रकार हैं-ध्रुव (कुआं, बगीचा, तालाब आदि का निर्माण), त्रिक (प्रतिदिन किया जाने वाला दान), काम्य (पुत्र, विजय, ऐश्वर्य आदि इच्छाओं के लिए किया गया दान) और नैमित्तिक भी तीन प्रकार का है-जब दान ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या या अन्य पवित्र समयों की अपेक्षा से दिया जाता है, तो उसे 'कालापेक्ष' नैमित्तिक दान कहते हैं। जब दान श्राद्ध, विवाह, यज्ञ, पर्व या अन्य धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा से किया जाता है, तब वह 'क्रियापेक्ष' कहलाता है। संस्कार, विद्या-अध्ययन, तप या विशेष गुणों की अपेक्षा से दिया जाने वाला दान 'गुणापेक्ष' कहलाता है। दान की तीन श्रेणियां हैं-उत्तम (घर, भूमि, गौ, विद्या, प्राण और सुवर्ण), मध्यम (अन्न, वस्त्र, बगीचा, वाहन आदि) और कनिष्ठ (जूता, छाता, बर्तन, दही, दीपक, लकड़ी-पत्थर आदि)।

दान का तीन कारणों से नाश हो जाता है-पश्चात्ताप, अपात्र को देना और अश्रद्धा। पश्चात्ताप से किया दान आसुर-दान कहलाता है। श्रद्धा रहित दान राक्षस-दान है। अपमान के साथ दिया दान पैशाच-दान कहलाता है। ये तीनों ही दान व्यर्थ और निष्फल माने गए हैं। इस प्रकार नारद ने राजा धर्मवर्मा को दान तत्व का माहात्म्य बताया।

अध्ययन कक्ष

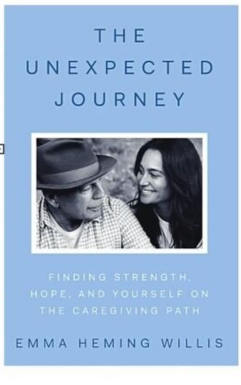

द अनएक्स्पेक्टेड जर्नी

लेखिका : एम्मा हेमिंग विलिस
प्रकाशक : द ओपन फील्ड
मूल्य : 2,599 रुपये (हार्डकवर)

एक सुपरस्टार का खुद को यों भूल जाना

हॉलीवुड के सुपरस्टार रहे ब्रूस विलिस को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वह खुद को भूल चुके हैं। उनकी देखभाल में जुटीं पत्नी एम्मा हेमिंग की यह बेस्टसेलर किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है, जो ऐसी ही स्थितियों से जूझ रहे हैं।

एम्मा हेमिंग विलिस एक मॉडल, एक पत्नी, दो बच्चों की मां, तीन बच्चों की सौतेली मां होने के साथ एक वीगन स्किन केयर कंपनी की संस्थापक और हॉलीवुड के कभी सुपरस्टार रहे अभिनेता ब्रूस विलिस की पत्नी हैं। हाल ही में उनकी पहली पुस्तक द *अनएक्स्पेक्टेड जर्नी* का विमोचन हुआ है, जो डिमेंशिया से पीड़ित उनके पति की देखभाल के अनुभवों पर केंद्रित है।

2022 में उन्हें ब्रूस की बीमारी का पता चला, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के चलते जो अब पहचानना तो दूर, बोल भी नहीं सकते। एम्मा अपनी इस बेस्टसेलर किताब में उन क्षणों का उल्लेख करती हैं, जब वह डॉक्टर से मिलने के बाद डर, उलझन और इस एहसास से स्तब्ध होकर बाहर निकली थीं कि उनकी दुनिया बिखर गई है।

ब्रूस विलिस एक बड़े, लेकिन विवादित स्टार रहे। मशहूर अभिनेत्री डेमी मूर से उनकी शादी और तलाक की अलग ही कहानी है। इसके बाद ही ब्रूस और एम्मा की कहानी शुरू हुई, जिसमें भविष्य के सुनहरे सपने शामिल थे। लेकिन अब एम्मा के लिए उन सपनों का कोई अर्थ नहीं रह गया और वह पहले से कहीं ज्यादा अकेली और अलग-थलग महसूस करने लगीं हैं। अपनी छोटी बेटियों का पालन-पोषण करते हुए उन्होंने अपने पति की देखभाल की।

द *अनएक्स्पेक्टेड जर्नी* दरअसल एक मार्गदर्शिका है, उन महिलाओं के लिए, जो अपने पति की देखभाल के दौरान किसी से मदद मांगने में खुद को दोषी समझने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी ही जिम्मेदारी है। ब्रूस विलिस का आज यही सच है कि उन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वह खुद को भूल चुके हैं।

ऐसे में उनकी पत्नी एम्मा की कहानी इसलिए पठनीय है, क्योंकि लोगों को उनके संघर्ष के बारे में जानना चाहिए और साथ ही, जो महिलाएं उनके जैसी स्थितियों से गुजर रही हैं, उनके लिए वह एक प्रेरणा है। वह लिखती हैं कि देखभाल करने वालों को स्वयं अपनी खूबियों और समस्याओं को पहचानना होगा और खुलकर मदद मांगनी होगी। अगर जरूरी हो, तो कोई सहायक नियुक्त करने में कोई बुराई नहीं है। जो देखभाल कर रहा है, उसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने सुपरस्टार पति की यह हालत देख एम्मा की भावनाएं किताब में कई बार उन पर हावी होती दिखती हैं। वह अपनी इस किताब के जरिये अपने जैसी स्थितियों वाली सभी महिलाओं से कहती हैं, 'अपने पति की इस हालत में उनकी देखभाल करना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि इस स्थिति का सामना करने वाली आप अकेली नहीं हैं। आप बहुत अच्छा कर रही हैं और समय के साथ सब अच्छा भी होता जाएगा। बस आप आगे बढ़ती रहें।'

यह किताब डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एम्मा के दर्द से उपजी है, जिसे उसने खुद से भी बड़े एक उद्देश्य में बदल दिया है। यह एक गहन व्यक्तिगत और अत्यंत करुणामयी सहायक मार्गदर्शिका है, जो देखभाल करने वालों को अपने प्रियजन के रोग से निपटने के दौरान स्वयं की देखभाल करने में मददगार साबित हो सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अभियान

amarujala.com
अमर उजाला

“जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए।
- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

Hindi@mithelesh
▪ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

तुम कितनी दूर हो,
जाने कितने लफ्ज लगते हैं
तुम तक पहुंचने के लिए...
जाने मेरी कितनी ख्वाहिशों का बोझ उठाकर,
ये तकिया रोज मेरे साथ सो जाता है...

दूर पहाड़ से, एक नदी आई है शहर में,
तुम्हारी खाली बोतल लौटाने को...

विश्व शांति का सार्थक प्रयास

झरोखा
21 सितंबर

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में आज के दिन को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति घंटी बजाई जाती है। यह घंटी जापान द्वारा भेंट की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सभी देशों और लोगों के बीच शांति, सद्भाव और सहयोग का आदर्श स्थापित करना है।

शांति दिवस यह याद दिलाता है कि हिंसा, युद्ध और संघर्ष के स्थान पर संवाद, समझदारी और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि विश्व शांति केवल युद्ध न होने की स्थिति नहीं है, बल्कि इसमें समानता, न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा भी शामिल है। इस दिन दुनियाभर में 'सीजफायर और नॉन-वायलेंस' यानी युद्धविराम और अहिंसा का आह्वान किया जाता है। यह दिन याद दिलाता है कि वैश्विक स्तर पर सहयोग और समझदारी ही स्थायी शांति की नींव रख सकती है। यह दिवस केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि हम मिलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति बिना भय और हिंसा के जीवन जी सके।

▪ ललित कौशिक, दिल्ली

जीएसटी सुधार एक संतुलित कर प्रणाली की ओर इशारा करते हैं। आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर कर बढ़ा है। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

सुधारों में विकास की नई इबारत

विकास नीति का नया रूप

चिट्ठी 1

जीएसटी सुधार केवल कर संग्रहण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक ढांचे को दीर्घकालीन मजबूती देने वाली रणनीति है। यह सवाल कराधान की जटिलता या पारदर्शिता भर का नहीं, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि भारत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह स्थापित करता है। यहीं से ये सुधार एक कर नीति से आगे बढ़कर विकास नीति का रूप लेते हैं।

वास्तविक समस्या यह रही है कि अब तक एमएसएमई क्षेत्र कर ढांचे की जटिलता, अनुपालन की ऊंची लागत और सीमित बाजार पहुंच से जूझता रहा। नतीजतन, रोजगार सृजन और निर्यात की क्षमता घटती गई। यदि यही स्थिति बनी रही तो भारत का 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य चुनौती में पड़ सकता है।

नए सुधारों का लक्ष्य कर आधार को विस्तारित करना, दरों को सरल बनाना और राजस्व के रिसाव को रोकना है। किंतु जब तक इन प्रावधानों को व्यवहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, परिणाम सीमित रहेंगे। कर भुगतान की पूरी डिजिटल व्यवस्था, छोटे उद्यमों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग ही इन सुधारों की सफलता तय करेंगे।

समाधान यही है कि सुधार को केवल राजस्व उगाही की दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि इसे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का आधार बनाया जाए। केंद्र और राज्यों को मिलकर ऐसी नीति बनानी होगी, जहां एमएसएमई को सस्ता ऋण, आसान बाजार पहुंच और कौशल विकास की वास्तविक सुविधा मिले। तभी जीएसटी सुधार भारत को कराधान की जटिलताओं से मुक्त कर आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की दिशा में सार्थक योगदान कर सकेंगे।

▪ अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

नैतिक संस्कारों का संकल्प भी जरूरी

चिट्ठी 2

श्राद्ध एक अनुष्ठान/संस्कार है, जो हिंदू धर्म में पितरों के निमित्त किया जाता है। यह उनकी आत्मा की शांति एवं नाराजगी दूर करने और उनसे आशीर्वाद के लिए किया जाता है। श्राद्ध की इतनी महत्ता है कि कोई नया वस्त्र खरीदना या कोई शुभ कार्य का आरंभ तक वर्जित है। लोग बखूबी इन नियमों का पालन करते हैं।

दूसरी ओर, जब तक बुजुर्ग जीवित रहते हैं, घर-परिवार में उनकी उपेक्षा की जाती है, तिरस्कार किया जाता है और मनपसंद खाना बनाना तो दूर, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। न किसी के पास बुजुर्गों के पास बैठने का समय होता है और न ही कोई चाहता है। उनकी नाराजगी, अकेलेपन से सरोकार तो दूर, उनसे दुर्व्यवहार तक किया जाता है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर फालतू सामान की तरह घर के किसी कोने में अकेले छोड़ दिया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हमने जीते जी उनका मान-सम्मान, ख्याल नहीं रखा तो मरने के बाद उनका मनपसंद खाना कौवों को खिलाने से कुछ नहीं होने वाला। श्राद्ध जैसे संस्कार को करना अच्छी बात है, मगर नैतिक संस्कारों को अपनाते हुए जिंदगी रहते बुजुर्गों का ख्याल रखना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, अकेला न महसूस होने देना और मान-सम्मान देना भी तो जरूरी है। बस इतना सा ही तो चाहते हैं बुजुर्ग। अगर जिंदा रहते हमने उन्हें नाराज रखा, महत्व नहीं दिया तो मरणोपरांत श्राद्ध कर प्रसन्न करना व्यर्थ है।

▪ अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

शांति प्रयासों की आवश्यकता

चिट्ठी 3

आज पूरी दुनिया और पृथ्वी परमाणु युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठी हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध लगातार तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हजारों सैनिकों की आहुति चढ़ चुकी है। दूसरी तरफ इस्राइल-हमास युद्ध में भी युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। परमाणु संपन्न देशों में चीन, रूस और उत्तर कोरिया की बागडोर तानाशाह प्रशासकों के हाथों में है, और वे विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और सनक के चलते परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। इतिहास गवाह है कि सनकी प्रशासकों से हमेशा मानवता और शांति को युद्ध और हिंसा का खतरा बना रहा है।

आजादी के बाद से ही भारत की चीन से दुश्मनी चली आ रही है। दूसरी तरफ भारत, रूस का अभिन्न मित्र है, हालांकि अमेरिका से भी उसके अच्छे संबंध हैं और वह सदैव शांति का पक्षधर रहा है। ऐसे में रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-ताइवान विवाद, उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया पर दादागिरी और अमेरिकी एवं नाटो देशों का चीन, रूस, उत्तर कोरिया का विरोध पूरे विश्व में परमाणु युद्ध की प्रस्तावना लिख रहे हैं। पाकिस्तान और खाड़ी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह मानवता और पृथ्वी के लिए बहुत विनाशक होगा।

▪ संजीव ठाकुर, रायपुर

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं
दिल्ली से श्वेता गोयल, जालंधर से राजेश कुमार चौहान, फिरोजाबाद से शिवम राठौर, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी, बरेली से सीमा गुप्ता, देहरादून से निधि मल्ल, इंदौर से अमृतलाल मारू, सूरत से कांतिलाल मांडोत, रायपुर से भावना संजीव ठाकुर, उज्जैन से हेमा हरि उपाध्याय।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

एक द्वीप पर डॉन जूलियन की 'गुड़िया'

मेक्सिको में एक ऐसा द्वीप है, जहां पेड़ों पर ढेर सारी गुड़िया हैं। लोगों को लगता है कि ये गुड़िया आपस में बातें भी करती हैं!

घूमने-फिरने के शौकीन हर तरह की जगहों पर जाना पसंद करते हैं, चाहे वो दिल को सुकून देने वाली हो या फिर डराने वाली। मेक्सिको का 'ला इस्ला डे ला म्यूनेकस द्वीप' पेड़ों से भरा हुआ है, जिन पर सैकड़ों की संख्या में गुड़िया लटकी हुई हैं। साल 2001 के बाद से इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड के नाम से पहचाना जाने लगा।

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह द्वीप पहले कभी ऐसा नहीं था। 2001 में यहां के केयर टेकर डॉन जूलियन की मृत्यु के बाद से इस स्थान की गिनती डरावनी जगहों में होने लगी। स्थानीय लोगों की मानें तो आइलैंड पर टंगी गुड़ियों में एक बच्ची की आत्मा है। उनके अनुसार, एक लड़की लाश की उतराती हुई डॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस वक्त लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी। जूलियन ने लड़की को बचाने की काफी कोशिश की, मगर वह उसको बचा नहीं सका। बच्ची की मौत के कुछ समय बाद एक गुड़िया बहती हुई आई। डॉन जूलियन ने इस गुड़िया को बच्ची समझ कर उसे वहीं पर बांधकर लटका दिया, जहां उस बच्ची की मौत हुई थी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, उस घटना के बाद डॉन जूलियन को कई गुड़िया और मिलीं। बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसने उन सभी को पेड़ों पर लटका दिया। लोगों का मानना है कि इन गुड़ियों के अंदर बच्ची की आत्मा है। अक्सर ये गुड़िया एक-दूसरे से बात करती हैं और आंखें हिलाती हैं। इसी वजह से इस आइलैंड की गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में की जाती है। हॉन्टेड होने के कारण यह जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यहां जो कोई भी आता है, उसे अकेले घूमने की इजाजत नहीं दी जाती। इस आइलैंड पर घूमने के लिए टूर गाइड का साथ में होना जरूरी है।

▪ शालू नेगी, चमोली

शब्द और स्वर पर गहन मंथन

1960 में बनी फिल्म 'दिल अपना और प्रीत पराई' का गाना 'अजीब दास्तां है ये' को लिखने के बाद शैलेंद्र ने सबसे पहले लता मंगेशकर को पढ़वाया था।
▪ ज्योतिका मिश्रा, नोएडा

स्मृति शेष

असमिया संगीत को दिया नया मुकाम

उत्तर-पूर्व के रॉकस्टार कहे जाने वाले जुबिन गर्ग (जुबिन बोर्थाकुर) गुजरी 19 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने असमिया संगीत को नई ऊंचाइयां दीं। मेघालय के तुरा में 18 नवंबर, 1972 को जन्मे जुबिन 12 वाद्य यंत्रों में पारंगत थे। उन्होंने असमिया एल्बम 'अनामिका' से डेब्यू किया और असमिया, बंगाली, हिंदी, नेपाली एवं बोडो आदि करीब 40 भाषाओं में 38 हजार गाने रिकॉर्ड कराए।

'मिशन चाइना' जैसी असमिया फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया, जो क्षेत्रीय सिनेमा को बॉलीवुड स्तर पर ले गया। बॉलीवुड में उनका प्रवेश 2006 में फिल्म 'गैंगस्टर' के सुपरहिट गाने 'या अली' से हुआ, जिसने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। इसके बाद 'दिल तू ही बता' (कृष 3) और 'जाने क्या चाहे मन' (प्यार के साइड इफेक्ट्स) जैसे गानों ने उन्हें पार्श्व गायक के रूप में स्थापित कर दिया। 2021 में उन्हें 'तोमार खोला हवा' के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक चुना गया और 2006 में ग्लोबल इंडियन फिल्म अवॉर्ड से नवाजा गया था।

▪ रजा मोहम्मद, लखनऊ

कब पूरी होंगी उत्तराखंड की आकांक्षाएं

उत्तराखंड की स्थापना कुछ महान आकांक्षाओं के साथ हुई थी। उम्मीद थी कि नया राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के साथ अपने लोगों का भविष्य बेहतर बनाएगा, लेकिन 25 वर्षों बाद भी यह सपना अधूरा है।

उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर, 2000 को हुई थी। इसकी स्थापना के कुछ ही समय बाद मुझे राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित हिल स्टेशन मसूरी में एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। मेरा जन्म और पालन-पोषण देहरादून के बाहरी इलाके में हुआ था, जो नीचे घाटी में बसा एक शहर है। मसूरी पहुंचने पर मैं नजदीकी सार्वजनिक कॉल बूथ (तब मोबाइल फोन नहीं थे) गया और नैनीताल में रहने वाले इतिहासकार शेखर पाठक को फोन किया। जब उन्होंने फोन उठाया तो मैंने कहा- "मैं अपने प्रदेश से बोल रहा हूं।" यह वाक्य मेरे भीतर उमड़े गर्व और आत्मीयता का प्रतीक था।

हालांकि उस समय मेरा स्थायी ठिकाना बंगलूरू था, फिर भी मेरा गहरा जुड़ाव उस क्षेत्र से बना हुआ था, जहां मैं बड़ा हुआ और अपना पहला शोध कार्य किया। मैंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में राज्य निर्माण के लिए चल रहे आंदोलन पर गहरी नजर रखी थी और उसकी सफलता का जश्न मनाया था। जिस प्रकार 1971 में पूर्ण राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की स्थापना ने वहां के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग खोला, वैसे ही उम्मीद थी कि उत्तराखंड के लोग भी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं को साझा करने वाले नेताओं द्वारा संचालित राज्य से लाभान्वित होंगे। पहाड़ों की भौगोलिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को वही नेता समझ सकते थे, जो यहां के लोगों के बारे में नजदीक से जानते हों।

उत्सव या मायूसी : कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इन 25 वर्षों में कांग्रेस दस साल और भारतीय जनता पार्टी पंद्रह साल सत्ता में रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार बड़े पैमाने पर जश्न का आयोजन करेगी, झंडा फहराएगी, रैलियां करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जश्न मनाने जैसा बहुत कम है। दोनों दलों की सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कोई ठोस काम नहीं किया। आज वहां पलायन और बेरोजगारी की पीड़ा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। 2017 से सत्ता में रही भाजपा ने विकास के मुद्दों के बजाय हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया, उनके भीतर डर का माहौल पैदा किया गया। यह उस क्षेत्र की परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, जहां पहले कभी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ था। गणराज्य के अन्य राज्यों की तरह यहां भी हिंदुत्व उस नशे की तरह है, जिसे जनता को इसलिए परोसा जाता है, क्योंकि राजनेता अपने मतदाताओं को वर्तमान और भविष्य में गरिमापूर्ण एवं सुरक्षित जीवन देने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।

विकास के नाम पर विध्वंस : उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो हो रहा है, वह अधिकतर विध्वंस साबित हुआ है। खराब तरीके से बनी सड़कें, गलत ढंग से सोची-समझी बांध परियोजनाएं और विशाल निर्माण कार्य पहाड़ों के लिए अभिशाप बन गए। इनमें सबसे खतरनाक है 'चार धाम हाईवे' परियोजना। यह धार्मिक आस्था के नाम पर शुरू की गई, लेकिन इसके कारण पहाड़ की संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई। दुखद यह है कि अनगिनत वैज्ञानिक साक्ष्यों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना को रोकने के बजाय आगे बढ़ने की इजाजत दी।

जंगलों का क्षरण : सन 2000 के बाद से अब तक उत्तराखंड ने लगभग 50,000 हेक्टेयर प्राकृतिक वन 'विकास परियोजनाओं', जैसे- हाईवे, बांध, खदानें, सरकारी टाउनशिप आदि के नाम पर खो दिए हैं। यदि यह माना जाए कि एक हेक्टेयर वन में औसतन 3,000 पेड़ होते हैं तो 25 वर्षों में लगभग 15 करोड़ पेड़ काट दिए गए। इस विनाश की आर्थिक और पर्यावरणीय लागत अकल्पनीय है।

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

आपदाएं प्राकृतिक या मानव जनित : हिमालय सुंदर जरूर है, लेकिन यहां बेहद नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह क्षेत्र भूकंप-प्रवण है और यहां घना वन केवल स्थानीय गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि मृदा कटाव और बाढ़ से बचाव के लिए भी आवश्यक है। पिछले वर्षों में हमने चमोली की आपदा, केदारनाथ की त्रासदी और हाल ही की धराली जैसी घटनाएं देखी हैं। भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं से मौतें और आर्थिक क्षति बढ़ी है, लेकिन नेताओं और मीडिया द्वारा इन्हें अक्सर 'प्राकृतिक आपदा' कहा जाता है, जबकि सच यह है कि इनका बड़ा हिस्सा मानव जनित है। राजनेताओं-ठेकेदारों-अफसरों की मिलीभगत से बेतहाशा सड़कें, बांध और रिसॉर्ट बनाने की मंजूरी दी जाती है। संवेदनशील पर्यावरण पर ऐसे निर्माण वर्षा के समय और भी खतरनाक साबित होते हैं। परिणामस्वरूप, जान-माल और आजीविका की भारी क्षति होती है।

नदियों पर खतरा : आज की सबसे विवादास्पद योजनाओं में एक है- देहरादून की बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। यह परियोजना लगभग 6,000 करोड़ रुपये की है और असली मकसद यह है कि मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटक जल्दी मसूरी पहुंच सकें। इस योजना से हजारों मकान ढहेंगे, मिट्टी का भारी कटाव होगा और नदियों के प्राकृतिक जल मार्ग अवरुद्ध होंगे। नागरिक समूहों का कहना है कि यह परियोजना वास्तव में केवल ठेकेदारों, कार निर्माताओं और राजनेताओं को लाभ पहुंचाएगी। आर्किटेक्ट भारती जैन चेतावनी देती हैं कि लाखों घनमीटर मिट्टी नदियों से निकाली जाएगी, लेकिन इसके सुरक्षित निस्तारण की कोई योजना नहीं है। यदि यह मिट्टी नदियों के किनारे डाली गई तो नदी-तल ऊपर उठ जाएगा और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। यदि इसे कंक्रीट से पाटा गया तो भूजल पुनर्भरण रुक जाएगा। उनके शब्दों में, "ये नदियां सिर्फ मौसमी नाले नहीं हैं, ये हमारी भूजल-रेखा को पुनर्भरण करने वाली नसें हैं। इन्हें रोककर हम बरसात में बाढ़ और गर्मियों में सूखा आमंत्रित करेंगे।"

नागरिकों की असहमति : देहरादून में हाल ही किए गए एक सर्वेक्षण ने इस परियोजना के प्रति नागरिकों की गहरी और बढ़ती असंतुष्टि को उजागर किया। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की तरह यह परियोजना भी स्थानीय लोगों से अधिक पर्यटकों की सेवा करेगी। सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों अतिरिक्त गाड़ियां मसूरी में आएंगी तो उस भीड़ को कैसे संभाला जाएगा? क्या सरकार पहाड़ की ढलानों पर दस मंजिला पार्किंग भवन बनाने की योजना बना रही है?

हाल की त्रासदी और सीख : इस बार देहरादून में भारी वर्षा की खबरें आईं। सड़कें, पुल, दुकानें और घर बह गए। घाटी के कई लोगों ने जान गंवाई। विडंबना यह है कि रिस्पना और बिंदाल (वही दो नदियां, जिन पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाले हैं) खतरे के स्तर से ऊपर बह रही थीं। क्या अब भी अधिकारी इन गलत परियोजनाओं पर पुनर्विचार करेंगे या इसे एक और 'प्राकृतिक आपदा' कहकर टाल दिया जाएगा?

पर्यटन की पुनर्परिभाषा : उत्तराखंड को सबसे अच्छी तरह जानने वाले इतिहासकार शेखर पाठक ने बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी की है कि हमें पर्यटन को तीर्थ यात्रा जैसा बनाना चाहिए, जो प्रकृति और मानव समुदाय का सम्मान करने वाला हो। लेकिन वर्तमान सरकार तीर्थ यात्रा को पर्यटन जैसा बनाना चाहती है- ज्यादा शोरगुल और प्रकृति तथा समाज को नष्ट करने वाला। पर्यटन का यह मॉडल टिकाऊ नहीं है।

भविष्य की प्राथमिकताएं : राज्य को 25 वर्ष पूरे होने पर दो प्राथमिकताओं पर गंभीरता से काम करना होगा-

मानव संसाधन में निवेश - बेहतर, सुरक्षित और सस्ते स्कूलों एवं अस्पतालों का संचालन करना। युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना। पलायन की समस्या को रोकना।

प्राकृतिक संसाधन की रक्षा - जल, जंगल और जमीन को बचाना। टिकाऊ विकास के मॉडल पर काम करना। अनियंत्रित निर्माण के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाना।

उत्तराखंड की स्थापना कुछ महान आकांक्षाओं के साथ हुई थी। उम्मीद थी कि नया राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के साथ अपने लोगों का भविष्य बेहतर बनाएगा, लेकिन 25 वर्षों बाद भी यह सपना अधूरा है।

नंद पंडित को याद करते हुए नवरात्र

नवरात्र पर्व केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि गहन शास्त्रीय चिंतन और परंपरा का प्रतीक भी है। इसकी पूजा-विधि, व्रत-नियम और दुर्गोत्सव की मर्यादाओं को पहली बार शास्त्र सम्मत ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य सत्रहवीं शताब्दी के आचार्य विनायक पंडित ने किया था, जो नंद पंडित नाम से प्रसिद्ध थे। भारत रत्न डॉ. पांडुरंग वामन काणे के मतानुसार, नंद पंडित के आश्रयदाता साधारणपुर (सहारनपुर) के महाराजाधिराज परमानंद थे।

शास्त्री कोसलेन्द्रदास

खुला आकाश

नंद पंडित ने शास्त्रीय विवेचन से सिद्ध किया कि नवरात्र शब्द काल का नहीं, बल्कि कर्म का वाचक है। यहां 'रात्रि' का आशय दिन-रात से नहीं, बल्कि 'तिथि' से है। इस प्रकार नवरात्र का वास्तविक अर्थ है- विशिष्ट पूजा के साथ नौ तिथियों में किए जाने वाले व्रत।

1550 ईसवी में जन्मे राम पंडित के पुत्र नंद पंडित काशी में निवास करते थे। उनका लेखन काल 1580 से 1630 तक पचास वर्षों का रहा। नंद पंडित की विष्णु स्मृति पर लिखी महत्वपूर्ण टीका का समय 1622 ईसवी है। नंद पंडित के ग्रंथों की सूची उन्होंने स्वयं अपने एक ग्रंथ 'श्राद्धकल्पलता' में दी है, जिनमें अठारह ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में दत्तक, श्राद्ध और संस्कारों पर विद्वत्तापूर्ण चर्चा हुई है। इनमें 'नवरात्र-प्रदीप' भी एक महत्वपूर्ण कृति है।

'नवरात्र-प्रदीप' में नंद पंडित ने नवरात्र शब्द की व्याख्या करते हुए विद्यमान मतभेदों को स्पष्ट किया। कुछ विद्वानों के अनुसार, नवरात्र का आशय केवल नौ दिन और नौ रातों से था, वहीं कुछ इसे तिथि-वृद्धि होने से दस दिन तक भी मानते थे। नंद पंडित ने शास्त्रीय विवेचन से सिद्ध किया कि नवरात्र शब्द काल का नहीं, बल्कि कर्म का वाचक है। यहां 'रात्रि' का आशय दिन-रात से नहीं, बल्कि 'तिथि' से है। इस प्रकार नवरात्र का वास्तविक अर्थ है- विशिष्ट पूजा के साथ नौ तिथियों में किए जाने वाले व्रत।

नवरात्र-प्रदीप में उन्होंने व्रती के नियम, देवी दुर्गा की पूजा-विधि एवं दुर्गा सप्तशती के पाठ-विधान का व्यवस्थित वर्णन किया। नवरात्र की पूजा-पद्धति को उन्होंने स्पष्ट और अनुशासित स्वरूप दिया। पूर्वी भारत में प्रचलित दुर्गोत्सव की शास्त्रीय मर्यादाओं की स्थापना का श्रेय नंद पंडित को ही जाता है। नवरात्र-प्रदीप का पहली बार प्रकाशन 1928 ईसवी में हुआ, जिसका संपादन गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, वाराणसी के पंडित वैद्यनाथ शास्त्री ने किया था। इसकी विद्वत्तापूर्ण भूमिका महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने लिखी थी। नंद पंडित का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे गहन शास्त्रीय अध्ययन और तर्कसंगत व्याख्या से भारतीय परंपरा को नए आलोक में प्रस्तुत किया जा सकता है। नवरात्र को केवल आस्था का पर्व न मानकर उन्होंने इसे शास्त्र सम्मत साधना का अंग बनाया। यही कारण है कि वह आज भी धर्मशास्त्र परंपरा में युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

ब्लूचिस्तान : पाक-चीन को झटका

पाकिस्तान का ब्लूचिस्तान खुली हवा में सांस लेना चाहता है। वो आजादी के लिए छटपटा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ब्लूचिस्तान में पाकिस्तान के हुकमरानों के अत्याचार की दास्तां बहुत लम्बी है। यह भी वास्तविकता है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ब्लूचिस्तान पर नियंत्रण खो दिया है। पाकिस्तान सच्चाई को छिपाता है और वहां के लोगों की आवाज दबाने की पूरी कोशिश करता है। पाकिस्तान टूट के कगार पर है। यह इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है कि भारत विभाजन के बाद स्टेट ऑफ क्लात यानि ब्लूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र रहा। ब्लूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होना ही नहीं चाहता था और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी आजाद ब्लूचिस्तान के समर्थक थे। 1947 में बुगती नवाब और क्लात के खान के साथ जो संबंध थे वो कभी बदल गए थे। तब जिन्ना ने ब्लूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने ब्लूचिस्तान का जमकर शोषण किया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से आता है लेकिन यह प्रांत अभी भी पिछड़ा हुआ है। आजादी की मांग कर रही ब्लूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना और आईएसआई की नाक में दम कर रखा है।

ब्लूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानि बीएलए को लेकर पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की तिकड़ी ने मिलकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अमेरिका ने इस मामले में अपना रंग बदल लिया है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र में ब्लूचिस्तान से जुड़े दो संगठनों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। पाकिस्तान में बीएलए और उसकी मिलिट्री विंग मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सैक्शन 1267 के तहत आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में अमेरिका ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि ये दोनों ब्लूच संगठन अलकायदा या फिर आईएसआईएस से जुड़े हैं। दरअसल अमेरिका ने पिछले महीने बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा था कि मजीद ब्रिगेड, बीएलए के पिछले विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) पदनाम का एक उपनाम था। उस समय अमेरिका के इस कदम को एक संतुलन वाले कदम के रूप में देखा गया था, क्योंकि अमेरिका ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा समूह करार दिया था।

ब्लूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानि बीएलए को लेकर पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की तिकड़ी ने मिलकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अमेरिका ने इस मामले में अपना रंग बदल लिया है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र में ब्लूचिस्तान से जुड़े दो संगठनों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। पाकिस्तान में बीएलए और उसकी मिलिट्री विंग मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सैक्शन 1267 के तहत आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव रखा था।

मगर यूएन में तकनीकी आधार पर अमेरिका ने ब्लूच संगठनों पर बैन लगाने से साफ इन्कार कर दिया। पाकिस्तान, वर्तमान में 15 देशों की सुरक्षा परिषद में 2025-26 के कार्यकाल के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है और चीन स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका की उस घोषणा से उत्साहित होकर पाकिस्तान और चीन अपना निजी फायदा देखते हुए बीएलए मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करना चाहते थे लेकिन उनकी साजिश नाकाम रही। मगर संयुक्त राष्ट्र में तकनीकी आधार पर अमेरिका ने ब्लोच संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से साफ इंकार कर दिया। दरअसल पाकिस्तान और चीन अपना निजी फायदा देखते हुए इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत जब भी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाता है तो चीन हमेशा उस पर वीटो लगाकर रोक देता रहा है।

ब्लूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि वे आतंकवादी नहीं हैं बल्कि मातृभूमि के रक्षक हैं। बीएलए के लड़ाकों ने इस साल मई के महीने में पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रैस ट्रेन को हाईजैक कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। इसके अलावा वहां आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। कौन नहीं जानता कि यह हमले पाकिस्तान की सेना के दमन के खिलाफ हैं। न केवल ब्लूच आंदोलन जोर पकड़ रहा है, बल्कि पश्तून भी अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। फ्री ब्लूचिस्तान मूवमेंट (एफबीएम) के नेता हिर्बेयर मरी ने पश्तूनों के साथ मिलकर काम करने और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय गठबंधन बनाने पर सहमति जताई है। फ्री ब्लूचिस्तान मूवमेंट ईरान के कब्जे वाले ब्लूचिस्तान में भी एक्टिव है और ब्लूच लोगों को उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने विभाजित क्षेत्र को एकीकृत कर लेंगे। फ्री ब्लूचिस्तान मूवमेंट ने कहा है कि ब्लूच सात दशकों से अधिक समय से युद्ध की स्थिति में है। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना ब्लूच नागरिकों को अंधाधुंध तरीके से निशाना बना रही है जिससे गंभीर मानवीय संकट पैदा हो रहा है। हजारों ब्लूच लोगों को जबरन गायब कर दिया गया और लाखों लोग अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हो गए हैं।

पाकिस्तान बनने के बाद से ही ब्लूचिस्तान से विद्रोह की आवाज उठती रही है लेकिन ब्लूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद स्थिति भी जटिल हो गई है। पाकिस्तान में ब्लूचिस्तान का ग्वादर कोट चीन को दे दिया है और स्थानीय ब्लूच उसका विरोध कर रहे हैं। ब्लूचिस्तान 68 बिलियन डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। अगर ब्लूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला जाता है तो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ब्लूचिस्तान के लोग अब यह मान बैठे हैं कि उनका भविष्य पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। वहां पाकिस्तान की नैतिक, मनोवैज्ञानिक पराजय हो चुकी है। फिलहाल पाकिस्तान और चीन को करारा झटका मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को ब्लूचिस्तान की स्थिति को गम्भीरता से पहचानना होगा और पाकिस्तान के दमन को रोकने के लिए अपनी चुप्पी तोड़नी होगी।

और नशे से दूर रहकर ही बनेगा हरियाणा...

धूम्रपान पर रोक के लिए हरियाणा सरकार ने की सराहनीय पहल है,
और एक वर्ष तक गुटखा, पान, तंबाकू सभी की बिक्री पर सवाल है,
जागरूक आवाम के साथ ही यह मुहिम कर पाएगी कमाल है,
और नशे से दूर रहकर ही बनेगा हरियाणा निरोगी और खुशहाल है !!

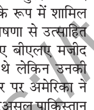
गीता पाढा

कैसे नो-बॉल पर आउट हुए कैप्टन

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'जरा-जरा सी इतनी सी बात पर
हवा यूं भड़क जाती है
तूफानों में भला दीयों की फरियाद
कब सुनी जाती है'

इन दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा नेतृत्व से बेहद ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके मन में तो जैसे बस यही चल रहा है कि 'मतलब निकल गया तो जानते नहीं।' भाजपा को लगने लगा था कि 'कैप्टन उनके लिए बस एक चूके कारतूस रह गए हैं, जो शायद उसके अब किसी काम नहीं आने वाले।' सो भाजपा ने उनसे तमाम बड़े-बड़े वादे कर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कैप्टन करीबियों का दर्द है कि 'कम से कम इन्हें किसी राज्य का गवर्नर तो बनाया ही जा सकता था।' अपनी निरंतर उपेक्षा से आहत कैप्टन ने एक बार मन बना ही लिया था कि 'वे अपने पुराने घर कांग्रेस में लौट जाएंगे', वे सोनिया गांधी से मिल कर उनके संग चाय भी पी आए और उनके साथ अपने मन की बातें भी शेयर कर ली। एक तरह से कैप्टन ने सोनिया को इशारा दे दिया था कि 'वे फिर से कांग्रेस ज्वॉइन करें या नहीं, पर परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर कांग्रेस की मदद करते रहेंगे।' जब इस बात की भनक केंद्र सरकार को लगी तो कैप्टन व उनके परिवार पर ईडी की जांच तेज कर दी गई।

मामला कैप्टन के पुत्र की विदेशों में यानी फ्रांस, दुबई और स्विट्जरलैंड में स्थित संपत्तियों से जुड़ा है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि 'ईडी इन संपत्तियों की जांच कर सकती है।' वैसे भी पंजाब भाजपा की एक दुखती रग है। वह बहुत कोशिशों के बाद भी वहां अपने पैर नहीं जमा पा रही। कभी उसे शिरोमणि अकाली दल का सहारा था, अब वह आम आदमी पार्टी और कैप्टन के पुराने भरोसेमंदों के सहारे वहां पार्टी की नैया पार लगाना चाहती है। सो कांग्रेसी नेता व कैप्टन के पुराने वफादार मनीश तिवारी भाजपा की स्वभाविक पंसद बन कर उभरे हैं। वे चंडीगढ़ के सांसद हैं और एक तरह से कांग्रेस के बागी गुट के एक अहम झंडाबरदार भी माने जाते हैं। जाति से ब्राह्मण हैं और पंजाब के पुराने नेताओं में शुमार होते हैं। सो, भाजपा ने मनीश तिवारी पर पहले से डोरे डालने शुरू कर दिए थे, मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में उन्हें शामिल किया था, उनके नाम को लेकर राहुल गांधी के विरोध को किनारे रखते हुए।

लद्दाख में किसकी जमेगी धाक?

लद्दाख का पहाड़ी रेगिस्तान पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी अधिकारों के रक्षा के मुद्दे पर उबल रहा है। लेह और कारगिल की शीर्ष संस्था ने जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, जन दबावों में आकर अपनी संस्था से राजनीतिक चेहरों को हटाने का फैसला लिया था। इस फैसले की गाज दो बड़े नेताओं पर भी गिरी है, इनमें से एक हैं थुप्स्तान छेवांग जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनावों में पहले न सिर्फ बीजेपी छोड़ दी थी बल्कि अपनी लोकसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। ये पूर्व में दो बार के भाजपा सांसद रह चुके थे।

इनके अलावा यहां के कांग्रेसी दिग्गज रिगजिन जोरा को भी इस शीर्ष संस्था से इस्तीफा देना पड़ा था। पर थुप्स्तान छेवांग की संघ की पृष्ठभूमि और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अपनी निकटता वे चाह कर भी नहीं छुपा पा रहे। वहीं इनको चुनौती मिल रही है एक गैर राजनैतिक व्यक्ति, इंजीनियर व शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से जो यहां के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन कर उभरे हैं। यह कोई दूसरी बार है जब वांगचुक एक अनिअनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे है। जाहिरा तौर पर वे केंद्र सरकार की आंखों की किरकिरी भी बने हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक अजीब शर्त रख कर थुप्स्तान को फिर से इस शीर्ष संस्था में शामिल करवा दिया है। पर स्थानीय लोग इसे सरकार के दबाव की नीति मान रहे हैं, यह बात थुप्स्तान को भी भटका रही है कि 'वे लद्दाख के मुद्दे पर निर्भीकता से कायम रहेंगे या केंद्र की लाइन लेने पर बाध्य होंगे', जो भी हो यह बात थुप्स्तान की अपनी स्वच्छ सार्वजनिक छवि के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

आप की परेशानी का सबब मेहराज

मेहराज मलिक का सियासी सफर कई अनसुलझी गुत्थियों से भरा है, पर एक दिन अचानक उन्होंने सबको विस्मित करते जम्मू-कश्मीर में आप का झाड़ू चला दिया और विधानसभा चुनाव जीत गए तो गद्गद् भाव से आम आदमी पार्टी ने भी इन्हें यकबयक अपनी जम्मू-कश्मीर इकाई का प्रमुख बना दिया। हैरत की बात तो यह कि मलिक के इस सियासी अभ्युदय से पहले उस प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जानने वाले लोग भी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। मलिक का सियासी सफर भी कई मायनों में दिलचस्प है, वे सबसे पहले चर्चा में तब आए जब उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में एक अप्रत्याशित जीत दर्ज करा ली। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी छवि एक बेबाक और आक्रामक जनप्रतिनिधि की बनाई। वे अक्सर जनता के मुद्दों को लेकर अधिकारियों से सीधा टकराव ले लेते थे, उनकी इसी अदा ने उन्हें लोगों और मीडिया में और भी लोकप्रिय बना दिया। पर उनकी यही अतिशय आक्रामकता तब हत्थे चढ़ गई जब उन्होंने अपने गृह जनपद डोडा के डीसी पर जन कल्याण परियोजनाओं को लागू न करने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अपशब्दों की बारिश कर दी। तब जाकर उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद ही सरकार व प्रशासन ने उनके अतीत को खंगालना शुरू कर दिया, इसी जांच के दौरान उनके कुछ पुराने वीडियो मिले जिनमें वे आतंकवादियों के समर्थन में विवादास्पद भाषण देते दिखे, सरकार फौरन हरकत में आई, मलिक को और नापने की तैयारियां शुरू हो गई, इस जांच ने आम आदमी पार्टी की पेशानियों पर बल ला दिए हैं, अब मलिक न तो उनसे निगलते बन रहे हैं और न ही उगलते।

बिहार में हाथ नहीं मलेगी कांग्रेस

क्या बिहार चुनाव राहुल गांधी का सियासी तारणहार बन सकता है? जिस तरह बिहारी जनता ने खास कर वहां के युवाओं ने राहुल गांधी की हालिया 'वोटर अधिकार यात्रा' को हाथों-हाथ लिया उससे नेता प्रतिपक्ष के हौसले बम-बम हैं। राहुल बिहार चुनाव से एक नई कांग्रेस के अभ्युदय की आहट देख रहे हैं। सो इस बार वहां के कांग्रेसी प्रत्याशी को टिकट पाने के लिए कई-कई स्क्रीनिंग के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सबसे अहम रिपोर्ट तो राहुल अपने भरोसेमंद सुनील कानूगोलू की मान रहे हैं, इसके बाद राज्य कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की भी अपनी सिफारिशें हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अनुमोदन है। यानी इस बार राहुल सिर्फ अजय माकन के नेतृत्व वाली स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वैसे अब तक कांग्रेस महागठबंधन में 70 सीटों की ही डिमांड कर रही है, पर सूत्रों का मानना है कि इस दफे कांग्रेस को 55 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। क्योंकि पिछली बार 70 सीट लेकर भी कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक ही जीत पाए थे। वैसे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राजेश राम ने अपनी ओर से संभावित उम्मीदवारों की एक तैयार सूची दिल्ली भेज दी है, जिसमें एक सीट पर तीन दावेदारों के नाम भेजे गए हैं, फिलहाल यह लिस्ट राहुल गांधी और केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के पास है। इससे पहले राहुल पप्पू यादव के लिए भी सीमांचल की 5-7 सीटों की वकालत कर रहे थे, पर पिछले दिनों पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर जिस तरह पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर हंस-हंस कर पीएम मोदी से बतियाते देखा गया, इस बात ने निश्चय ही राहुल के मन में भी संशय पैदा किया होगा कि 'कहीं भाजपा पप्पू पर डोरे तो नहीं डाल रही?'

...और अंत में

सियासी खेल में कभी-कभी अपना प्यादा भी बिसात पर राजा के समक्ष शह-मात के उलझनों को दुरूह बना देता है, बिहार में संभवत: प्रशांत किशोर के मामले में भी यही हो रहा है। भाजपा का अपना एक जनमत सर्वेक्षण बता रहा है कि पीके लगातार राज्य के अपने सजातीय ब्राह्मण वोटर समेत अन्य अगड़े मसलन भूमिहार, ठाकुर व कायस्थ वोटरों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं, पर वे चाह कर भी मुस्लिम, दलित, ओबीसी व ईबीसी वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद नहीं कर पा रहे। जिन वोटरों को वे गोलबंद कर पा रहे हैं वे तो भाजपा के अपने ही परंपरागत वोटर हैं, इसीलिए पीके से गुजारिश की गई है कि 'वे अपनी बदली रणनीति पर काम करें', कहीं घर को ही न आग लग जाए, घर के चिराग से।

'एनसीडी' बीमारियां जो दिखती नहीं, लेकिन मारती जरूर हैं : डब्ल्यूएचओ

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आजकल जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि न किसी के पास खाने का वक्त है, न सोने की फिक्र और न अपनों संग बैठकर दो पल बिताने की सुध! लोग दिन भर की थकान को कोल्ड ड्रिंक से धोते हैं, स्ट्रेस को सिगरेट के छल्लों में उड़ाते हैं या शराब में घोल कर पी जाते हैं। ऊपर से काम का प्रेशर, सोशल मीडिया की दौड़ और रिश्तों की उलझनें। इसी का नतीजा है कि कुछ ऐसी बीमारियां शरीर में प्रवेश कर रही हैं जिनके लक्षण प्रत्यक्ष तौर पर दिखते नहीं हैं। बीमारियां जो दिखती नहीं हैं लेकिन भीतर ही भीतर शरीर को खोखला करती रहती हैं। इन्हें ही कहा जाता है एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) यानी गैर संचारी रोग।

एनसीडी की फेहरिस्त में दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर और मानसिक तनाव शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताजा रिपोर्ट इसकी गंभीरता का आभास कराती है। संगठन ने कहा है कि इन बीमारियों से लड़ाई में दुनियाभर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मतलब साफ है—खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और गहराता जा रहा है। 'सेविंग लाइव्स, स्पेंडिंग लेस,' यानी 'जिंदगियां बचाइए, ज्यादा पैसा मत खर्च कीजिए' शीर्षक से रिपोर्ट तैयार की गई है। और यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। ये बताती है कि इन बीमारियों से लड़ने में भारी-भरकम बजट नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी सी समझदारी भरा निवेश पर्याप्त है।

रिपोर्ट कहती है कि अगर हर देश सिर्फ 3 डॉलर (यानि लगभग 250 रुपए) प्रति व्यक्ति हर साल इन बीमारियों की रोकथाम और इलाज पर खर्च करे, तो 2030 तक 12 मिलियन (1.2 करोड़) लोगों की जान बचाई जा सकती है। यानि कह सकते हैं कि सिर्फ एक पिज्जा के बराबर पैसे में एक जान! पर दिक्कत ये है कि बहुत से देश अब इस लड़ाई में ढीले पड़ गए हैं। 2010 से 2019 के बीच अधिकतर देशों ने इन बीमारियों से होने वाली मौतों को कुछ हद तक कम किया था, लेकिन अब हालात फिर बिगड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो हालात पहले से भी खराब हो रहे हैं।

सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि ये बीमारियां गरीब और मिडिल क्लास देशों में ज्यादा कहर ढा रही हैं। हर साल लगभग 75 फीसदी मौतें ऐसे देशों में होती हैं, जहां इलाज महंगा है और जागरूकता की कमी है।

गड़बड़ लाइफस्टाइल से एनसीडी में इजाफा

डब्ल्यूएचओ उन कारणों को भी बताता है जिनकी वजह से एनसीडी में इजाफा होता है और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ है—ज्यादा जंक फूड, कम कसरत, नींद की कमी और स्ट्रेस भरी जिंदगी इसका कारण है। डब्ल्यूएचओ साफ कहता है कि इन कंपनियों का असर नीति बनाने वालों पर भी पड़ता है, जो जरूरी कानूनों को पास नहीं होने देते।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, गैर-संचारी रोग और मेंटल हेल्थ सिचुएशन साइलेंट किलर हैं, जो हमारे जीवन और इनोवेशन को छीन रहे हैं। हमारे पास जीवन बचाने और पीड़ा कम करने के साधन हैं। डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और मोल्दोवा जैसे देश इस दिशा में अग्रणी हैं, जबकि अन्य देश पीछे छूट रहे हैं। एनसीडी के विरुद्ध लड़ाई में निवेश करना केवल एक चतुर अर्थशास्त्र नहीं है—यह समृद्ध समाज की आवश्यकता है।

डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर सरकारें थोड़ी समझदारी दिखाएं और 'बेस्ट बाइज' (अच्छे खरीद) कॉन्सेप्ट को अपनाएं तो बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जाए, बच्चों को जंक फूड के विज्ञापन से बचाया जाए, शराब की बिक्री पर कंट्रोल किया जाए, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया जाए—तो हम इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

दैनिक समाचार पत्रों को पढ़ना ही लोगों की पसंद

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f /kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

पिछले साल की बात है हांगकांग से मेरे सहपाठी का मुझे फोन आया कि किरण मुझे पंजाब केसरी चाहिए तो मैंने उसे कहा कि रोज भेजना महंगा पड़ेगा तो तुम ई-पेपर पढ़ लिया करो, उसका जवाब था कि जो आनंद अखबार को पढ़कर आता है वो ई-पेपर में नहीं, न किसी सोशल मीडिया पर। ऐसे ही लंदन से मेरे जानने वालों का फोन था कि क्या उन्हें अखबार रोज मिल सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी उटपटांग खबरें दिखती हैं, जो मालूम ही नहीं पड़ता सच है या झूठ। समझ आ रहा था कि कहीं के भी निवासी हों वो अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया देखकर एक महिला गलत सेहत के नुस्खों का पालन करते आईसीयू में पहुंच गई। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ रहे हैं।

इस बार ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (एबीसी) ने जनवरी-जून 2025 की ऑडिट अवधि के लिए प्रमाणित प्रसार संख्याएं जारी कीं। एबीसी के महासचिव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दैनिक समाचार पत्रों के प्रसार से अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रिंट मीडिया उद्योग के लिए एक स्वस्थ वृद्धि को दर्शाता है। अखबारों की प्रसार संख्या आए दिन बढ़ रही है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें ज्यादा हैं इसलिए लोग भरोसेमंद खबरों के लिए अखबार पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। यही नहीं अखबार में समाचार पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ मिलता है। सिर्फ हेडलाइन नहीं। अखबार राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक खबरें देने के साथ शहर और मौहल्ले की खबरें भी देता है जो ऑनलाइन नहीं मिलतीं। यही नहीं अखबार पढ़ने से शब्दावली अच्छी होती है। रोजगार और अवसर- विज्ञापन, नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। सही और ताजी जानकारी मिलती है। सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है।

यह सच है कि आज की दुनिया में जिस तेजी से बदलाव हो रहा है वह पहले कभी नहीं था। जब से कंप्यूटर देश और दुनिया में सक्रिय हुआ तब से इसका प्रभाव उद्योग से जुड़ी हर गतिविधि पर देखा जा सकता है। कई बार तो लोग कह भी देते हैं कि जमाना कंप्यूटर का है और इसी कंप्यूटर से उत्पन्न सोशल मीडिया, यूट्यूब, मोबाइल, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीट्र के बारे में भी यही राय बन रही है। अखबारी दुनिया की अगर हम बात करें तो मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आज भी लोगों का भरोसा प्रिंट मीडिया पर बढ़ रहा हो और अखबारों की बिक्री में आठ लाख से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी हो तो हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती ही जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया का तेजी से उभार और फिर इस पर लाखों चीजों के बारे में जानकारी चाहे वह तथ्यों पर आधारित है या नहीं, का प्रसार हो जाना सचमुच हैरान कर देने वाला था। इस दृष्टिकोण से लोगों का मीडिया के प्रति भरोसा बरकरार रहना एक सुखद एहसास है।

जनवरी से लेकर जून 2025 के बीच ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने देशभर के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन छपने वाले अखबारों की औसतन बिक्री 29744148 कॉपियों तक पहुंच गयी है इससे पहले 2024 के दिसंबर तक यह आंकड़ा 28941876 था और इस प्रकार इसमें 2025 की रिपोर्ट आते-आते 3 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है जिसका मतलब यह हुआ कि 802272 कॉपियों की वृद्धि हो चुकी है। मेरा यह मानना है कि लोगों का भरोसा, उनका प्यार और उनका खुद का आत्मसम्मान अखबारों के लिए एक धरोहर बन जाता है। आज भी समाचार पत्र पूरी तरह से जांच-परख के बाद ही तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं और फिर खबर छापते हैं। ऑडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन के आंकड़ों में और भी बहुत कुछ कहा गया है। एबीसी के मुताबिक भारत में लोग अखबार को ज्यादा विश्वसनीय मान रहे हैं और इसलिए वह यह कहते हैं कि प्रिंट मीडिया गहराई वाले कंटेंट सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसी कंटेंट के दम पर प्रिंट मीडिया की पकड़ मजबूत हो रही है। कुल मिलाकर आज भी भारत में अखबार विश्वसनीय सूचना का स्रोत माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी विज्ञापनदाताओं के लिए अखबार एक मजबूत प्लेटफार्म बनकर अपना काम कर रहा है तभी तो अखबारी जगत का सर्कुलेशन बढ़ रहा है।

कितनी भी घटनाएं हुई हों, भंडाफोड़ या घोटालों की खबरें हों या फिर राजीव हत्याकांड या किसी नेता या हस्ती की मृत्यु की न्यूज हो लोग अगले दिन का अखबार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा कंटेट तथा ज्यादा डिटेल्स चाहिए। अखबारों को लेकर पीएचडी कर रही एक युवती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लोग एक ही खबर का रेपीटेशन नहीं चाहते, जैसा कि सोशल मीडिया कर रहा है। लोग किसी भी कटंट विषय की अतिरिक्त जानकारी के अखबार की कटिंग्स तक सम्भाल कर रखते हैं। यह प्रिंट मीडिया के प्रति लोगों की विश्वसीयता और आस्था है। सच बात तो यह है कि एक अखबार में काम करने वाले पत्रकार भी जुनून में काम करते हैं। एक टीम वर्क की तरह तभी तो समाचार पत्र हर सुबह सबकी पहली पसंद बनते हैं।

सोशल मीडिया के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि किसी भी जानकारी को या घटना को या इवेंट वायरल कर देना ही पत्रकारिता नहीं है। उदाहरण के तौर पर कई हादसे पिछले दिनों उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में हुए। इसकी जानकारी सोशल मीडिया ने जिस ढंग से दी उनमें कईयों ने तो वर्षों पुरानी फोटो छाप दी या वर्षों पुराने वीडियो छाप दिए। ये सब तथ्य परख नहीं था। फैक्ट चैक के माध्यम से सच्चाई सामने आ ही जाती है। सोशल मीडिया अपनी अच्छी पहुंच रखता है लेकिन विश्सनीयता के मामले में अगर इससे जुड़े लोग तथ्यों के साथ चलें और कंटेंट से छेड़छाड़ न करें तो बहुत ही अच्छा है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी स्वरूप हैं वे देश के मान-सम्मान और गरीमा के बारे में अवश्य सोचकर चलें क्योंकि यह तय है कि एक जानकारी अगर गलत ढंग से दी जाये और वह वायरल हो जाये तो बात बिगड़ जाती है। कितने ही लोग सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट के दम पर चीजें प्रस्तुत कर देते हैं जिनका गलत असर पड़ता है। वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। सोशल मीडिया की गलत प्रस्तुतिकरण या गलत कंटेंट को लेकर अगर कोई शिकायत सामने आती है तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए और जो दोषी हो उन्हें कानून की जद में लाकर कुछ न कुछ पग जरूर उठाना चाहिए। इस कड़ी में सोशल मीडिया के तहत यूटयूबर्स ने जो किया वह किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया भी आगे बढ़े और अपनी पहचान तथ्यों के साथ बनाए तो हम इसका समाचार पत्रों की तरह ही सम्मान करेंगे जिसने अपनी पठनियता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ाई है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

एच-1बी के लिए प्रत्येक आवेदन पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाने संबंधी ट्रंप के ताजा फैसले से अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की संख्या में खासी गिरावट आ सकती है। अभी एच-1बी लाभार्थियों में भारतीय पेशेवर 70-71 फीसद तक हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालात साजगार बनाने के फेर में अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भारत और अन्य देशों से पेशेवरों की सेवाएं लेने को महंगा बना कर हालात जटिल किए जा रहे हैं।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक@Chellaney

स्वास्थ्य सेवाएं

भारत डोगरा

वंचित न रहें दूर-दराज के लोग

अनेक विकासशील देशों ने माना है कि दूर-दूर के गांवों में स्वास्थ्य की आवश्यक और अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं सुनिश्चित करना कठिन हो रहा है क्योंकि देश में चाहे पर्याप्त डाक्टर हों पर इन गांवों में डाक्टरों की बहुत कमी है। इस हकीकत को समझते हुए विभिन्न सरकारों ने भी ऐसे अनेक प्रयासों को प्रोत्साहित किया है कि दूर-दूर के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की बेहतर उम्मीद उपस्थित कर सकें। देश के विभिन्न भागों में डाक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और विशेषज्ञों ने भी दूर-दूर के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के अनेक कार्यक्रम चलाए हैं और प्रयोगात्मक प्रयास किए हैं, जो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर चर्चित रहे हैं।

इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय प्रयास लगभग 13 वर्षों से दक्षिण राजस्थान में बेसिक हेल्द सर्विस (बीएचएस) संस्था द्वारा हो रहा है। इसके सह-संस्थापकों डॉ. पवित्र मोहन और डॉ. संजना मोहन के अनुसार इनका आदर्श स्वास्थ्य सेवा का प्रयास ऐसा है, जो समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जिसमें स्वास्थ्य सबका अधिकार हो और जिसे सामुदायिक भागेदारी से इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त और प्रदान करने वालों, दोनों की गरिमा सुनिश्चित रहे। स्वास्थ्य उपलब्धियां टिकाऊ और मजबूत होनी चाहिए। यह प्रयास इस समय उदयपुर और सालम्बुर जिलों में 6 'अमृत' क्लीनिकों पर आधारित है, जो जरूरतमंद समुदायों के बीच दूर-दूर के गांवों में आरंभ किए गए हैं। प्रत्येक क्लीनिक की मुख्य जिम्मेदारी चार भली-भांति प्रशिक्षित नर्सों के समूह पर है, जो आगे भी नया प्रशिक्षण प्राप्त करती रहती हैं। वे किसी भी समय पर फोन या वीडियो से बीएचएस के डाक्टरों से परामर्श कर सकती हैं। सप्ताह में एक निर्धारित दिन एक या दो डाक्टर पूरे समय क्लीनिक पर रहते हैं। जिन अधिक जटिल केसों का इलाज क्लीनिक में संभव नहीं होता उन्हें उदयपुर के अस्पतालों को रेफर किया जाता है, जहां संस्था के मुख्य कार्यालय की ओर से भी यथासंभव सहायता की जाती है। इन क्लीनिकों में अधिकांश लैब टेस्ट करने की सुविधा है। तीन क्लीनिकों को पोर्टेबल एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। अन्य सुविधाएं जुटाने के प्रयास जारी हैं।

नर्सों का चयन प्रायः उन्हीं आदिवासी समुदायों से किया जाता है, जिनमें यह प्रयास सक्रिय है। इस तरह इन्हें समुदायों की स्वास्थ्य समस्याओं और इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की गहरी समझ रहती है। यहां नर्सों को स्वास्थ्य अभियान में अग्रणी भूमिका दे कर उनमें जो विश्वास व्यक्त किया जाता है, उसे उन्होंने भरपूर निभाया है, साहस तथा योग्यता से निभाया है। दिन के अतिरिक्त रात के समय इमरजेंसी केस भी वे संभालती हैं। गांवों में भी जरूरत पड़ने पर वे पहुंचती हैं। इन सभी कार्यों में उन्हें क्लीनिक में मौजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिलता है, जो समुदाय के स्तर पर अनेक जिम्मदारियों को संभालते हैं। क्लीनिक के आसपास के गांवों में इस प्रयास की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जिन्हें गांव में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए स्वास्थ्य किरण का नाम दिया गया है। वे गांव के सभी परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी एकत्र करती हैं और जिन्हें कोई बीमारी है, या स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें क्लीनिक जाने के लिए प्रेरित करती हैं। कुपोषण से पीड़ित बच्चों का पता लगाना, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का आकलन करना, उन्हें समय पर जांच के लिए भेजना, बीमारियों को रोकने संबंधी शिक्षण कार्य करना भी उनकी जिम्मेदारी है। आपात स्थिति में क्लीनिक तक पहुंचाने में एंबुलेंस सेवा के माध्यम से सहायता करने में भी वे आगे रहती हैं।

इन सबकी सक्रियता के साथ बीएचएस के डाक्टर भी क्लीनिक में उपस्थिति या फोन और वीडियो पर परामर्श के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. विदित पांचाल, जो निष्ठा भाव से तीन क्लीनिकों में सेवाएं दे रहे हैं, बताते हैं कि गांवों में स्वास्थ्य समस्याएं बहुत गंभीर हैं, और विविधता भरी हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का पास ही उपलब्ध होना बहुत जरूरी है।

क्लीनिक के पास के गांवों में स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, जिससे समुदाय के महत्त्वपूर्ण और अधिक सक्रिय सदस्यों का परामर्श प्राप्त होता रहे। अन्य सहयोगी संस्थाओं की सहायता भी विशिष्ट कार्यों के लिए प्राप्त कर उन्हें भी जोड़ा जाता है। किसी भी रोग के इलाज के साथ इसकी रोकथाम से जुड़े प्रयास और शिक्षण को भी समुचित महत्त्व दिया जाता है। इलाज के दौरान और उसके बाद मरीज का फालोअप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से किया जाता है। यह टीबी जैसी बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें कई महीनों तक नियमित दवा लेना जरूरी है। टीबी के मरीजों को दवा के साथ पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। पोषण तो स्वास्थ्य की नींव है। अतः कुपोषण कम करने का कार्यक्रम निरंतरता से चलता रहता है। इलाज के अतिरिक्त कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार दिया जाता है। बच्चों का पोषण सुधारने के लिए अनेक गांवों में फुलवाड़ियों की स्थापना की गई है, जहां छोटे बच्चों को प्रति दिन तीन बार पौष्टिक आहार दिया जाता है। खेलकूद के साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य के नियम भी सिखाए जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार इन गांवों में कुपोषण में महत्त्वपूर्ण कमी आई है। इसके अतिरिक्त अनेक गांवों में किचन गार्डन और बकरी तथा मुर्गी पालन को भी पोषण-सुधार की दृष्टि से बढ़ाया गया है।

जिन परिवारों के अनेक सदस्य गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं, उन परिवारों को भी इस प्रयास से राहत प्राप्त हुई है। कुल मिला कर अभी तक हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सका है। विशेषकर टीबी, मलेरिया और कुपोषण से राहत दिलवाने में इस प्रयास का योगदान उल्लेखनीय रहा है। दूसरी ओर, मातृत्व सुरक्षा में सुधार कर भी बहुत सी महिलाओं और बच्चों का जीवन बचाया जा रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों और डाक्टरों के मिले-जुले प्रयास से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गर्भवती महिलाएं नियमित जांच करवाएं तथा क्लीनिक या जरूरत पड़ने पर किसी अधिक बड़े अस्पताल में बच्चे के जन्म के समय पहुंच सकें। गर्भावस्था में खतरे की किसी स्थिति की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। साथ में परिवार नियोजन की दिशा में भी समुचित प्रयास किए जाते हैं। इस प्रयास में स्वास्थ्य सेवा को सब तक पहुंचाने के लिए पहला कदम तो यह है कि इसे बहुत कम कीमत पर उपलबध करवाया जाए। सामान्यतः एक सप्ताह का दवाओं और फीस सहित खर्च 50 रुपये तक सीमित रखा जाता है। दूसरा कदम यह है कि यदि कोई मरीज यह राशि देने में असमर्थ है, तो उसे इलाज निशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। बिना इलाज और दवा के उसे लौटाया नहीं जाता। जो मरीज अमृत क्लीनिकों के सामान्य क्षेत्र से बहुत दूर से भी यहां की प्रशंसा सुनकर पहुंच जाते हैं, उन्हें भी इलाज की सब सुविधाएं दी जाती हैं। अनेक अन्य आदर्शवादी डाक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कुछ अन्य स्थानों पर भी बहुत प्रेरणादायक प्रयास कर रहे हैं व इन सबसे सीखते हुए दूर-दूर के गांवों की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुार संभव है।

एक उल्लेखनीय प्रयास लगभग 13 वर्षों से दक्षिण राजस्थान में बेसिक हेल्द सर्विस (बीएचएस) संस्था द्वारा हो रहा है। इसके सह-संस्थापकों डॉ. पवित्र मोहन और डॉ. संजना मोहन के अनुसार इनका आदर्श स्वास्थ्य सेवा का प्रयास ऐसा है, जो समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जिसमें स्वास्थ्य सबका अधिकार हो और जिसे सामुदायिक भागेदारी से इस तरह बढ़ाया जाए कि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त और प्रदान करने वालों, दोनों की गरिमा सुनिश्चित रहे। स्वास्थ्य उपलब्धियां टिकाऊ होनी चाहिए। यह प्रयास इस समय उदयपुर और सालम्बुर जिलों में 6 'अमृत' क्लीनिकों पर आधारित है, जो जरूरतमंद समुदायों के बीच दूर-दूर के गांवों में आरंभ किए गए हैं। प्रत्येक क्लीनिक की जिम्मेदारी चार भली-भांति प्रशिक्षित नर्सों के समूह पर है, जो आगे भी नया प्रशिक्षण प्राप्त करती रहती हैं

'जैन जी' और मीडिया

मीडिया

सुधीश पचौरी

एक चैनल 'जैन जी' पर चरचा करते हुए सर्वे दिखाता है, जिसमें सबसे ज्यादा '39' फीसद 'जैन जी' मोदी को ही चाहती है। स्पष्ट है कि 'जैन जी' को पटाने-सटाने की राजनीति शुरू है, लेकिन 'जैन जी' जैसी 'आत्मकेंद्रित', 'अहंकारी' और 'घोर आत्मरतिवादी', 'आईमीमाई सेल्फवादी' और 'सोशल मीडियाजीवी' पीढ़ी किस मानदंड से 'क्रांतिकारी' पीढ़ी है

'जैन जी' की चरचा है। 'जैनजी' का हल्ला है। हर चैनल, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया 'जैन जी' की चरचा कर रहा है, और पूछ रहा है कि जैन जी है क्या? लेकिन अभी तक की चरचाओं में 'जैन जी' एक मिथक की तरह बनी हुई है। यह नाम मीडिया में पिछले दिनों तब आया जब नेपाल की 'माओवादी सरकार' के 'भाईभतीजावाद' और 'भ्रष्टाचार' के खिलाफ 'सोशल मीडिया' पर सक्रिय असंतुष्ट युवा सड़कों पर उतर पड़े और सत्ता को बदलने की मांग करने लगे और तीन चार दिन में बदल भी गई।

इस आंदोलन को लीड करने वाले कुछ युवा नेताओं ने ही अपने को 'जैन जी' नाम दिया। इसके बाद यही 'जैन जी' यहां के विपक्ष की 'चहेती' बन गई और मीडिया चरचा में आ गई चरचाओं में विपक्ष के कुछ नेता-प्रवक्ता इसे 'कोतिकारी पीढ़ी' मान रहे हैं, और आह्वान कर रहे हैं कि नेपाल की 'जैन जी' पीढ़ी की तरह यहां की 'जैन जी' पीढ़ी भी यहां की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उसे उखाड़ फेंके... कुछ तो रट लगाए हैं कि हे 'जैन न' जी पीढ़ी तू जल्दी आ, इस सत्ता को हिला, उखाड़ फेंक और नेपाल की तरह नई सत्ता यानी हमारी सत्ता ला और हमें सत्ता में बिठा...। मुझे लगता है कि एक बार फिर विपक्ष के कुछ नेता, नेपाल के घटना विकास को 'जैन जी' का अचानक आह्वान कर 'जैन जी' के 'आइडिया' को एक 'मेनेजेबिल आइडिया' समझकर अपने 'मनोरथ' को बाहर कर दिया है जबकि 'जैन जी' की असली ताकत, उसका जादू अब भी 'अकथनीय' और 'अपरिभाषेय' है...। यह शनिवार की सुबह है, और यह लेखक कई चैनलों को खंगाल चुका है, और पा रहा है कि कई चैनल 'जैन जी' पर 'कब्जे' की लड़ाई को शुरू हुआ दिखा रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि हे 'जैन जी' तू उठ, जाग, सत्ता के विरोध में आंदोलन कर; और हमें बचा...दूसरे बता रहे हैं कि अपनी 'जैन जी' स्वभाव से देशभक्त है, उसे भारत से प्यार है, वह राष्ट्रवादी मूल्यों में यकीन करती है, और उसे मोदी से प्यार है। कुछ पहले एक चैनल ने एक सर्वे में बताया था कि '66' फीसद 'जैन जी युवा' मोदी को अपना 'नायक' मानते हैं। एक चैनल रिपोर्ताज है जिसमें कुछ युवा कहे जा रहे हैं कि मैं 'जैन जी' हूं, मेरा रंग भगवा है। मैं राष्ट्रवादी हूं...एक और 'जैन जी' कहने लगता है कि कुछ लोग 'अर्बन नक्सल' हुए जा रहे हैं। वे 'जैन जी' के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। भारत को 'उपद्रवग्रस्त' कर उसके विकास की तेज गति को रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। यहां की 'जैन जी' ये कभी नहीं होने देगी...।

इसी क्रम में एक चैनल पर कुछ विपक्षी नेता कहते दिखते हैं कि 'जैन जी' आ रही है...'जैन जी' जग गई है...दूसरे कह रहे हैं कि 'जैन जी' इस व्यवस्था से असंतुष्ट है, उसको नई व्यवस्था चाहिए...ऐसे ही एक नेता जी कहिन कि यही तो असली 'हाइड्रोजन बम' था...फिर एक चैनल पर एक वीडियो दिखता है, जिसमें 'जैन जी' पीढ़ी के कई युवा कमरे में मेज के इर्द-गिर्द बैठे हैं कि सामने से पीएम मोदी जी की एंट्री होती है। वे तेज कदमों से हंसते हुए आते हैं। जाहिर है कि वे इन युवाओं से कुछ 'बातचीत' मारने वाले हैं...मैं भी आप की तरह इस 'जैन जी' के बारे में जानना चाहता हूं ताकि समझ सकूं कि ये है क्या है? क्या सह सब देशों में एक जैसी है? क्या यह भारत को भी श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल बना सकती है?

फिर,एक सवाल यह भी है कि वह भारत को उससे भी पिछड़े देश नेपाल की तरह का क्यों बनाना चाहेगी? ऐसा करने की जगह वह इस देश को अमेरिका या यूरोपीय देशों जैसा क्यों नहीं बनाना चाहेगी? पिछड़े देशों की जगह उसे एक 'विकसित देश' क्यों न बनाना चाहेगी? सबसे ताकतवर देश क्यों नहीं बनाना चाहेगी? जो पीढ़ी 'नये पूंजीवाद' में पली-बढ़ी है,'स्मार्टफोन', 'इंटरनेट','सोशल, मीडिया' से 'संवेदित', 'संप्रेरित' और 'संचालित' पीढ़ी है, जो पूरी तरह 'उपभोक्तावादी' और 'इहलोकवादी', 'भौतिकवादी', 'सुखवादी' पीढ़ी है। वह उपद्रव, हिंसा, अराजकता को कैसे पसंद कर सकती है क्योंकि इस प्रक्रिया में उसका 'सुख-चैन' भी छिन सकता है? ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगी...एक चैनल 'जैन जी' पर चरचा करते हुए एक सर्वे दिखाता है, जिसमें सबसे ज्यादा '39' फीसद 'जैन जी' मोदी को ही चाहती है। स्पष्ट है कि 'जैन जी' को पटाने-सटाने की राजनीति शुरू है, लेकिन 'जैन जी' जैसी 'आत्मकेंद्रित', 'अहंकारी' और 'घोर आत्मरतिवादी', 'आईमीमाइसेल्फवादी' और 'सोशलमीडियाजीवी' पीढ़ी किस मानदंड से 'क्रांतिकारी' पीढ़ी है?

२१वीं सदी की शांति का नया मंत्र

शांति दिवस

योगेश कुमार गोयल

शांति आज जीवन, न्याय, समानता, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक संतुलन से जुड़ी एक व्यापक संस्कृति है। 21 सितम्बर को मनाया जाने वाला 'अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस' इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक विषय 'शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें' के तहत मानवता के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है

पूरी दुनिया आज ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, जलवायु संकट, साइबर हमले और सामाजिक असहिष्णुता ने मानवता की साझा आकांक्षाओं को बारंबार चुनौती दी है। ऐसे में शांति का विचार युद्ध न करने तक सीमित नहीं रह गया है। शांति आज जीवन, न्याय, समानता, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक संतुलन से जुड़ी एक व्यापक संस्कृति है। 21 सितम्बर को मनाया जाने वाला 'अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस' इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक विषय 'शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें' के तहत मानवता के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना का उद्देश्य युद्ध और हिंसा के दुष्परिणामों पर ध्यान दिलाना था। आज के वैश्विक परिदृश्य में इसका महत्त्व पहले से कहीं अधिक है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व में लगभग 2.4 अरब लोग किसी न किसी रूप में संघर्षों से प्रभावित हैं। 2023 में शरणार्थियों की संख्या 11.7 करोड़ से अधिक हो गई। जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शांति केवल कूटनीतिक वार्ताओं का विषय नहीं है, बल्कि वैश्विक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक न्याय से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है।

शांति की संस्कृति का निर्माण यूनेस्को के उस मूल सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि 'युद्ध मनुष्यों के दिमाग में शुरू होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा मनुष्यों के दिमाग में ही की जानी चाहिए।' संयुक्त राष्ट्र द्वारा पिछले वर्षों में दिए गए शांति दिवस के विषयों का विश्लेषण बताता है कि शांति के लिए समय-समय पर बदलती चुनौतियों के अनुरूप नीति निर्माण की आवश्यकता है। 2010 में 'शांति और विकास के लिए युवा' पर बल दिया गया जबकि 2019 में 'शांति के लिए जलवायु कार्रवाई' जैसे विषयों ने पर्यावरणीय संकट को शांति का केंद्रीय मुद्दा बनाया। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 का विषय 'एक साथ शांति को आकार देना' था जो दर्शाता है कि वैश्विक संकटों के समय सहयोग की संस्कृति ही समाधान का आधार बनती है। इसी प्रकार 2024 का विषय 'शांति की संस्कृति का विकास करना' इंगित करता है कि शांति को युद्ध विराम की अवधि तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे समाज के हर स्तर पर विकसित करना होगा। आर्थिक असमानता शांति की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत तक पहुंची जबकि करोड़ों लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता हिंसा, अपराध और सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। इसलिए शांति निर्माण के लिए आर्थिक नीति में समावेशी विकास को केंद्र में रखना आवश्यक है।

साइबर सुरक्षा आज शांति निर्माण का एक नया आयाम बन चुकी है। 2024 में दुनिया भर में लगभग 5.8 अरब डिवाइसेज पर साइबर हमलों की आशंका व्यक्त की गई। साइबर युद्ध, डेटा चोरी और दुष्प्रचार आधुनिक संघर्षों के प्रमुख उपकरण बन गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म सुरक्षित न हों तो शांति की संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। शांति निर्माण में संस्कृति, कला और संवाद भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम मानसिक आघात से उबरने में मदद कर सकते हैं। महात्मा गांधी का यह कथन कि 'शांति का कोई मार्ग नहीं है, शांति ही मार्ग है' हमें याद दिलाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का तरीका है।

अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार कि 'शांति बल से नहीं बल्कि समझ से कायम रहती है' बताता है कि संवाद और समझ ही स्थायी समाधान के आधार हैं। पर्यावरण संरक्षण भी शांति निर्माण का आवश्यक अंग है। महिलाओं की सहभागिता भी शांति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। शोध बताते हैं कि जहां महिलाओं को शांति प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है, वहां संघर्ष समाप्त होने की संभावना 35 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यह समय है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका पहचाने, समाज के हर स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दे और ऐसी संस्कृति का निर्माण करे जिसमें साझा विकास की बात हो।

प्रकृति दिए जा रही है मौन चेतावनी

टिटहरी

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत का ग्रामीण जीवन सदियों से प्रकृति के साथ गहरे संवाद में रहा है। खेत, मौसम और जीव-जंतु मिलकर किसान की दिनचर्या और भविष्य, दोनों को प्रभावित करते हैं। इन सबके बीच टिटहरी एक ऐसा छोटा-सा पक्षी है, जो सामान्य आंखों से मामूली दिखता है, लेकिन किसानों और लोक जीवन की स्मृतियों में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला प्रहरी माना जाता है। यह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि धरती और आकाश के बीच संवाद का माध्यम है, मौन दूत है जो संकट और समृद्धि, दोनों की आहट पहले ही दे देता है।

ग्रामीण अनुभव बताते हैं कि टिटहरी का व्यवहार मौसम और कृषि की दिशा तय करने में अहम संकेत देता है। यदि वह चार अंडे देती है तो चार महीने अच्छी वर्षा होने का विश्वास किया जाता है। जब वह ऊंचाई पर अंडे देती है, तो लोग मानते हैं कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। यदि कभी वह मजबूरी में छत या पेड़ पर अंडे दे, तो यह भीषण बाढ़ का संकेत माना जाता है। वहीं, यदि अंडे न दे तो सबसे डरावनी स्थिति होती है, क्योंकि लोग इसे अकाल का दूत मानते हैं। किसान कहते हैं कि जिस खेत में टिटहरी अंडे देती है, वह खेत खाली नहीं रहता। वहां फसल जरूर होती है। इस तरह यह पक्षी न केवल वर्षा और मौसम से जुड़े संकेत देता है, बल्कि उपजाऊपन और अकाल जैसी चरम स्थितियों की चेतावनी भी बन जाता है। लोक जीवन में एक और मान्यता है कि टिटहरी का मृत शरीर कुरुक्षेत्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। चाहे यह तथ्य हो या कल्पना, लेकिन यह विश्वास उसे जीवन और अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक बना देता है। टिटहरी को देखने वाला किसान समझ जाता है कि यह पक्षी उसकी मिट्टी, फसल और भविष्य का पहरेदार है। यही कारण है कि ग्रामीण लोक गीतों और कहावतों में भी टिटहरी का उल्लेख मिलता है। यह ऐसा जीव है, जिसकी गतिविधियों पर पीढ़ियों का भरोसा रहा है।

सवाल उठता है कि जब विज्ञान मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह, राडार और कंप्यूटर मॉडल जैसे अत्याधुनिक साधन लेकर आया है, तब टिटहरी जैसे पक्षियों की भूमिका क्या रह जाती है। वास्तव में इसका उत्तर यही है कि विज्ञान और लोक अनुभव एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो टिटहरी जैसे पक्षी पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक भाषा में इन्हें 'इकोसिस्टम इंडिकेटर' कहा जाता है यानी ऐसे जीव जो अपने आचरण से पर्यावरणीय बदलावों की समय रहते जानकारी दे देते हैं। इस प्रकार लोकानुभव ने जो बातें कही हैं, वे वास्तव में वैज्ञानिक कारणों से जुड़ी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसानों ने इन्हें अपनी भाषा और प्रतीकों में व्यक्त किया। शहरों में रहने वाला इंसान नहीं जानता कि कब कोई पक्षी अपनी आदत बदल रहा है, कब उसकी संख्या घट रही है, या कब उसका स्वर बदल रहा है। यही लापरवाही हमें अचानक आने वाली आपदाओं के सामने असहाय बना देती है। यदि हम टिटहरी और अन्य पक्षियों के संदेशों को गंभीरता से लें तो आपदा प्रबंधन की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। टिटहरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह पक्षी खेत को कभी खाली नहीं छोड़ता। उसका वहां अंडे देना किसानों के लिए आश्वासन का प्रतीक है। यह विश्वास अपने आप में संदेश है कि प्रकृति मनुष्य को निराश नहीं करती बशर्ते हम उसका सम्मान करें। विज्ञान देर से अलर्ट करता है, लेकिन टिटहरी पहले से सावधान कर देती है।

समेकित विकास से बचाव संभव

निकोबार का पर्यावरण

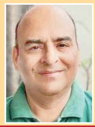

पंकज चतुर्वेदी

क्या विकास के प्रतिमान में आदिम लोगों के नैसर्गिक पर्यावास, जीवन शैली, बोली-भाषा को संरक्षित करने की कोई नीति नहीं है? हिन्द महासागर में 572 द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार इन दिनों ऐसे ही द्वंद्व से गुजर रहा है। ये द्वीप इंडोनेशिया और थाईलैंड के पास हैं। 2013 में इसे यूनेस्को के जैवमंडल कार्यक्रम (ह्यूमन एंड बायोस्पियर प्रोग्राम) में शामिल किया गया। यह जगह समृद्ध जैव-विविधता और वन्यजीवों की एक असाधारण विविधता का घर है।

सरकार के अनुसार, यह दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में से एक है। ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत सितम्बर, 2020 में उस समय हुई थी, जब कोविड के चलते दुनिया थमी हुई थी। उस समय नीति आयोग ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी)' जारी किया था। कोई 72,000 करोड़ रुपये की एकीकृत परियोजना में मेगा पोर्ट, हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किमी. में विस्तृत शहर, सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण शामिल हैं।

यहां आने वाले सालों में कोई चार लाख बाहरी लोगों अर्थात वर्तमान आबादी के कई हजार प्रतिशत को बसाने की योजना है। मार्च, 2021 में गुरुग्राम स्थित एक परामर्श एजेंसी एईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 126 पेजों की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) जारी की थी। इसकी रिपोर्ट पाते ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति लेने की औपचारिकता शुरू हो गई। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करने के लिए हैदराबाद स्थित विमता लैब्स को काम सौंपा गया। दिसंबर, 2021 में मंत्रालय ने ईआईए रिपोर्ट के मसौदे को टिप्पणियों और चर्चा के लिए जनता के बीच रखा। जनवरी, 2022 में अनिवार्य जनसुनवाई ग्रेट निकोबार के प्रशासनिक मुख्यालय कैंपबेल खाड़ी में आयोजित की गई और विमता ने अंतिम ईआईए रिपोर्ट मार्च में प्रकाशित की। जनसुनवाई प्रक्रिया के दौरान जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर एवं डीन जानकी अंधारिया ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को लिखा कि प्रस्तावित कंटेनर टर्मिनल ऐसे स्थान पर है, जहां पिछले 10 वर्षों में 444 भूकंप (हर साल लगभग 44 भूकंप) आए। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद ईएसी की कई बैठकों में इस परियोजना पर चर्चा की गई और आखिरकार, अगस्त, 2022 में मंजूरी के लिए परियोजना की सिफारिश की। मंत्रालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर नवम्बर में अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी दे दी । 27 अक्टूबर, 2022 को मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग ने परियोजना के लिए 130.75 वर्ग किमी. के प्राचीन वन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी जिसके बाद यह हाल के दिनों में किया गया सबसे बड़ा फॉरेस्ट डायवर्जन (परिवर्तन) बन गया-वह भी आधी-अधूरी औपचारिकता के साथ। यहां साढ़े आठ लाख पेड़ काटे जाना है ।

द्वीप का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग किमी. से थोड़ा ज्यादा है। इसका लगभग 850 वर्ग किमी. क्षेत्र अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण विनियमन, 1956 के तहत आदिवासी रिजर्व के रूप में नामित है। पारिस्थितिक रूप से समृद्ध द्वीप को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। ईआईए रिपोर्ट में द्वीप का क्षेत्रफल एक जगह पर 1,045 वर्ग किमी. है जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह 910 वर्ग किमी. है। बताया गया कि गैलाथिया बंदरगाह क्षेत्र किसी भी प्रवाल भित्तियों को रिकॉर्ड नहीं करता है जबकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अध्ययन से पता चलता है कि गैलाथिया खाड़ी में प्रवाल भित्तियां 116 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। प्रवाल भित्तियां या प्रवाल शैल श्रेणियां (कोरल रीफ्स) समुद्र के भीतर के चट्टान हैं, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। गैलाथिया की खाड़ी भारत में जायंट लीथरबैक नामक कछुआ प्रजाति के लिए प्रतिष्ठित प्रजनन और अंडे देने का स्थान अर्थात नेस्टिंग साइट है, जिसे तीन दशकों में किए गए सर्वेक्षणों के तहत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ कहा गया है। द्वीप में जीवों की 330 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जबकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार, इनकी संख्या 695 है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ग्रेट निकोबार से दूसरी जगह किसी प्रवासी पक्षी की सूचना नहीं है जबकि सर्वविदित है कि यह द्वीप विश्व स्तर पर दो महत्त्वपूर्ण पक्षी फ्लाईवे की जगह है अर्थात जिस रास्ते से होकर प्रवासी पक्षी भारत आते हैं।

निकोबार में विकास की योजना में विरली प्रजाति के आदिवासियों के साथ भी 'शब्द-भ्रम' खेला गया। विशेष रूप से संवेदनशील पांच जनजातीय समूहों-ग्रेट अंडमानी, जरवा, ओंज, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनली के नैसर्गिक आवास को नजरंदाज किया गया। अलबत्ता सरकारी रिपोर्ट यह जरूर कहती है कि 'आदिवासियों के अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी और उनका ध्यान रखा जाएगा।' *(लेख में विचार निजी हैं)*

हिन्द महासागर में 572 द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार इन दिनों द्वंद्व से गुजर रहा है। ये द्वीप इंडोनेशिया और थाईलैंड के पास हैं। 2013 में इसे यूनेस्को के जैवमंडल कार्यक्रम (ह्यूमन एंड बायोस्पियर प्रोग्राम) में शामिल किया गया। यह जगह समृद्ध जैव-विविधता और वन्यजीवों की असाधारण विविधता का घर है। सरकार के अनुसार, यह दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में से एक है। द्वीप का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग किमी. से थोड़ा ज्यादा है। इसका लगभग 850 वर्ग किमी. क्षेत्र अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण विनियमन, 1956 के तहत आदिवासी रिजर्व के रूप में नामित है

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-35, अंक 38 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मैच के बाद दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। इसका कुछ मतलब नहीं। नाटकबाजी है जो अटारी-वाघा सीमा पर दोनों तरफ के सैनिक बेहतर कर सकते थे। आपने खेलने का फैसला किया है तो आपको खिलाड़ी रहना चाहिए। न देशभक्त बनें, न खिलाड़ी। बस दुकानदार रहे।
राहुल पंडिता, लेखक @rahulpandita

पड़ोस में अशांति

प्रो. सतीश कुमार

किस ओर जाता दिखता है नेपाल

नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, वह अनहोनी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से हो रहा है, वह प्रश्न खड़ा करता है। गरीब देश और धनी नेता सिद्धांत नेपाल में प्रचलित है। अंदरूनी समस्याओं को नजरअंदाज कर भारत विरोधी मुहिम को हवा देने की बात भी पुरानी है। राजशाही में भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ओली के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ। युवा पीढ़ी हताश हो गई। पलायन तेजी से बढ़ा। धर्म और समाज की मजबूत भीत को वामपंथी सोंच ने तोड़ने का षड्यंत्र रचा। सनातन व्यवस्था हाशिये पर आ गई। बाहरी शक्तियां पहले से ही मजबूत थीं। मसलन, ईसाई मिशनरी की पकड़ में बहुत हद तक शहरी आबादी थी, जो आज भी है। इसलिए डीप स्टेट सिद्धांत का जब प्रश्न उठता है, तो उनका तरीका मिशनरी के रास्ते से होकर गुजरता है। जिस तरीके से नेपाल के युवा पीढ़ी में उबाल समुद्री तूफान की तरह पैदा किया गया, वह किसी सुनयोजित सोच का ही नतीजा है। इसलिए बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी तंत्र के तार इससे नहीं जुड़े हुए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों, संसद और पूर्व प्रधानमंत्री के घरों पर हमला किया और उनमें आग लगा दी। हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालात इतने खराब हो गए कि नेपाल में सेना को भी सड़कों पर उतरना पड़ा। नेपाल में 'जेन-जी' आंदोलन सिर्फ एक तात्कालिक विरोध नहीं है, बल्कि दशकों के कुशासन और राजनीतिक विफलता का परिणाम है। नेपाल में हालिया विरोध प्रदर्शनों के पीछे सबसे बड़ा कारण युवा जनसंख्या का बढ़ता असंतोष और व्यापक भ्रष्टाचार है। ये दोनों कारक आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और देश की वर्तमान अस्थिरता की जड़ हैं। नेपाल की लगभग 42.5% आबादी 16 से 40 साल के बीच की है, जो इसे एक 'युवा राष्ट्र' बनाती है। यह युवा पीढ़ी राजनीतिक और आर्थिक, दोनों तरह के कुशासन से निराश है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है। इस वजह से हर दिन हजारों युवा नौकरी की तलाश में विदेश जा रहे हैं। युवाओं को लगता है कि उनकी शिक्षा और मेहनत का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नौकरी और मौके सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं, जिनके राजनीतिक संपर्क हैं। 'जेन-जी' पीढ़ी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। वे दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रही प्रगति को देखते हैं, और अपने देश की धीमी रफ्तार से निराश हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी बात रखने और संगठित होने का एक मंच दिया है। सोशल मीडिया पर 'नेपो किड्स' नाम के ट्रेंड ने नेताओं के बच्चों की शानदार जीवनशैली को उजागर किया। जब युवा गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तब राजनेताओं का यह दिखावा उनका गुस्सा और भी बढ़ा देता है।

हाल के वर्षों में कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, जैसे कि सहकारी घोटाला और भूतानी शरणार्थी घोटाला, जिनमें करोड़ों रुपये का हेरफेर हुआ है। इन घोटालों ने युवाओं के मन में विश्वास पैदा कर दिया है कि नेता अपने फायदे के लिए काम करते हैं। लगातार सरकार बदलने और नेताओं के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया है। उन्हें लगता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती। नेपाल में युवाओं की बढ़ती जनसंख्या और उनके सपनों के बीच गहरी खाई है, जिसे भ्रष्टाचार और खराब शासन ने और भी चौड़ा कर दिया है। इसी असंतोष के कारण युवा सड़कों पर उतरे और यही वह चिंगारी है जिसने हालिया विरोध प्रदर्शनों को बड़ा रूप दे दिया। कुल मिलाकर, नेपाल की मौजूदा स्थिति भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत को यहां बहुत सोच-समझ कर और धैर्य के साथ काम करना होगा। नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को बांग्लादेश और मालदीव से कुछ महत्त्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है।

'डीप स्टेट' एक षड्यंत्र सिद्धांत है, जो मानता है कि किसी देश की चुनी हुई सरकार के पीछे एक गुप्त और अनौपचारिक सरकारी संस्था होती है। इस गुप्त संस्था में सरकारी अधिकारी, सैन्य अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के लोग शामिल होते हैं, जो अपनी नीतियों और हितों को बढ़ावा देने के लिए पर्दे के पीछे से काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि देश को चलाने वाले नेता सिर्फ मोहरे होते हैं, जबकि असली फैसले यह गुप्त समूह लेता है। नेपाल की राजनीति जिस तरीके से हिचकोले ले रही है, उससे आम समुदाय अत्यंत हताश और विक्षुब्ध है। 2008 के बाद से 13 सरकार बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री पद म्यूजिकल चेयर की तरह बन गया लेकिन जब से ओली पुनः प्रधानमंत्री 2024 में बने, उसके बाद से नेपाल निरंतर समस्याओं से घिरता गया। अंदुरूनी विखंडन और रस्साकसी और गंभीर बन गई। नेपाल के भीतर हिन्दू संस्कृति बाहरी ताकतों के निशाने पर है। क्रिश्चियन पावर लॉबी हावी है, सत्ता संतुलन का खेल पैसों पर खेला जा रहा है। मुस्लिम आबादी अप्राकृतिक ढंग से बढ़ती जा रही है। 30 साल पहले मुस्लिम आबादी 1 प्रतिशत से भी कम थी, आज 5 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुकी है। रोहिंग्या समुदाय के लोग भी काठमांडू शहर के भीतर देखे जा सकते हैं।

बहुत कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहा है तो बहुत कुछ राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा सकता है। इस डेमोग्राफिक बदलाव से सामाजिक समरस्ता और सांस्कृतिक आधार कमजोर बन रहा है। राजनीतिक और आर्थिक संकट भी पनप रहा है। नेपाल की संस्कृति का विघटन मुस्लिम और ईसाई समुदाय के पसरते पैर की वजह से हो रहा है। नेपाल में ईसाई समुदाय के 'दबदबे' पिछले कुछ दशकों में प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो नेपाल में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय है। नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार, देश में ईसाई आबादी कुल जनसंख्या का 1.76% है, जो लगभग 5,12,313 लोग हैं। यह संख्या पहली नजर में बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन इसकी वृद्धि दर बहुत तेज है। नेपाल के संदर्भ में भारत को अत्यंत सजग रहने की जरूरत है। 5 बड़े राज्यों से हमारी सीमाएं मिलती हैं। लाखों लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। रोटी-बेटी और रोजी-रोटी का आयाम दोनों देशों के बीच है। बाकी देशों में इस बवाल की लहर सोशल मीडिया या टीवी चैनल तक सीमित होगी लेकिन भारत में आग की लपट में बहुत कुछ बर्बाद होगा क्योंकि नेपाल अलग देश होने के बावजूद भारत के साथ एक जुड़वां की तरह आबद्ध है, उसके ऊपर कोई भी दर्द भारत के लिए कष्टदायक होगा। यह सच किताबों और कूटनीति के जरिए नहीं समझा जा सकता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदना के साथ ही महसूस किया जा सकता है। ■

नेपाल की संस्कृति का विघटन मुस्लिम और ईसाई समुदाय के पसरते पैर की वजह से हो रहा है। नेपाल में ईसाई समुदाय के 'दबदबे' में पिछले दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो नेपाल में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय है। नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार, देश में ईसाई आबादी कुल जनसंख्या का 1.76 प्रतिशत है, जो लगभग 5,12,313 लोग हैं। यह संख्या पहली नजर में बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन इसकी वृद्धि दर बहुत तेज है। नेपाल के संदर्भ में भारत को अत्यंत सजग रहने की जरूरत है। 5 बड़े राज्यों से हमारी सीमाएं मिलती हैं। लाखों लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। रोटी-बेटी और रोजी-रोटी का आयाम भी दोनों देशों के बीच है

अखिलेश आर्येन्दु

संपूर्ण क्रांति के लिए स्थापित हुआ आर्य समाज

भारतीय नवजागरण में जिन संस्थाओं या आंदोलनों का देश, समाज और संस्कृति के उत्थान में सबसे अधिक योगदान और स्थाई प्रभाव देखा गया उनमें महर्षि दयानंद सरस्वती के जरिए स्थापित आर्य समाज प्रमुख है। इसकी स्थापना 1875 में बम्बई (अब मुंबई) में हुई थी। देश, समाज नवनिर्माण, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, समाज सुधार, संस्कार, विचार, जीवनशैली, साहित्य, भाषा, लिपि, मानव मूल्य स्थापना और मानवता के कल्याण से ताल्लुक रखने वाले जैसे अनेक क्षेत्रों, विषयों और स्थापनाओं की यात्रा के साथ आर्य समाज बढ़ता गया और आज 150 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा इसे आर्य समाज को नये समय के साथ नये चिंतन, विमर्श और समीक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। आर्य समाज के 150 साल पूरे होने के अवसर पर तमाम देशों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।

एक सौ पचास वर्ष पहले जब आर्य समाज स्थापित हुआ था, देश और समाज अंग्रेजी राजसत्ता के आधीन थे। ऐसे में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के जरिए देश को आजादी दिलाने और समाज को सुधार कर भटके हुए भारतीयों को वैदिक मार्ग पर लाने के अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। आज 32 से अधिक देशों में आर्य समाज स्थापित हैं, जिनके जरिए शिक्षण संस्थाएं और दूसरे प्राकल्प संचालित हैं। आज दुनिया भर में पांच हजार से अधिक आर्य समाज, 100 से अधिक गुरुकुल, इतने ही अनाथालय, हजारों की तादाद में डीएवी शिक्षण संस्थाएं आर्य समाज और महर्षि दयानंद के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही हैं।

वेदों को फिर समाज का हिस्सा बनाने, वैदिक वांगमय को जन-जन तक पहुंचाने, देश को आजाद कराने, वर्ण व्यवस्था की खूबियों को समाज को बताने, समाज सुधार, हिन्दी के विकास, नागरी लिपि को सम्मान, दलितों और महिलाओं को समाज में उचित जगह और सम्मान दिलाने और उनकी रक्षा करने, पुरातन वैदिक शिक्षा पद्धति गुरुकुल को फिर से शिक्षा का जरिया बनाने, जन्मगत जाति व्यवस्था से उपजी बुराइयों, कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंड़ों से जनता को सावधान और गुमराह होने से बचाने और भारतीय सांस्कृतिक चेतना जगाने जैसे ऐतिहासिक कार्य आर्य समाज के जरिए किए गए हैं।

स्वदेशी ही भारत का आत्मगौरव है, इसे किसी ने पहली बार बगैर किसी स्वार्थ और डर से ऊपर उठ कर कहा तो वे महर्षि थे। उन्होंने 1876 में स्वदेशी का नारा दिया जिसमें स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी धर्म, स्वदेशी राज, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी गौरव, स्वदेशी ज्ञान-विज्ञान, स्वदेशी आचार-विचार, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी विचार, स्वदेशी संविधान, स्वदेशी कानून, स्वदेशी चिंतन और स्वदेशी आहार-विहार, स्वदेशी संस्कार, अध्यात्म विद्या सहित स्वदेशी के सभी तरह के आदर्श और मूल्य शामिल हैं। जिस राष्ट्रवाद, सत्य की स्थापना, वेदों के मुताबिक समाज का निर्माण, कृण्वतो विश्वमार्यम का विश्व समाज को सर्वोत्तम बनाने और वैदिक शिक्षा प्रणाली व पद्धति से बच्चों के संस्कार के मकसद के अलावा जिन वैदिक विचारों, चितन, विमर्श और मिशन को लेकर महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में शुरुआत की थी, आर्य समाज ने उन्हें हकीकत में बदलने के संकल्प के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। वह दयानंद के मकसद को कितना पूरा कर पाया है, यह जरूर उसे अब सोचने की जरूरत हो सकती है क्योंकि लम्बी यात्राओं में संस्थाओं में तमाम तरह के उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हम आर्य समाज का जब भी मूल्यांकन करें उसके मौजूदा हालात के ही मद्देनजर न करें, बल्कि 150 सालों में आर्य समाज ने देश, संस्कृति, समाज, मानवता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भावना फैलाने, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने, भाषा, लिपि, वेद-वेदांग, दलित, महिला, उपेक्षित, अनाथ और गुमराह लोगों को सही राह पर लाने जैसे माननीय संवेदना वाले कार्यों का भी बेबाक मूल्यांकन क्या नहीं करना चाहिए?

आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष

महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, वेदों का हिन्दी में भाष्य, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, संस्कार विधि, वेदांजलि जैसी चालीस से अधिक किताबें लिखीं जिन्हें आर्य समाज ने अपने समाज, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म सुधार के लिए इस्तेमाल किया। चर्चित फ्रेंच लेखक रोम्यां रोला ने दयानंद की वेगवती क्रांति की आंधी और धधकती वेद ज्ञान की ज्वाला को देखा था। उन पर इनका प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने स्वामी दयानंद के समाज सुधार वाली क्रांति की धारा को उस युग की सबसे प्रबल धारा कहा। वे कहते हैं-'दयानंद ने वेद के दरवाजे सारी मानव जाति के लिए खोले। उनके लिए सारी मानव जाति एक ईश्वर की संतान है। दलितों, शोषितों और अछूतों के अधिकारों का उनके जैसा कोई पैरोकारी नहीं हुआ।' रोम्यां रोला के इन विचारों में अंध समर्थन नहीं है, बल्कि तत्कालीन भारत पर दयानंद और आर्य समाज के गहरे असर का परिणाम है। भारतीयों में सबसे पहले अंतर्मन के सोए स्व को जगाने, उन्हें वैदिक धर्म, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और आत्म-गौरव को बोध कराने का कार्य नवजागरण काल में सबसे पहले महर्षि दयानंद ने किया था। उन्होंने अंग्रेजो को ललकार कर कहा-भारत भारतीयों का है। यहां की मिट्टी, पानी, हवा, आग और धरती के हर कण पर भीरतीयों का ही हक है। एक बार उनकी सभा में गवर्नर जनरल आए और सभा खत्म होने के बाद पूछा-आप हमारे राज्य के बारे में भी कुछ प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? महर्षि बोले हां, करता हूं। क्या करते हैं-महर्षि बोले-मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देशवासी विदेशी राजसत्ता के बंधनों से जल्द से जल्द मुक्त हों। यह सुन कर जनरल सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक संन्यासी अंग्रेजी राज्य के बारे में इस तरह के विचार रखता होगा। ■

आदर्श शासन और समाजवाद के प्रणेता

महाराजा अग्रसेन भारतीय संस्कृति और इतिहास के उन दिव्य शासकों में गिने जाते हैं, जिनकी शासन-कीर्ति किसी एक युग तक सीमित नहीं रही। उनका लोकहितकारी चिंतन कालजयी हो गया। उनकी विलक्षण एवं आदर्श शासक-प्रणाली और उसकी दृष्टि में सत्ता का हित सर्वोपरि न होकर समाज एवं मानवता सर्वोच्च था। उन्होंने अपने जीवन और दर्शन से मानवता को नई दिशा प्रदान की। वे केवल अग्रवाल समाज के ही शासक नहीं थे, बल्कि आदर्श समाज व्यवस्था के प्रणेता और शांति के दूत भी थे।

महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। धार्मिक मान्यतानुसार इनका जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की चौंतीसवी पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के प्रतापनगर के महाराजा वल्लभ सेन के घर द्वापर के अंतिमकाल और कलियुग के प्रारंभ में लगभग 5150 वर्ष पूर्व हुआ था। अग्रसेन महाराज वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन के जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज वल्लभ से कहा था कि यह बालक बहुत तेजस्वी है और बड़ा राजा बनेगा। इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था का उदय होगा और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर रहेगा। सचमुच उनका युग रामराज्य की साकार संरचना था जिसमें उन्होंने अपने आदर्श जीवन कर्म से, सकल मानव समाज को महानता का जीवन-पथ दर्शाया। उनकी जन्म जयंती आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात नवरात्री के प्रथम दिन यानी 22 सितम्बर, 2025 को मनाई जाएगी।

अग्रसेन जयंती

वे केवल सम्राट नहीं थे, बल्कि दार्शनिक, चिंतक और युगदृष्टा थे। उन्होंने 'राजा प्रजा का सेवक है' जैसी अवधारणा को व्यवहार में उतारा। उनका व्यक्तित्व हमें महावीर, बुद्ध और अशोक जैसे शांति दूतों की याद दिलाता है। उन्होंने हिंसा का त्याग कर अहिंसा, सहयोग और सामूहिकता को समाज की आत्मा माना। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया कि उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक निवासी उसे एक रुपया व एक ईंट देगा, जिससे आसानी से उसके लिए निवास स्थान व व्यापार का प्रबंध हो जाए। उन्होंने पुनः वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल मान्यताओं को लागू कर राज्य के पुनर्गठन में कृषि-व्यापार, उद्योग, गौपालन के विकास के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया। इससे न केवल आर्थिक सहयोग की व्यवस्था बनी, बल्कि समाज में भाईचारे और साझा जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई। यह सोच आज की आधुनिक 'कोऑपरेटिव सोसायटी' और 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' की जड़ों में देखी जा सकती है। अग्रसेन जी का जीवन संदेश था-हिंसा से नहीं, शांति और सहयोग से ही स्थायी सुख संभव है।

महाराज अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श पर वे आग्रेय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा जगत की उन्नति मूल रूप से जिन चार स्तंभों पर निर्भर होती है, वे हैं-आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक। अग्रसेन जी का जीवन-दर्शन चारों स्तंभों को दृढ़ करके उन्नत विश्व के नवनिर्माण का आधार बना है। लेकिन इसे समय की विडंबना ही कहा जाएगा कि अगणित विशेषताओं से संपन्न, परम पवित्र, परिपूर्ण, परिशुद्ध, मानव की लोक कल्याणकारी आभा से युक्त महामानव महाराज अग्रसेन की महिमा से अनभिज्ञ अतीत से वर्तमान तक के कालखंड ने उन्हें समाज विशेष का कुलपुरुष घोषित कर उनके स्वर्णिम इतिहास को हाशिए पर डाल दिया है।

समाज व्यवस्था उनके लिए कर्त्तव्य थी, इसलिए कर्त्तव्य से कभी पलायन नहीं किया तो धर्म उनकी आत्मनिष्ठा बना, इसलिए उसे कभी नकारा नहीं। महाराजा अग्रसेन जी की इसी विचारधारा का ही प्रभाव है कि आज भी अग्रवाल समाज शाकाहारी, अहिंसक एवं धर्मपरायण के रूप में प्रतिष्ठित है। अग्रसेन जी ने राजनीति का सुरक्षा कवच धर्मनीति को माना। राजनेता के पास शस्त्र है, शक्ति है, सत्ता है, सेना है फिर भी नैतिक बल के अभाव में जीवन मूल्यों के योगक्षेम में वे असफल होते हैं। इसीलिए उन्होंने धर्म को जीवन की सर्वोपरि प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठापित किया।

■ *प्रस्तुति : ललित गर्ग*

राग रंग | आलोक पराड़कर

विद्यालयों में रंगकर्म की जरूरत

लखनऊ में इधर दो ऐसे आयोजन हुए जिनमें विद्यालयों में रंगमंच की जरूरत पर चर्चा करते हुए सरकारों से मांग की गई कि आरंभिक कक्षाओं से ही रंगमंच को शामिल किया जाए। विद्यालयों के वार्षिकोत्सवों में एक-दो नाटकों के मंचन से ही इस दायित्व से मुक्त हो लेने की जगह बाकायदा पाठ्यक्रम बनाकर रंगमंच की पढ़ाई हो। एमिटी विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में वार्षिक थिएटर उत्सव के अवसर पर शिक्षा में रंगमंच पर दो दिवसीय संगोष्ठी हुई तो बेनहर फोरम फॉर थिएट्रिकल आर्ट्स (बफ्टा) ने लखनऊ में अपनी गतिविधियों का आगाज करते हुए इसी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। ये आयोजन बताते हैं कि अब शिक्षा में रंगमंच की मांग बढ़ने लगी है।

प्रसिद्ध रंगकर्मी राज बिसारिया ने 70 के दशक में जब अपनी टॉ (थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप) बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप को लेकर उपहास भी किया था लेकिन बिसारिया का कहना था कि वास्तव में वह रंगमंच में प्रशिक्षण के महत्त्व को समझाना चाहते हैं। बाद में उनके प्रयासों से लखनऊ में भारतेन्दु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई जो आज पांच दशकों का सफर तय कर रही है। वास्तव में समाज में रंगमंच को लेकर यह धारणा नहीं बन पाई कि इसकी भी शिक्षा आरंभिक कक्षाओं से होनी चाहिए। संगीत और चित्रकला की पढ़ाई तो होने लगी, शिक्षक भी नियुक्त हुए लेकिन रंगमंच के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी। जबकि रंगमंच सीखते हुए ढेर सारी कलाओं से जाने-अनजाने ही रिश्ता हो जाता है, और साहित्य से निकटता भी।

यह भी सुखद है कि एमिटी विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में यह थिएटर उत्सव का तीसरा वर्ष था। रंगमंच और फिल्म की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लब का गठन भी किया गया है, जिसमें पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थी सक्रिय हैं। बीते 18 एवं 19 सितम्बर को थिएटर उत्सव के विभिन्न सत्रों में शिक्षा में रंगमंच पर विशेषज्ञों के साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों और देश भर से आए और ऑनलाइन जुड़े शोध विद्यार्थियों ने विचार रखे। प्रसिद्ध रंगकर्मी अनिल रस्तोगी, शिक्षाविद् उर्वशी साहनी, एमिटी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की निदेशक कुमकुम राय, असि. प्रोफेसर मंजरी जौहरी, ए.बाबू राजेंद्र प्रसाद, रोहित यादव, अर्चना गुप्त ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि रंगमंच केवल प्रस्तुति की कला नहीं, रचनात्मकता, कलात्मकता, आलोचनात्मक समझ और सामूहिकता को विकसित करने का माध्यम भी है। यह संवेदनशील भी बनाता है। आयोजन में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय तथा अवध गर्ल्स डिग्री कालेज का भी सहयोग एवं प्रतिभागिता रही।

थिएटर उत्सव की पूर्व संध्या पर रोहित यादव के निर्देशन में गिरीश कर्नाड के 'नागमंडल' का मंचन भी उल्लेखनीय रहा। राज बिसारिया द्वारा स्थापित टॉ के वरिष्ठ सदस्य रोहित ने विद्यार्थियों के लिए इस नाटक का चुनाव कर जोखिम तो उठाया ही था, इसे संगीत की दृष्टि से काफी समृद्ध भी कर दिया। 'नागमंडल' लोक कथाओं के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज, स्त्री पर होने वाले अत्याचार, विवाह संस्था के विद्रूप का प्रभावी चित्रण करता है। रोहित ने युवा प्रतिभागियों और दर्शकों के मद्देनजर नाटक में लोक के साथ ही कुछ प्रचलित गीतों और आधुनिक संगीत का भी इस्तेमाल किया था। ज्योति कन्याओं के साथ हास-परिहास और नृत्य से आरंभ होकर नाटक धीरे-धीरे गंभीर होता जाता है तथा दर्शकों पर अपनी पकड़ बना लेता है। इसमें नाटक में रानी की भूमिका में रिम्मी राय का प्रभावपूर्ण अभिनय भी सहायक बनता है। कुबेर तिवारी अपन्ना की कठोरता को तो कुशलता से अभिव्यक्त कर जाते हैं, लेकिन नागप्पा के प्रेम की कोमलता में थोड़ा पिछड़े दिखे। दिव्यांशी श्रीवास्तव और राजकुमार राय भी अच्छे थे। अन्य भूमिकाओं में अरुणा सिंह, सृष्टि मित्र, अनन्या शुक्ल, वासवी चतुर्वेदी, अंशिका साहनी, शिवानी कुमारी, प्रियांश दत्ता राय, प्रियांशु उपाध्याय, हर्ष सिंह थे। नाटक में विकास सिंह एवं वेद प्रकाश ने संगीत पक्ष को अच्छे से संभाला था। गायक-गायिकाओं के दल के साथ वे मंच पर थे। नाटक में छाया पुतल का सुंदर उपयोग हुआ, खासकर नाग से जुड़े दृश्यों में। बफ्टा की आठ सितम्बर को हुई संगोष्ठी में भारतेन्दु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रतिशंकर त्रिपाठी, वरिष्ठ रंगकर्मी सलीम आरिफ, उनकी अभिनेत्री पत्नी लुबना सलीम, समाजसेवी सुधीर हलवासिया ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रंगमंच अच्छे मूल्य सिखाता है। संस्था के संस्थापक तारिक खान ने कहा कि प्रयागराज के कुछ विद्यालयों में रंगमंच को शिक्षा से जोड़ा गया है। संचालन युवा रंगकर्मी शुभम तिवारी ने किया। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

सृजन की आधुनिक दृष्टि

19वीं शताब्दी में मूर्तिकला सृजन के लिए नये दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले जूलियो गोंजालेज को एक अग्रणी स्पेनिश चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने लोहे में आधुनिक मूर्तिकला विशेष रूप से वेल्डिंग के माध्यम से मूर्तिकला प्रक्रिया के साक्ष्य को दृश्यमान बनाए रखने जैसे नवाचारों के माध्यम से आधुनिक मूर्तिकला में क्रांति ला दी। वेल्डिंग का उपयोग मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक आवश्यकताओं और विनिर्माण की मांगों के कारण वेल्डिंग तकनीक का उदय हुआ। अपने पिता कॉनकॉर्डियो गोंजालेज से प्रारंभिक प्रशिक्षण लेने वाले जूलियो गोंजालेज ने एक कारखाने में काम करके धातुओं को ऊष्मा से जोड़ने के दौरान रचनात्मक तौर पर अपनी मूर्तिकला में इस तकनीक को विकसित किया और 1927 में वेल्डेड लोहे से अपनी पहली मूर्ति बनाई, जो उनके काम का विशिष्ट माध्यम रहा। पिकासो जैसे कलाकारों को यह तकनीक सिखाने वाले जूलियो का आज ही के दिन 21 सितम्बर को 1876 में बार्सिलोना में जन्म हुआ था। इस कलाकार ने आधुनिक मूर्तिकला को एक नयी दिशा दी और इन दो कलात्मक दिग्गजों ने वेल्डिंग तकनीक में मूर्तिकला की संभावनाओं को हमेशा के लिए बदल दिया।

अपने परिवार से धातु के काम का प्रशिक्षण लेने के बाद जूलियो पेरिस गए और कला में अपनी मौलिकता के साथ-साथ मूर्तिकला को नवीन वैचारिक संदर्भों के रूप में लोहे के अभिव्यंजक उपयोग को विकसित किया। 1927 में गोंजालेज ने वेल्डेड लोहे से अपनी पहली मूर्तियां बनाईं। 1937 के पेरिस विश्व मेले के लिए प्रतीकात्मक मूर्ति 'ला मोंटसेराट' का निर्माण किया, जिसे स्पेन में हुए गृह युद्ध के दौरान बनाया गया था। बार्सिलोना में स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने वाले इस कलाकार ने पेरिस जाकर कला के आधुनिक परिदृश्य में ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग का उपयोग करके मूर्तिकला के लिए एक नई दृश्य भाषा बनाने की नई तकनीक विकसित की। पारंपरिक मूर्तिकला से आगे बढ़कर आधुनिक मूर्तिकला के माध्यम के रूप में लोहे के अग्रणी उपयोग के लिए प्रसिद्ध हुए इस कलाकार ने पेंटिंग, रेखाचित्र, धातु के मुखौटे और मूर्तियां को ठोस आयतन की बजाय रैखिक रूपों में गढ़ा। गोंजालेज ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने आधुनिक लौह मूर्तिकला को विस्तृत आकार देकर औद्योगिक वेल्डिंग को ललित कला से जोड़ा। तकनीकी कौशल और रचनात्मक क्षमताओं का विकास करती वेल्डिंग कला मूर्तिकला औद्योगिक तकनीक और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक आदर्श मिश्रण है। गोंजालेज को कॉन्स्टेंटिन ब्रांकुसी, पाब्लो पिकासो और अल्बर्टो जियाकोमेटी के साथ आधुनिक मूर्तिकला के अग्रणी अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने क्यूबिस्ट सिद्धांतों को त्रि-आयामी वेल्डेड रूपों में पेश किया, जिसने समकालीन कला में क्रांति ला दी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अतिरिक्त सैन्य उपकरणों ने वेल्डिंग उपकरणों को कलाकारों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध कराया था जिसके बाद अमेरिका और यूरोप भर के कला विद्यालयों ने धातुकर्म को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया। अमूर्त अभिव्यक्तिवादी आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए वेल्डिंग के सहज, हाव-भाव गुणों को अपनाया। डेविड स्मिथ और रिचर्ड सेरा जैसे कलाकारों ने पैमाने और भौतिक संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहे डिजिटल युग में भी समकालीन आधुनिक वेल्डिंग मूर्तिकला उन्नत तकनीक और टिकाऊ प्रथाओं से लाभान्वित हुई है। प्रसिद्ध वेल्डिंग मूर्तियों में पिकासो की 'शिकागो पिकासो', अनीश कपूर की 'क्लाउड गेट' (द बीन) और एडुआर्डो कैटलानो की 'फ्लोरालिस जेनेरिका' शामिल हैं। वेल्डेड कृतियों में ईला हिल्टुनेनद्वारा जीन सिबेलियस स्मारक तथा अलेक्जेंडर काल्डर और जूलियो गोंजालेज जैसे मूर्तिकारों द्वारा गढ़ी अमूर्त कृतियां भी हैं। इस तकनीक में आधुनिक मूर्तिकला को आगे बढ़ाते हुए गोंजालेज जैसे कलाकारों ने बड़े पैमाने पर कलाकृतियों का निर्माण किया। आधुनिक मूर्तिकला के माध्यम के रूप में लोहे के अभिव्यंजक उपयोग को विकसित करने वाले इस स्पेनिश मूर्तिकार और चित्रकार का 27 मार्च, 1942 को फ्रांस में निधन हो गया। ■

https://t.me/AllNewsPaperPaid1